LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 7, 2023 / Agrahayana 16, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 7, 2023 / Agrahayana 16, 1945 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

RESIGNATION BY MEMBERS	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **(S.Q. NO. 61 & 70, 62 – 65)**	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **(S.Q. NO. 66 – 80)**	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **(U.S.Q. NO. 691 – 828, 830 – 855, 857 – 908, 910 – 920)**	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 7, 2023 / Agrahayana 16, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 7, 2023 / Agrahayana 16, 1945 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 87**
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	**288**
Statements	
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS	**288**
249th and 250th Reports	
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**289 - 322**
MATTERS UNDER RULE 377 -- LAID	**323 - 29**
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	**323**
Shri Janardan Singh Sigriwal	**324**
Shri Sushil Kumar Singh	**324**
Shri Khagen Murmu	**325**
Shri Satyadev Pachauri	**325**
Shrimati Geeta Kora	**325**
Dr. DNV Senthilkumar S.	**326**
Shri Raghu Rama Krishna Raju	**327**
Shri Rahul Ramesh Shewale	**328**
Shri Dinesh Chandra Yadav	**328**
Shrimati Sangeeta Azad	**329**
Shri Thomas Chazhikadan	**329**

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL (Contd. - Concluded)	**330 - 413**
Shri Rajiv Pratap Rudy	330 - 32
Shri Kodikunnil Suresh	333 - 35
Shri Rahul Ramesh Shewale	336
Shri Hasnain Masoodi	337 - 38
Shri Syed Imtiaz Jaleel	339 - 40
Shri Tapir Gao	341 - 42
Prof. Sougata Ray	343 - 45
Dr. M. P. Abdussamad Samadani	346 - 47
Shri Jamyang Tsering Namgyal	348 - 50
Dr. S.T. Hasan	351 - 52
Dr. Satya Pal Singh	353 - 55
Adv. Dean Kuriakose	356 - 57
Shri Kaushlendra Kumar	358
Shri Arvind Sawant	359 - 61
@ Dr. Pon Gautham Sigamani	362
Dr. Sanjeev Kumar Singari	363 - 65
Shri Girish Chandra	366 - 67
Dr. Mohammad Jawed	368 - 69
Shri Gajendra Umrao Singh Patel	370 - 71
Shri Ramshiromani Verma	372

@For English Translation of the speech made by the Hon. Member Dr. Pon Gautham Sigamani in Tamil, please see the Supplement (PP 362A – 362B)

Shri Raju Bista	**373 - 74**
Shri N.K. Premachandran	**375 - 78**
Shri Raghu Rama Krishna Raju	**379**
Dr. Nishikant Dubey	**380 - 82**
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	**383 - 86**
Shri Ve. Vaithilingam	**387**
Shri Jagdambika Pal	**388 - 90**
Adv. A. M. Ariff	**391**
Shri Ritesh Pandey	**392 - 93**
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	**394 - 97**
Shri Dharmendra Pradhan	**398 - 409**
Motion for Consideration – Adopted	**410**
Consideration of Clauses	**410 - 13**
Motion to Pass	**413**

xxx

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 7, 2023 / Agrahayana 16, 1945 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL 362A – 362B

xxx xxx xxx xxx

Dr. Pon Gautham Sigamani 362A – 362B

xxx xxx xxx xxx

(1100/KN/SM)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि इस सभा के निम्नलिखित निर्वाचित माननीय सदस्यों ने लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है–

1. राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर जी,
2. राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री दिया कुमारी जी,
3. मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमान नरेन्द्र सिंह तोमर जी,
4. मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी,
5. मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री राकेश सिंह जी,
6. मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीया श्रीमती रीती पाठक जी;
7. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी;
8. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीया श्रीमती गोमती साय जी; और
9. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री अरूण साव जी।

मैंने इन सदस्यों के त्याग-पत्र को दिनांक 6 दिसंबर, 2023 से स्वीकार कर लिया है।

(प्रश्न 61 और 70)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 61 – श्रीमती संगीता आजाद।

माननीय मंत्री जी, क्या प्रश्न-70 क्लब कर दें, क्योंकि यह भी किराये से संबंधित है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : जी हाँ।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष जी, धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपना सवाल पूछें और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि वे संक्षिप्त में जवाब दें। मैं हर बार कहता हूं और बार-बार आग्रह करता हूं। मुझे लगता है कि इस बार मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश को सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराये पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार समाज के निचले पायेदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये में सब्सिडी देने के लिए कोई योजना बना रही है, जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अध्यक्ष जी, नागर विमानन क्षेत्र वर्ष 1993 से समस्त रूप से एक डिरेगुलेटेड सेक्टर है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्या को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऑर्ग्युमेंट्स हैं, उसके आधार पर नागर विमानन क्षेत्र में वर्ष 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में यह संख्या बढ़कर साढ़े 14 करोड़ यात्री संभव हो पाए हैं।

(1105/PC/RP)

इसका एक मुख्य भाग 'उड़े देश का आम नागरिक' की योजना ही है, जहां वाइबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि 'उड़ान' उन क्षेत्रों में प्रचलित हो, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटा दिया गया था। ऐसे कई शहर हैं, जहां प्रधान मंत्री जी ने स्वत: अपने आप रुचि लेकर यह संभव करके दिखाया है।

ओडिशा में झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रुपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट इसके उदाहरण हैं। ऐसे कई एयरपोर्टर्स हैं, कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं, जिनका क्रियान्वयन 'उड़ान' योजना में संभव हो पाया है। इसी के साथ हमारे देश के 1,30,00,000 ऐसे यात्री हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्लेन में बैठकर सफर नहीं किया। वे प्लेन को केवल ऊपर उड़ता देखते थे। 'उड़ान योजना' के तहत उनका आज प्लेन में सफर करना संभव हो पाया है। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का यह सपना साकार हुआ है। ... (व्यवधान)

यदि हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, तो पिछली बार मैंने सदन में यह भी सूचित किया था कि विश्व भर में seasonality के आधार पर एयर फेयर्स चलते हैं। जब लो सीज़न होता है, जो वर्षाकाल होता है, वह जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है। दशहरे के बाद जनवरी तक हाई सीज़न

शुरू होता है और फिर उसके बाद दोबारा लो सीज़न शुरू होता है। आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं, वे फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पीटेटिव हैं। इसी के साथ-साथ हमारा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक, जो आज हमारे साढ़े चौदह करोड़ यात्री हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। तीन गुना ज्यादा यह क्षेत्र बढ़ेगा।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार अपनी स्वयं की पूर्ण रूप से नियंत्रित सरकारी एयरलाइंस का संचालन करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

अभी माननीय मंत्री जी ने 'उड़ान योजना' की बात कही है। अभी आजमगढ़ के बगल के आपने अयोध्या का इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाकर उसका संचालन करा दिया, गोरखपुर का एयरपोर्ट बन गया, लेकिन आजमगढ़ का एयरपोर्ट, जो पिछले दो वर्षों से बनकर तैयार है, सरकार उस एयरपोर्ट का संचालन कब करेगी? माननीय मंत्री जी इसका भी जवाब दें।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश अभी किया है और आप चमत्कार देखिए कि केवल एक नेतृत्व है, जिसकी यह संकल्पता थी कि भारत को एक नए नागर विमानन क्षेत्र में हमें प्रवेश करवाना होगा। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के आधार पर एयर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि जिस क्षेत्र में वर्ष 2014 में केवल 400 प्लेन्स थे, वहीं एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कंपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर, 470 प्लेन्स का ऑर्डर 250 बोइंग के साथ और 220 एयर बसेस के साथ विश्व में डाला है। … (व्यवधान) इस क्षेत्र में यह परिवर्तन आया है। माननीय सांसद महोदया ने आजमगढ़ के बारे में अपनी चिंता जताई है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ सिर्फ आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता के साथ-साथ वह हमारी चिंता भी है। आजमगढ़, श्रावस्ती और आसपास के एयरपोर्ट्स की वर्तमान में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप बिलकुल चिंता न करें, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 'उड़ान योजना' के आधार पर हमने आजमगढ़ से लखनऊ के लिए एक रूट भी दे दिया है। आने वाले वर्ष में लाइसेंसिंग प्रकिया समाप्त होने के बाद उसकी शुरूआत भी की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों को साढ़े चार साल हो गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें एक मूल प्रश्न पूछा जाता है और एक सप्लिमेंट्री पूछी जाती है। हम सबने उसकी पालना की है। आप सब पुराने सदस्य हो गए हैं, इसलिए इसकी पालना करें।

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी – अब आप बोलिए।

… (व्यवधान)

(1110/NKL/CS)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, with regard to the exorbitant ticket fares in flights, the hon. Minister, in his reply, has stated what best he can do in this regard. The Ministry had consultation with the airlines, and the representatives were advised to self-regulate and keep passengers' interests in mind while fixing ticket rates. Through you, I would like to ask the hon. Minister, what kind of self-regulation they are doing except in squeezing kind of exploitation of the passengers. That is what they are doing. You may give many advices. But how are they responding?

Sir, you have to realise one thing. To spend vacation, holidays or even for having treatment, people are coming by road. They are being exploited like anything. There is no control. The Government is washing its hands. The Government says, they have nothing to do. Before this rule came into force, there was another provision. During that time, the Government could interfere in price rise situation.

Now, Sir, what is happening is this. I wish to bring one thing to the notice of the hon. Minister. Please take note of it. The Report of the Parliamentary Standing Committee on Tourism states:

> "The Committee notes that affordable air transport is a must for the growth of tourism in India, which is presently reviving. The Committee recommends that the Ministry may devise suitable monitoring mechanism to keep a check on the sudden surge in prices during the festive season, holidays, natural calamities and things like that."

Sir, I would like to ask the Government whether the Government can say that they cannot interfere like that. Are you doing this to the mercy of private companies? That is not fair. The Government is responsible towards the tax payers.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I am coming to the point. As per the present Act, there is a provision that they can make a reasonable profit. That is not defined. What is the reasonable profit you are talking about? What is the definition of that? This is nothing but a vague statement. Kindly come forward to have a solution to this burning problem in the country.

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्रीगण से आग्रह करता हूँ कि जब मैंने आपका नाम पुकार दिया है तो फिर आप उनको समय क्यों दे रहे हो? यह व्यवस्था तो मुझे करनी है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, माननीय सदस्य हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

माननीय अध्यक्ष : वह बात ठीक है, लेकिन इतना लंबा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, हमारे बड़े सीनियर मैंबर हैं, मैंने सोचा कि मैं उन्हें बीच में नहीं टोकता हूँ। Shri E.T. Mohammed Basheer is a very senior Member and someone who I have known for the last 20 years. I can very well understand his emotions. But I would like to state on the Floor of this House that we must understand the situation in the Civil Aviation space.

The first point I would like to make is this. महोदय, मुझे आपका थोड़ा संरक्षण मिले और मुझे थोड़ा समय मिले। Civil Aviation is a seasonal sector. You have high season and you have low season. From October till mid-Jan is the high season, after that comes a very low season until April-May when holidays start, and then, again you have a high season till mid-June. This is not limited to India alone. This is a global phenomenon. Having said that, from our side, we have monitored fares and a tariff monitoring unit that looks at 60 routes randomly. If you buy a ticket in advance, this tariff monitoring unit looks at Day 30 fares, Day 15 fares, Day 7 fares, and likewise, it goes up to 3, 2 and 1. There are two ways. If you do a booking in advance, there will be no high fares. But if you do a booking on the last day, then according to the Reservation Booking Designators, which is the RBD system, fares do rise as far as airlines are concerned. Having said that, I would like to place on record two facts. Number one, in the last three years, if we take all airlines together, they have made losses of close to between Rs. 55,000 crore and Rs. 1,32,000 crore on an annual basis. The

COVID-19 pandemic has completely destroyed the financial viability of airlines. Even in that environment, our airlines have operated on a very sustainable basis.

The second point I would like to make as far as Basheer ji's statement is concerned is this. He has talked about high fares. If you look at the data, I am willing to share the data with him. In Calendar Year January 2022 till October 2022 and Calendar Year January 2023 till October 2023, apart from the month of January, across every month, there has been a decline in fares across most of the routes.

(1115/MMN/IND)

This is keeping seasonality in mind. When there is seasonality, then the fares do go up. Basheer Saheb, I would like to explain this to you also. At the end of the day, the aviation turbine fuel is close to 40 per cent of the operating cost of an airline and the ATF prices have gone up from Rs.55,000 a kilolitre to Rs.1,50,000 a kilolitre. Though they have gone up 3X, the airfares have gone up no way in rational to that. Today, the ATF price is down to Rs.1,08,000 a kilolitre which is still close to about two-and-a-half times from where it was. So, the airlines are operating under very exogenous circumstances and still providing relief and travel to a majority of our population at a reasonable cost.

माननीय अध्यक्ष : श्री जुएल ओराम। आप भी शार्ट में बोलें और मंत्री जी भी शार्ट में जवाब दें।

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): महोदय, उड़ान योजना के अंतर्गत 100 एयरपोर्ट्स सिलेक्ट हुए थे। उसमें राउरकेला एयरपोर्ट पांचवें स्थान पर था। राउरकेला स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। उत्तर काशी में हरक्यूलस प्लेन द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के पाइप को एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया गया। राउरकेला स्टील प्लांट से कोरोना के समय ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट हुई थी। माननीय मंत्री जी राउरकेला स्टील प्लांट के मंत्री हैं, जमीन उनकी है और सिविल एविएशन के भी वे मंत्री हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतना स्ट्रेटेजिक और बढ़िया एयरपोर्ट होते हुए भी राउरकेला एयरपोर्ट का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, माननीय सदस्य की बात इस प्रश्न के साथ ताल्लुकात नहीं रखती क्योंकि टिकट प्राइसिंग से संबंधित प्रश्न है लेकिन राउरकेला के लिए

हमने प्राथमिकता दी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे मुझसे आकर जरूर मिलें और हमारी जो विकास और प्रगति की नीति है, उस पर हम जरूर विश्लेषण करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the answer of the hon. Minister would go to show that as per Sub-Rule (1) of Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937, every Air Transport Undertaking engaged in scheduled air service is required to establish tariff having regard to all relevant factors, including cost of operation, characteristic of services and generally prevailing tariff.

This is my simple question to the hon. Minister. Who is the authority to monitor the tariff making system? We are having the electricity regulatory mechanism and there is a regulatory mechanism in the petroleum sector. In almost all the sectors, there is a regulatory mechanism to determine the tariff. What is the reason? Even in the case of motor transport also, the State Governments are determining the bus fares and all that. Why is such a special treatment or privilege being provided to the airline sector alone? There is no monitoring mechanism. There is nothing. Today, the airfare in the Thiruvananthapuram-Delhi sector is more than Rs.30,000 in the domestic air services.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, I would like to respond to Premachandran ji by saying that I have said repeatedly on the floor of this House that the civil aviation sector is a deregulated sector. It was deregulated in the year 1993. We do have a Tariff Monitoring Unit which does monitor 60 routes on a random basis. Wherever we find that there is excessive pricing, that has been conveyed to the airlines. Last time when the prices had gone up, there was a double effect. We had a high season in April and May. Unfortunately, one of our airlines in our country, Go First, had shut down. So, there was a double effect. I myself had taken a meeting of the airlines for specific sectors like Leh, Mumbai, Ahmedabad and Srinagar where the fares had gone excessive and we had told the airlines that they must self-regulate.

Also, out of the 315 routes that were applied by Go First, in those areas we gave 68 more routes and within a period of 10-15 days, the prices came down to close to 60-70 per cent from the highs that they had gone to.

(1120/VR/RV)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, pravasis of Kerala are facing extreme difficulties especially during the holiday seasons of Christmas, New Year, Onam, Bakra Eid and school vacations. Majority of Gulf passengers travel in these seasons. They all belong to working class, and their salaries are very meagre. This is a long pending demand from the Gulf passengers. The air fare during the peak season triples, and not only triples but it rises to almost 10 times.

I would like to request the hon. Minister to kindly consider this demand from pravasi Malayalees seriously.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, we have four airports in Kerala. I would like to report to this Houe that all four airports have international connectivity at this point of time. Calicut has close to about 416 international flights connected to multiple cities. So is Kochi with 21 airlines. It has close to about 564 international flights per week connected to 16 cities. Kannur also has close to 98 international flights connected to almost six or seven cities in the Middle East, and Thiruvananthapuram also has close to 254 flights connected to about 16 or 18 cities across the world. So, there is already a tremendous amount of connectivity in Kerala on an international perspective. We have very clearly requested Indian airline companies to increase their flights from cities in South India to the Middle East based on what Suresh ji has said.

Now, we are hoping that airlines will increase the capacity as they increase their fleet. Today we have close to about 635 planes in India in our fleet. As that fleet is increasing with this big order, I am very confident that in the times to come Indian airlines will fly much more to the Middle East. (ends)

(प्रश्न 62)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भूमिका मत बाँधना, सीधे प्रश्न पूछना।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वेन्डर्स, पटरी तथा फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है। इससे कारोबार करने वाले लोगों का भविष्य सुधरेगा। इस योजना को लागू किए हुए तीन साल हो गए और अब तक देश में कुल 56 लाख लोग इस योजना का लाभ लेने की स्थिति में हैं।

महोदय, बिहार देश की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 14 करोड़ है, लेकिन वहां पर मात्र 56,000 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलना है जबकि वहां के लाखों लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है। हमारा क्षेत्र काराकाट संसदीय क्षेत्र है। वहां पर 5,000 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें मात्र 2,000 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। हम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे बैंकों के चक्कर दिन-रात काट रहे हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ कब मिलेगा? जो बैंक इस काम को दिलचस्पी से नहीं कर रहे हैं, क्या सरकार का उन बैंकों पर कोई ठोस कार्रवाई करने का विचार है?

(1125/GG/SAN)

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पर काम हो रहा था, उस समय कुछ रिसर्च की गई थी और हमें लगा कि हमारी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 45 करोड़ है और इसमें से स्ट्रीट वेंडर्स या रेहड़ी-पटरी पर जो अपना काम करते हैं, उनके क्या नंबर्स होंगे? हमने यह अंदाज़ा लगाया था कि 2 या 2.5 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जो कि करीब 90 लाख का फिगर होता है। महोदय, यह एक ऐसी विशेष केंद्रीय योजना है और प्रधान मंत्री जी ने जो निर्णय महामारी के दौरान लिया, because this was the most vulnerable section of our society. जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, कृषि क्षेत्र में जो हमारे बहन-भाई काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे या सरकारी दफ्तरों में जो काम करते थे, उनको तो तनख्वाह मिलती रही, परंतु ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले थे, उनका पूरा काम रुक गया था। ये लोग मनी लेंडर्स से 300 प्रतिशत इंट्रेस्ट पर लोन लिया करते थे और इनकी बहुत ही गंभीर स्थिति थी। जब यह स्कीम महामारी के दौरान रोल आउट हुई, तब एक दिन में इसकी गाइडलाइंस नोटिफाई हो गईं और बहुत ही जल्दी यह स्कीम सफल हो गई। As of today, under this scheme, 56 lakh street-vendors have already availed of the first loan. If you add up the second and third loans, 73 lakh people have availed of it. बैंक्स को शुरू में प्रॉब्लम हुई, परंतु मैं समझता हूँ कि अगर बैंक्स कोऑपरेट नहीं करते तो it would not have been possible for this scheme to roll out with such efficiency. दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सैक्टर बैंक्स ने देखा कि यह जो लोन का अमाउंट है, पहला लोन 10 हज़ार रुपये का है, अगर उसको आप समय से लौटा दें, then, you get the second loan of Rs. 20,000, again all interest free. अगर उसको भी लौटा

दें तो 50,000 का लोन मिलेगा। Today, this is one of the most successful schemes. So far as Bihar is concerned, I do not know if this is a Question on Bihar or on the scheme, but I have the figures for Bihar. I will be very happy to share them with you. The first loan target for number of beneficiaries was 1,61,000 street-vendors. इसमें ऑलरेडी 59 पर्सेंट टारगेट अचीव हो चुका है और इसमें 94,519 लाभार्थी हैं। टोटल डिस्बर्स्ड लोन्स 1,16,689 रुपये है। The value of the loans disbursed is Rs. 142.61 crore, out of which women beneficiaries are 33,122, that is, 35 per cent. डिजिटली एक्टिव 46 प्रतिशत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े मेरे पास हैं और जो आंकड़े माननीय सदस्य दे रहे हैं, उनमें कुछ अंतर है, तो मैं इनके साथ बैठ कर डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास स्टेट वाइज़ स्टेटिस्ट्क्स भी हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी हैं, क्योंकि बेनिफीशरीज़ की जो पर्टिकुलर डीटेल्स हैं, I will not put them out because वह तो प्रिविसी की बात हो जाएगी।

माननीय सभापति : मंत्री जी, अभी टारगेट भी बढ़ा है, यह भी सबको बताइए।

श्री हरदीप सिंह पुरी : जी सर, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने कहा था कि हमने जो एस्टिमेशन किया था, वर्ष 2014 के एक्ट के समय, that they would be two or 2.5 per cent.

The original target, when the Cabinet approved the proposal, hon. Speaker, was Rs. 42 lakh. We have already disbursed to Rs. 53 lakhs. We are taking it up to 60-75 lakhs. So, the number of beneficiaries is increasing.

(1130/SNT/MY)

One should in the overall context understand that there are three separate issues involved here. One is the identification and respect of those who conduct their trade through street vending. The second thing is to ensure that the local authorities provide them that respect. And the third thing is to incentivise them to come and accept the loans and then to facilitate that. The fact that we have gone from a target of Rs. 42 lakh – was achieved – on to Rs. 53 lakh, now we are going up to Rs. 60-70 lakh, which means the scheme is doing well. If there are local situations in any part of the country where there may be factors which perhaps are local, we are very happy to help out. केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी यही कोशिश है कि इस योजना का लाभ हमारे मैक्सिमम उन भाई-बहन को मिले जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और इसके लाभार्थी मिले। I am personally in regular touch with Arbind Singh ji from National Association of Street Vendors of India and others. डिस्ट्रिक्टवाइज कुछ ऐसे स्टेटस हैं, जहां के स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी या ग्रिवान्स कमेटी में ज्यादा तेजी से काम नहीं हो रहा है। मैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखता है। But I would be happy to sit with the hon. Member and look at any specific issues which might be there.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि इसका आंकड़ा हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है। इसमें 56 लाख या 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शहर में रहने वाले और इस तरह के कारोबार करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ से ऊपर है। इसको बढ़ाना अनिवार्य है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय से हम यह जानना चाहते थे, यह मेरा क्वेश्चन है कि काराकाट लोक सभा क्षेत्र में पाँच हजार लोगों ने आवेदन दिया है। सासाराम जिला मेरे ही क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद जिला का तीन विधान सभा मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में आता है। वहां पाँच हजार लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें मात्र दो हजार लोगों का हुआ है और बाकी लोगों का नहीं हुआ है। उनका आवेदन दो साल पहले से पड़े हुए हैं। उनका काम बैंकों की लापरवाही के चलते नहीं हो रहा है। हमने कहा कि देश के अंदर जो बैंक इस योजना को लागू करने में लापरवाही कर रहे हैं, क्या उन बैंकों पर सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है? यह मेरा प्रश्न है।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I want to tell the hon. Member that any claim that there are ten crore…. … (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप हिन्दी में बोलिए। … (व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं हिन्दी में बोलता हूं। मैं पंजाबी और बांग्ला में भी बोल सकता हूं, परंतु आपको पसंद नहीं आएगी, जो मैं बोलूंगा।

देखिए, आपका कहना सही है कि देश की जो टोटल जनसंख्या है, वह 140 करोड़ है। उसमें यह कहना कि हमारे रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वालों की संख्या 10 करोड़ है। मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि यह आंकड़ा ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि वर्ष 2014 के एक्ट में जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय भी हमने कहा था कि दो प्रतिशत हो सकती है। अगर हमारी शहरी जनसंख्या अभी 45 करोड़ है, उसका भी सेन्सस में पता लगेगा, तो यह 90 लाख हो सकती है। हम इन 90 लाख की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं।

दूसरी बात, आपने काराकाट क्षेत्र की बात की। मेरे पास जो आंकड़े हैं- Number of males is 2,219; number of females is 5,214; loans distributed are worth Rs. 2,743 crore; number of beneficiaries is 2,192; and total amount disbursed is Rs. 3.47 crore The total number of beneficiaries is 2,192. The total amount disbursed is Rs. 3.47 crore. मैं आपको हरेक डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स दे सकता हूं। इसका डिटेल्स मेरे पास है। हमारा जो बॉडी ऑफ दी ऑन्सर है, उसमें भी हरेक स्टेट के डिटेल्ड आँकड़े दिए हुए हैं।

आप यह देखिए कि जैसे ही इस योजना का निर्णय लिया गया, बहुत ही जल्द यह सफल हो गई है। अभी भी जैसा मैंने बताया कि जो ओरिजिनल टारगेट था, वह 42-43 लाख लोन्स का था। वह उस समय टारगेट था। अभी ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लोन 56 लाख तक पहुंच गए हैं। यह हम सेकेंड और थर्ड बताएं तो 74 लाख पर पहुंच गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बैंक्स के साथ बात करके, जो एनबीएफसीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ऑर्गनाइजेशंस हैं, उनसे बात

करके हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे सभी स्ट्रीट वेंडर्स इसका फायदा लें। परंतु, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी मिसअण्डरस्टैंडिंग है।

(1135/CP/AK)

हर एक स्ट्रीट वेंडर को शायद अप्लाई करने की जरूरत न पड़ती हो। महामारी के दौरान उनका कारोबार पूरा बंद हो गया था। उस समय जो पहला लोन 10 हजार रुपये का लिया, उस समय उन्होंने उससे अपने बाकी लोन्स लौटाने की कोशिश की। अभी जो दो स्टडीज़ आई हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की है, उनके अनुसार यह बहुत सफल स्कीम है। इसमें 43 पर्सेंट ऑफ दी बेनिफिशियरीज़ ओबीसीज़ हैं, महिलायें 44 पर्सेंट बेनिफिशियरीज़ हैं। अगर आप एससी, एसटी को भी मिला दें तो 60-70 पर्सेंट इसके जो लाभार्थी हैं, वे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हो जाते हैं।

दूसरी बात, जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया है, their credit spending is also … (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): क्या माइनोरिटीज़ का कोई आंकड़ा है? … (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: When we go by these figures, we do not … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आगे बढ़ते हैं।

श्रीमती गीता कोडा।

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, लगता है बड़ी कंजूसी से दिया है। हमने पिछले तीन वर्षों के बारे में पूछा है और उस हिसाब से अगर झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में बहुत कम वेंडर्स ने यह लोन लिया है। इसके क्या कारण हैं?

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगी। वर्ष 2020 में यह योजना शुरू हुई। उस वक्त कोरोना काल था। ऐसे में कई वेंडर्स, जिन्होंने लोन लिए, उनका काम बंद हो गया या अतिक्रमण के नाम पर उन वेंडर्स को हटा दिया गया तो वे लोग अपना ऋण चुका नहीं पाये, जिसकी वजह से उनका सिविल खराब हो गया। क्या सरकार के ऐसे वेंडर्स की कोई सूची है? अगर है, तो उन वेंडर्स के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, ताकि वे पुन: लोन ले सकें और अपना व्यापार पुन: शुरू कर सकें?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker Sir, I would like to inform the hon. Members about the figures for Jharkhand's Singhbhum. There are 1,270 males and 514 females. The total number of loans disbursed is 1,784. The number of beneficiaries, the figures for total number of loans disbursed

and all these figures I am very happy to share with her. I think that there is a misunderstanding. जो इस योजना में एनपीएज़ बनते हैं, एनपीएज़ क्या हैं कि आप पहला लोन 10 हजार रुपये का लेते हें और मान लीजिए 1 साल में उसको लौटाना है तो यह कोलैटरल फ्री है। आप एक साल में उसे लौटा देते हैं तो आपको इंट्रेस्ट भी नहीं लगता। आप फिर दूसरा लोन 20 हजार रुपये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से 10 हजार, प्लस 20 हजार, प्लस 50 हजार का तीसरा लोन, टोटल 80 हजार रुपये लोन ले सकते हैं। महामारी के दौरान जो हमारी सोसाइटी में सबसे वलनरेबल सैक्शन था, यह माइक्रो एंटरप्रिन्योर बन गया। मैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्टडीज़ की बात कर रहा था, उनकी जो क्रेडिट स्पेंडिंग, ईटीसी है, उसको अगर आप देखें तो it is a highly successful scheme.

दूसरा, इसीलिए सिबिल स्कोर इसमें नहीं हैं, कोई एनपीएज़ इसमें नहीं बने हैं और इसको लोन में कंसीडर ही नहीं करते हैं। ये कोलैटरल फ्री लोन्स हैं। मैं समझता हूं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई लोन देने वाले बैंक की इंडीविजुअल हैजिटेशन हो सकती है, लेकिन जब भी हुआ, तब हमें वित्त मंत्रालय से बहुत अच्छा कोआपरेशन मिला। ये लोन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई हैजिटेशन is more at an individual level, then it would have reflected in the overall performance of the scheme. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आप सभी माननीय सांसदों से आग्रह करें, एक परिपत्र दोबारा जारी करें। यह स्कीम बहुत अच्छी है, इससे गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी माननीय सांसद इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और उसकी पूरी योजना की जब आप जानकारी लेंगे तो उसे परिपत्र में दें। वहां की नगर-निगम, कोरपोरेशन, उसमें उसे अप्लाई करना पड़ता है, फिर पूरा प्रोसीजर होता है, हमनें भी किया है, सभी एमपीज़ ने किया है। परिपत्र जारी करके सभी माननीय सांसदों से आप आग्रह करें, ताकि हम गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकें।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker Sir, thank you. I will implement it from my end as has been suggested by you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 63.

श्रीमती हेमामालिनी।

(1140/NK/UB)

(प्रश्न 63)

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ कर ड्राउट और एरिगेशन की समस्या से निजात दिलाया जाए। वर्ष 2002 में योजना बनायी और वर्किंग ग्रुप कन्सटीट्यूट भी किया गया। फर्स्ट फेज में सदर्न रीजन की नदियों को जोड़ना था, सेंकड फेज में नार्थ की नदियों को जोड़ने की बात हुई, लेकिन अटल जी की सरकार जाते ही ये सारा काम बंद हो गया। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी के समय के जितने भी इनकम्पलीट काम थे, उन कामों को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। सितम्बर, 2014 में देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी कन्सटीट्यूट की गई और अप्रैल, 2015 एक इंडिपेन्डेंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया।

मेरा सवाल है कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है और प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड पूरा करने के लिए क्या कुछ तय किया गया है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न बांधों में पानी के स्तर को लेकर था। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है वह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर कर देश के सामने जो वार्षिक समस्या और चुनौती है, देश के 16-17 प्रतिशत हिस्से में अकाल पड़ता है और लगभग इतने ही हिस्से में बाढ़ की स्थिति होती है, एक संतुलन और सम्यक देश में लाया जा सकता है। जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद दस साल तक उसे रोक दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुन: इसे प्रारंभ किया है। देश भर में 31 लिंक्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन सबकी पीएफआर बनी, उनमें से 15 से ज्यादा लिंक्स के लिए डीपीआर बनायी गई। डीपीआर बनने के बाद हमने राज्यों के साथ इसे शेयर किया। हम सभी जानते हैं कि भारत में संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है। इसमें राज्यों की सहमति बनाने के बाद ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। पांच ऐसे प्रॉयरिटी लिंक्स डिसाइड किए गए, उन पांच प्रॉयरिटी लिंक्स के बारे में मैं सदन को प्रसन्नता के साथ अगवत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, दोनों राज्यों के बीच एक ऐसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक कमी रहती है, ऐसा देश में माना जाता था, बुंदेलखंड के 60 लाख लोगों के लिए पेयजल और 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित हो सके। इस दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया और 45 हजार करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए, उसके लिए 90 परसेंट ग्रांट भारत सरकार की तरफ से मिले, इसे भी सुनिश्चित किया। इस दिशा में स्टेज-1 और स्टेज-2 की क्लेयरेंस मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रियाधीन है और निश्चित ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे।

इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रॉयरिटी लिंक की डीपीआर बनाने के लिए मैंने राज्यों से समझौता करने के लिए आग्रह किया है। राज्यों के द्वारा आपस में एमओयू हो जाने के बाद निश्चित ही अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में काम करेंगे।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि वर्ष 2030 तक भारत में वाटर की डिमांड सप्लाई से दोगुना अधिक हो जाएगी। रेन वॉटर कन्जर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कई स्कीम्स चलाई गई हैं। वॉटर स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट और लोकल लेवल पर प्रॉपर कोआर्डिनेशन न होने के कारण स्कीम का प्रॉपर इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि प्रॉपर इम्पलीमेन्टेशन और कोऑर्डिनेशन को एन्श्योर करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इम्पलीमेंट करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है?

(1145/SK/SRG)

देश में वाटर डिमांड और सप्लाई के अलार्मिंग गैप को लेकर रेन वाटर कन्जर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए फोकस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशन्स की आवश्यकता है। सरकार द्वारा लोगों को एजुकेट करने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए क्या स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्या की चिंता देश में बढ़ती हुई पानी की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए है। इस कठिन दौर में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, ऐसे में हमारी चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। चुनौतियों के बढ़ने के अनेक कारणों में बढ़ती आबादी, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ता औद्योगीकरण है। इसके साथ अगर पूरी दुनिया का मानचित्र आर्थिक प्रगति की दृष्टि से देखा जाए तो जिन देशों ने प्रगति की है, उनकी बढ़ती इकोनॉमी, बिजली की आवश्यकता और पानी का ग्राफ लगभग आइडेंटिकल होता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम तीन से पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से हमारी पानी की मांग और बढ़ने वाली है।

महोदय, एक तरफ जहां भूगर्भ के जल पर हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता है, इसके अत्यधिक दोहन के कारण निरंतर भूगर्भ का जल दबाव में था क्योंकि भूगर्भ के जल स्रोत सूखते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पिछले दस सालों में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आगे बढ़कर लीड किया है, इसके चलते विभिन्न योजनाएं ली गई हैं और राज्य सरकारों में चेतना व्याप्त हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पंचायतों के स्तर पर चुने हुए जन प्रतिनिधियों को पत्र लिखा और विभिन्न इंटरवेंशन्स लिए गए। अटल भूजल योजना के माध्यम से पहली बार देश में डिमांड को एड्रेस करने पर काम हुआ। 'अमृत सरोवर' के माध्यम से देश में ऐसे तालाबों को बनाने की योजना पर काम किया गया। इन सबके चलते जल चेतना देश में व्याप्त हुई और देश में जल संरक्षण को लेकर, वर्षा के जल से भूगर्भ में पुनर्जल भरण को लेकर गतिविधियां हुईं।

मैं आज सदन को प्रसन्नता से सूचित करना चाहता हूं कि देश में भूगर्भ जल का गिरता हुआ ट्रैंड, न केवल पिछले चार वर्षों से ठहरा है, अपितु वापस रिचार्ज होने की दिशा में बढ़ा है। ओवर एक्सप्लॉइटेड

ब्लॉक्स और क्रिटिकल एक्सप्लाइटेड ब्लॉक्स में पोजीटिव ग्रोथ हुई है और गिरने वाले ब्लॉक्स की संख्या की तुलना में सुधरने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है। हम विभिन्न इंटरवेंशन्स के माध्यम से संचित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और एक-एक बूंद पानी से अधिकतम लाभ ले सकें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत योजनाएं बनाई गई हैं। हमने माइक्रो इरीगेशन को एक्सपैंड करने पर काम किया है ताकि जो उपलब्ध पानी है, उसका अधिकतम उपयोग कर सकें। पानी एक सीमित संसाधन है और इस सीमित संसाधन की सीमितता को देखते हुए उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग करके किस तरह से अपने देश में पानी की निर्बाद्ध आपूर्ति कर सकें, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार सतत चिंतन-मनन करते हुए काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष: मेरा भी मानना है कि इस गंभीर चिंता पर सभी माननीय सदस्यों को एक गंभीर प्रयास अपने संसदीय क्षेत्र में करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके सरफेस वाटर को रोककर तालाब बना सकें और तालाबों को गहरा कर सकें। इसमें सांसद कोष निधि का भी उपयोग होना चाहिए और जन सहयोग का भी उपयोग होना चाहिए।

… (व्यवधान)

(1150/KDS/RCP)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, the main context of the question asked by Hemamalini ji was interlinking of the rivers throughout the nation which was once proposed by Atal Bihari Vajpayee ji. It was followed up by the next Government also. But I would like to know whether this proposal is at all viable. It is at all possible and can it be implemented in the country? If so, how far you have taken a lead or progress in this proposal?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और हम दोहन कर सकें, इस हेतु मैंने पूरे विस्तार से निवेदन किया था कि देश में लगभग 16-17 प्रतिशत हिस्सा ऐसा होता है, जहां हर साल बाढ़ आती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वैसा देश भर में लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है, जहां हर साल सूखे की चपेट होती है। हम इस तरह से वाटर ग्रिड बनाकर एक साम्य उपस्थित कर सकें, इसके ऊपर बहुत लंबे डेलिबरेशन्स और विचार करके इस तरह का निर्णय हुआ है। मैं यह मानता हूं कि यदि सभी राज्य सहमत हो जाएं और ये सारे लिंक्स बना दिए जाएं, तो देश के जल संसाधनों की उपलब्धता की चुनौती को हम सदियों तक के लिए एड्रेस कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : डॉक्टर एम.के. विष्णु प्रसाद -- उपस्थित नहीं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत लम्बी चर्चा होगी, क्योंकि अगर इस तरह से चर्चा चलेगी, तो कुल 20 प्रश्न हैं और प्रश्न केवल 3 लग रहे हैं। अत: मानननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यों से आग्रह है कि संक्षेप में प्रश्न पूछें और उनके उत्तर दें।

(प्रश्न 64)

माननीय अध्यक्ष : श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी -- उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोमती वेंकट रेड्डी -- उपस्थित नहीं।

श्री बिद्युत बरन महतो।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुराकाटी शाखा नहर से जादुगोड़ा, मुसाबनी एवं डुमरिया प्रखंड की करीब 12 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो मुख्यत: आदिवासी किसानों का है। गाजिया स्थित खरकई नदी पर वर्ष 2019-20 को 500 करोड़ रुपये की लागत से बैराज बनकर तैयार है। पिछले 3 वर्षों से मुराकाटी शाखा नहर न बनने के कारण सारे किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। विगत 4 वर्षों से…

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : जी महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उक्त योजना हेतु क्या जल्द से जल्द नहर निर्माण करने का काम करेंगे, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल सके?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जल क्योंकि राज्य का विषय है, अत: इस तरह की योजना का निर्माण करना, डीपीआर बनाना, योजना को लागू करना, नहरों का जाल खड़ा करना और सिंचाई की सुविधा बढ़ाना, ये सभी राज्य सरकारों के विशेषाधिकार में आते हैं। इस तरह का कोई भी प्रपोजल अभी भारत सरकार में लंबित नहीं है। माननीय सदस्य यदि पत्र लिखेंगे तो मैं उनके बिहाफ पर राज्य सरकार को पत्र लिखकर इनकी चिंता को संसूचित करूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): धन्यवाद अध्यक्ष जी। बिहार में गंडक कैनाल है, जहां वाल्मीकि नगर, नेपाल की तरफ से 15 हजार क्यूसेक पानी आता है। उसके लिए 8 हजार क्यूसेक पानी बिहार का है, लेकिन पानी बिहार तक नहीं पहुंचता है, पानी चोरी हो जाता है। मैं बार-बार यह विषय उठाता हूं। उसके लिए एक बड़ा प्रस्ताव सेंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल से भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस पर समय-समय पर माननीय मंत्री जी से विचार-विमर्श होता रहा है। मेरा जिला सबसे अंतिम है और सबसे कम सिंचाई की व्यवस्था है। मंत्री जी की संवेदना और प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या भारत सरकार इन दो बड़ी परियोजनाओं, जो गंडक कैनाल के पानी को सारण जिले तक पहुंचाने हेतु प्रस्तावित हैं व जिनका एक प्रस्ताव इरीगेशन व दूसरा बाढ़ नियंत्रण का भी है। डीपीआर बनने के बाद ये दोनों प्रस्ताव भारत सरकार के इन विभागों में प्रस्तावित हैं। क्या इन प्रस्तावों पर सरकार कोई निर्णय

लेना चाहेगी? इस विषय के बारे में आपको जानकारी है, अत: बिहार के हित में, मैं आपसे आग्रह करके इस बारे में जानना चाहूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को लेकर प्रश्न किया है, उस योजना की डीपीआर बनकर जो पहले इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस वर्ष 2012 में हुआ था, वह बहुत ज्यादा पुराना होने के कारण रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेशन करके उसके रिवीजन को वापस करना और एक बार फिर नए सिरे से इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस देने की आवश्यकता थी।

(1155/MK/PS)

प्रपोजल के लिए वापस एसडीसी के पास जब विचार के लिए आया था तो हमने और सीडब्ल्यूसी ने इसे दोबारा बिहार सरकार से कुछ सूचना देने के लिए भेजा है। एक बार बिहार सरकार द्वारा उन सूचनाओं को देने के बाद उसका अप्रैजल करके उसके तदनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड का एक एक्सलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट बटेश्वर पंप नहर योजना है। पिछले 20 सालों से वह नहीं बन पा रहा है। उसके कारण गोड्डा, मेरे लोक सभा क्षेत्र में जो गंगा का पानी आना है, वह नहीं आ पा रहा है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है और पूछना है कि एआईबीपी की जो बटेश्वर पंप नहर योजना है, उससे किसनों को पानी मिलेगा या नहीं? क्या बिहार सरकार की लापरवाही के कारण वह पानी जिन्दगी में कभी नहीं आएगा? मुझे यही पूछना था। धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से उनकी चिंता जायज है कि राज्य सरकार के रवैये के चलते वह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से डिले हुआ, लेकिन यह कहना कि मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा तो हम सबको आशान्वित रहने की आवश्यकता और निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इस दृष्टिकोण से हमें सफलता मिलेगी। अभी मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय में माननीय सदस्य ने मुझे पहले भी पत्र लिखा था। मैंने उस पत्र को राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ किसी भी तरह का कोई प्रपोजल प्राप्त नहीं हुआ है।

(इति)

(Q. 65)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, Sir, while road safety is of primary importance, functionality and convenience of local population should also be considered. A greenfield highway is currently under construction from Sathupally to Devarapalli covering 80 kilometres, cutting across my Parliamentary segment. There are three SC segments and two ST segments in the path. It was initially a six-lane highway with service road on either side. I now realised that the service road was cancelled and it is causing a lot of hardship to the local farmers who have to approach their farmlands on a daily basis. It is adding a few extra kilometres for each of them. I was told that the service road was cancelled due to safety concerns and also it was an obstacle for speed of the highway because it was meant to be an express highway.

Hon. Speaker, Sir, development should be inclusive and it should not cause hardships to the local population or to anyone for that matter. So, I request the hon. Minister to consider providing for just a service road with no additional exits or entries to the highways. Land has also been acquired for the same. It can accommodate a service road as well. Without the service road, the local population are currently enraged and do not look at it as a road to development as there are only two entries and exits in the entire fifty-kilometre stretch.

Hon. Speaker, Sir, through you, I request the hon. Minister to look into this matter and try and provide for it.

Thank you, Sir.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Hon. Speaker, Sir, basically, the express highway is access controlled, and the speed on the express highway is more than 100 kilometres or 120 kilometres. Now, with the service road, there is an issue because we are already facing a very crucial problem related with road accidents, which has already been elaborated. Unfortunately, in 2021, the number of road accidents was 4,12,432, and in 2022, the number of road accidents was 4,61,312. That is a rise of 12 per cent in the accidents. In 2021, the number of deaths was 1,53,972 and at present, it comes to

(pp. 20-30)

1,68,491. That is an increase of 10 per cent. Now, the problem is that when we construct the express highway, there are a huge number of people who are demanding for an increase in the speed because some of them are driving on Delhi-Mumbai Express Highway at speeds of 140 kilometres or 160 kilometres, and they are asking me to relax the law related with speed.
(1200/SMN/SJN)

At the same time, some other people are asking me to reduce the speed and suggesting that the number of accidents are increasing because of speed. Now, the problem is this. If we can connect service road, then again it will be a problem. But considering the convenience of the people, we will try to connect wherever it is feasible. When you are presenting this problem to me, I will check and verify it and I will try to find the way out. But one thing is absolutely correct where I need cooperation from all the stakeholders related with road accidents. It is very unfortunate. It is a loss of GDP of about 3.14 per cent and the most unfortunate thing is that 67 per cent deaths are happening in the age group of 18-45 years. The young people are facing this problem. I am verry sorry for this. Unfortunately, it is a good success story of our department. We are trying our level best for the last nine years but we are not in a position to reduce the accidents and deaths. It is a problem of human behaviour. They have to obey the law. Maintaining lane discipline, possessing driving license, and not talking on the mobile phone at the time of driving are some small things for which we need cooperation from the people.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री कृष्ण पाल जी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियों को भरने की रीति, शुल्क ओर भत्ते तथा उनके कार्यनिष्पादन की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिलर्स के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/चिलर्स/40/2021-22 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/डब्ल्यूएम/06/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पोसोको), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पोसोको), नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायिकियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायिकियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सिलवासा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सिलवासा का वर्ष 2022-2023 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात), भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात), भोपाल का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) दूसरा संशोधन, विनियम, 2023 जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एलएम/पीएम/0024/2020/यूडीएवाई/पीओएल. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-24 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3915(अ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेस-दो के संरेखण (अलाइनमेन्ट) को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी दिनांक 16 नवम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 4939(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(6) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4370(अ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे भूमिगत रेल (परिचालन और संरक्षण) अधिनियम, 2002 में संशोधनों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1202 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विवरण

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय के बारे में विद्युत मंत्रालय से संबंधित 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) 'नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों में मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' विषय के बारे में शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण।

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति
249वां और 250वां प्रतिवेदन

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार) : महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 249वां प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 250वां प्रतिवेदन।

----

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1204 बजे

माननीय सभापति : श्री धर्मवीर सिंह जी।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं समागम व भाईचारे के लिए जानी जाती है। हमारा सामाजिक ताना-बाना दुनिया में सबसे अलग है। पूरी दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता के कायल हैं।

(1205/SPS/SM)

भारतीय समाज में सदियों से तयशुदा शादियों की परंपरा रही है। आज भी देश में लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने माता-पिता या सम्माननीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की गई शादियों को ही प्राथमिकता देता है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन की सहमति भी होती है। तयशुदा शादियां कई चीजों का मेल कराने के आधार को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। जैसा कि सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्य व पसंद और साथ ही उनके परिवारों की पृष्ठभूमि को भी प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में शादी को एक पारिवारिक पवित्र बंधन माना जाता है, जो सात पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में शादियों को जीवन भर चलाने के लिए माना जाता है। यहां तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 40 परसेंट की तुलना में मात्र 1.1 परसेंट है। यह देखा गया है कि तयशुदा शादियों में तलाक की दर बहुत कम होती है। हालांकि, हाल के वर्षों में तलाक दर में काफी वृद्धि हो रही है, जिसमें ज्यादातर वजह प्रेम विवाह होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि प्रेम विवाह में लड़का-लड़की के मां-बाप की सहमति को जरूरी बनाया जाए, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े भाग में सेम गोत्र व एक ही गांव में शादी नहीं होती है, इसलिए प्रेम विवाह से गांव में झगड़े बहुत होते हैं। इन झगड़ों में खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति जरूर बनाई जाए।

सभापति महोदय, आजकल समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो यह बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो लोग महिला या पुरुष बिना शादी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन यह बुराई अब हमारे यहां पर तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा भी भयानक है। हाल ही में श्रद्धा और आफताब का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है, बल्कि रोजाना कोई न कोई केस सामने आ जाता है। इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है, वरन् समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है। दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती

---

* Pl. see pp 319-322 for the list of Members who have associated.

थी, अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा।

इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, ताकि समाज से यह खतरनाक बीमारी खत्म हो सके।

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले ऐरोली कलवा ऐलिवेटेड महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रकल्प की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठाणे रेलवे स्टेशन की भीड़ का 40 प्रतिशत अतिरिक्त भार कम करने के लिए कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर के श्रमिक वर्ग के लिए सीधे नवी मुंबई तक पहुंचने के लिए यह मार्ग आसान हो जाएगा।

वर्ष 2014 में पहली बार सांसद चुनने के बाद रेल बजट में तत्कालीन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु से की गई मांग के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 428 करोड़ रुपये दिए गए। इस परियोजना का भूमि पूजन 10 दिसंबर, 2016 में प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी साहब और हमारे शिव सेना प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के शुभ हाथों से हुआ था। इस परियोजना में एमएमआरडीए द्वारा 1080 झोपड़ियों के पुनर्वासन के कारण इस परियोजना में देरी न हो, इसलिए इस परियोजना को दो चरणों में किया गया था। वर्ष 2018 में इस दीघागांव रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया था। यह दीघा गांव रेलवे स्टेशन पिछले 7-8 महीने से बनकर तैयार है। इस दीघा गांव रेलवे स्टेशन के लिए 90 करोड़ रुपये का खर्चा भी किया गया है। इस स्टेशन के शुरू न होने के कारण लोग ज्यादातर खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। यहां के नागरिक भी इस उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे है।

महोदय, इस संबंध में देश के आदरणीय पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी साहब, रेलवे मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री, मध्य रेलवे के प्रबंधक को चार बार स्मरण पत्र देने के बावजूद और इस स्टेशन के पूरा होने के बावजूद भी यह काम शुरू नहीं किया गया है। दीघा स्टेशन के आस पास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां हैं, रिलायंस है और बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए नौकरी के लिए आने वाले श्रमिक वर्ग तथा स्थानीय नागरिकों का पैसा और समय दोनों व्यर्थ हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन के न खुलने से सेंट्रल रेलवे को मिलने वाला राजस्व भी कम हो रहा है।

(1210/MM/RP)

हाल ही में दीघा रेलवे स्टेशन को चालू करने का अभियान चलाया गया था। उस समय हजारों नागरिकों ने यहां सभा की थी। मैं हमारे देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी साहब और रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पिछले सात-आठ महीने से यह स्टेशन तैयार है। मेरा निवेदन है कि इस स्टेशन को चालू किया जाए।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षेप में रखने का प्रयास करें।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में जनता द्वारा बिल्होर स्टेशन पर लगातार रेलगाड़ी के स्टॉपेज की मांग की जा रही है। ट्रेन संख्या 14151-

14152 कानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस, 19409-19410 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22443-22444 कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस और 05305-05306 कानपुर-अनवरगंज-लाल कुंआ स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज की मांग लगातार की जा रही है। इन ट्रेनों का स्टॉपेज बिल्होर स्टेशन पर किया जाए। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत संडीला स्टेशन पर भी 13307-13308 किसान मेल और साथ ही 13005-13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस के भी ठहराव की लगातार जनता द्वारा मांग की जा रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस बारे में निवेदन भी किया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि संदर्भित रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों के अप-डाउन ठहराव हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): बहुत-बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं अपनी कांस्टिट्यूएंसी के कांठ तहसील के बारे में बताना चाहता हूं। इस तहसील से नॉर्दन इंडिया में मेडिकल रुई और बैंडेजेस का पूरा बिजनेस होता है और सप्लाई होती है। व्यापारी लोग जम्मू बहुत जाते हैं। कोविड से पहले सियालदाह एक्सप्रेस नंबर 13152 और 13151 इस स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन कोविड के बाद इसको रोक दिया गया है। यह ट्रेन जम्मू तवी तक जाती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इसको तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि व्यापारियों को मुरादाबाद जंक्शन आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कांठ से ही अमरोहा जाने वाली रोड के ऊपर एक क्रॉसिंग है- 443बी, जिसके ऊपर जाम लग जाता है और इतना बड़ा जाम लगता है कि हरिद्वार मार्ग भी बाधित हो जाता है। इसके ऊपर एक ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे की बचत करके इनवेस्ट किया था, जमा किया था। उनकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी, आज करीब 12 साल से, सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं। उन लोगों ने इलाज के लिए और अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे रखे थे, वे नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से हजारों लोग देश भर में आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इनवेस्टरों को पैसा मुहैया नहीं कराया गया है। जबकि स्थिति यह है कि आज भी हमारी सरकार, सेबी, सुप्रीम कोर्ट और सहारा के मामले में फंसी हुई है। इस देश के जिन लोगों ने सहारा समूह में पैसा लगाया था, उस पैसे के अभाव में वे लोग बिना खाने के मर रहे हैं।

(1215/YSH/NKL)

महोदय, इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश की जो आम गरीब जनता है, उसका क्या गुनाह है? उसने तो अपना पैसा इसलिए इनवेस्ट किया था, कि यह सरकार की एजेंसी है और उसका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इनवेस्टर्स को पैसे दिलवाने में अपने आप को असमर्थ साबित कर रही है, जिसके चलते आज स्थिति दयनीय हो चुकी है। हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इनवेस्टर्स को, चूँकि जहां तक इनवेस्टर्स का सवाल है तो मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इनवेस्टर्स यू.पी. और बिहार के हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। यू.पी. के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2,200 करोड़ रुपये इनवेस्ट

किए थे। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1,500 करोड़ रुपये इनवेस्ट किए थे। इनमें से कितने ही लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि सारा काम छोड़कर उन इनवेस्टर्स को उनकी राशि दिलाने का कष्ट करें।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उस पर हम सभी को सहमत होना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप ऐसी अपील मत कीजिए। सभी माननीय सदस्यों का अपना-अपना विवेक है। आप अपनी स्लिप भेज दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी में 55 सालों से किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। मैं देश के पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ। वहां 55 सालों के बाद किसानों को पानी मिला है। इसके लिए वहां के किसान आनन्दित हैं। उस समय के महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी साहब का, मुख्य मंत्री साहब का और उप मुख्य मंत्री साहब का भी मैं अभिनन्दन करता हूँ कि 55 सालों के बाद 182 गांवों को पानी मिला है।

पानी मिलने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में जो घाटमाथा का पानी है, जो सह्याद्रि से समुद्र की तरफ जाने वाला पानी है, वह 115 टीएमसी पानी बांध के जरिए शिर्डी, नासिक और मराठवाडा को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इससे किसानों को लाभ होगा। वर्ष 2005 में महाराष्ट्र में समान जल वितरण अधिनियम कानून पास किया गया, जिससे किसानों का जो हक है, चूँकि बिट्रिश काल में अकाल पीड़ित तहसीलों को पानी देने का निर्णय किया था, उसके तहत अकोले, संगमनेर, कोपरगाँव तथा श्रीरामपुर और मेवासा को न्याय मिला था, लेकिन उसके बाद वर्ष 2005 में समान जल वितरण अधिनियम कानून पास होने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र का पानी कम हो गया है। पानी को उपलब्ध करवाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि घाटमाता का पानी उपलब्ध करवाया जाए। उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में मराठवाडा में जायकवाडी डैम बनाया गया था। उसमें 109 टीएमसी पानी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में नासिक नगर का जो पानी उपलब्ध है, वह 80 टीएमसी है। यह पानी उपलब्ध होने से हमें दिक्कत हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि 115 टीएमसी पानी को उपलब्ध करवाया जाए। गोदावरी, मुला और प्रवारा नदी के ऊपर कोल्हापुरी बांध बनाकर 15 टीएमसी पानी हमेशा के लिए किसानों को उपलब्ध करवाया जाए और किसानों को न्याय मिले। इसके अलावा 5 टीएमसी जो कि अतिरिक्त पानी है, उसे संगमनेर, कोपरगाँव तथा श्रीरामपुर तहसील को उपलब्ध करवाया जाए। ये किसान पानी से वंचित है, उन्हें आप न्याय दिलाने का काम करें।

मैं शिर्डी से सांसद हूँ। बाबा का श्रद्धा और समृद्धि का संदेश है। मैं आपसे विनती करूंगा कि 115 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाकर हमें 20 टीएमसी पानी उपलब्ध करवाया जाए। शिर्डी को 20 टीएमसी पानी दिया जाए। 10 टीएमसी पानी नासिक को दिया जाए और जो अतिरिक्त पानी है, उसको मराठवाडा और जायकवाडी को दिया जाए।

आप तुरंत महाराष्ट्र प्रशासन को निर्देश दीजिए तथा प्रस्ताव मंगवाकर राज्य की ओर से उसको मान्यता दिलवाइए।

(1220/MMN/RAJ)

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Chairman, Sir, I would like to raise an important issue related to farmers of Dharashiv and Solapur districts of Maharashtra. It is related to Surat-Chennai National Highway Project and Solapur-Tuljapur-Dharashiv Railway Line Project.

I would like to draw Central Government's attention to the issue of land acquisition for these two projects. The land acquisition process is going on for these projects. However, the farmers are demanding that the land acquisition should be done directly. That is because the farmers would get five times more compensation if the land is acquired directly. I would like to mention here that the land is being acquired forcibly and they are getting comparatively lesser amounts for their lands. Sir, through you, I would like to draw Central Government's attention towards the fact that the land was acquired directly for railway projects like Pune-Miraj broadgauge railway line, Baramati-Faltan-Lonand new railway line, Aadasa-Gadchiroli new railway line and the famers got 5 times more money for their lands. It is clearly mentioned in the State Government's 2015 GR that direct land acquisition should be done in national level projects. However, unfortunately, compulsory land acquisition is being done for Dharashiv-Tuljapur-Solapur railway line project.

Even for Surat-Chennai National Highway Project compulsory land acquisition is being done forcibly. Sir, Dharashiv is an aspirational district and maximum number of farmers commit suicides in this district only. Hence, justice should be done to these poor farmers. Adequate and logical compensation should be given to the farmers. Sir, India got Independence in the year 1947 but our Marathounda was freed in 1948. Sir, the land acquisition should be done directly so that the farmers of my region get five times more compensation for their lands. Thank you.

* Original in Marathi

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I would like to raise a matter relating to the suspended stoppage of trains at many railway stations in Kerala after the COVID-19 pandemic.

Now the situation has changed and normalcy is restored but the suspended stoppages are not restored at many railway stations. Also, many problems faced by the train passengers while travelling in Kerala are not addressed. On the fourth of this month, two female students travelling in Parasuram Express fell unconscious in a suffocating stampede. Due to the uncontrollable rush, the train passengers in Kerala have been facing a miserable journey after the COVID-19 pandemic. Due to insufficient number of trains, many passengers have to rely on the same train both in the morning and in the evening. Holding up trains, including the passenger trains, to allow other trains to pass causes physical inconvenience to the passengers and also makes it difficult for them to reach the schools, workplaces, and to attend to other needs on time.

Due to the Sabarimala pilgrim season and the Christmas holidays, there will be rush of passengers from the neighbouring States of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and also from the metro cities like Delhi and Mumbai to Kerala.

I, therefore, request the hon. Railway Minister to sanction more passenger and special trains from the metro cities to avoid rush during the Christmas, Sabarimala pilgrim and new year seasons. Thank you.

(1225/KN/VR)

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Salem is an important commercial hub of Tamil Nadu. Thanthai Periyar at a conference held in Sooramangalam way back in 1952 put forth the demand for cration of a separate Railway Division in Salem for the economic development of this region. Our departed leader Late Shri Veerapandiyaar also organised several demonstrations for the creation of Salem Railway Division.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Hon. Member, have you changed your subject? You are not speaking on the subject which you have mentioned in the list.

*SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Sir, it is the same subject which I submitted.

In the year 2006, the then Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar inaugurated the new Salem Railway Division. This Railway Division is part of Southern Railways and it was separated from Palakkad in 2006 to be created as a separate division. It covers 15 districts of Tamil Nadu spreading over an area of 795 kms. Coimbatore Junction is a famous railway station. A pit line, which is necessary in every Division should be set up in Salem Railway Division so as to cater to the maintenance of railway coaches. There is no engine turn around facility in the Salem Division. I urge that the pit line facility should be set up facilitating maintenance of railway coaches and to operate trains in new routes. Salem town railway station, which was in operation near Ponnammapet, should be made functional as Salem East railway station. Trains like Salem-Chennai Egmore Express, which stand unattended in Salem Junction during day time, may be attended for maintenance if pit line is set up here, besides operating it between Salem and Coimbatore or Salem and Trichy. I urge that a second railway terminal should be set up at Ayodhyapattinam. Salem-Mayiladuthurai Express train, Salem-Coimbatore passenger train, Salem-Katpadi passenger train can be operated from this terminal benefitting the people living in and around Salem Sevvaipettai and Salem Town railway stations. I urge the Government for providing escalator facilities on Platforms 1 and 2 of the Salem railway station which can benefit aged and differently-abled persons. Even though Salem is a Railway Division, EQ is not being released from this Division. We have to approach Bengaluru, Trivandrum and Palakkad Divisions for getting EQ cleared. Therefore, I urge that EQ for all the trains plying through Salem should be released from Salem Division itself. A railway level crossing between Omalur and Mettur is always seen crowded and there is heavy traffic jam due to closure of gates. Thousands of vehicles ply on this route and there are more than 150 industries situated in this area. Thousands of tourist vehicles also use this road. I, therefore, urge that a railway overbridge be constructed across the level crossing between Omalur and Mettur. The Chennai-Salem Express (No. 22153) now departs from Chennai in the middle of the night at 1155. Passengers face several difficulties because of this. I request the Railway Ministry that this Train be made to depart from Chennai at 1040 pm or 11 pm as was the practice before Corona pandemic. Thank you.

माननीय सभापति : आपने पूरा चार्टर आफ डिमांड पेश कर दिया है।

---

* Original in Tamil

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सुवर्णरेखा परियोजना (SMP) के खरकई दाई मुख्य नहर से निःसृत मुराकाटी शाखा नहर के टनल के एकरारनामा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उक्त संबंध में वर्ष 2019 में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा फास्ट ट्रैक परफॉर्म क्लियरेंस (FTPC) के अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के लिए 14,959.744 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण का प्रस्ताव सम्मिलित था। पूर्व में वर्ष 2010 में प्राइस लेवल पर परियोजना की कॉस्ट 6613.34 करोड़ रुपये के इनवैस्टमेंट क्लियरेंस प्राप्त कर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1/PMC/कार्य-996/2017–46/20-21 रांची, दिनांक 19.03.2021 द्वारा परियोजना को 12,849.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

(1230/PC/SAN)

मुराकाटी शाखा नहर के निर्माण कार्य को सुसुप्तावस्था में रखा गया। मुराकाटी शाखा नहर के कुछ भाग में तीन इकरारनामों के तहर इकरारनामा संख्या SBD-01/2019-20, SBD-02/2019-20 तथा SBD-03/2019-20 दिनांक 11.01.2020 के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने का इकरारनामा 11.01.2020 को किया गया था। उस समय राज्य सरकार द्वारा तीन टनल्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इकरारनामा होने के साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त दिनांक 17.05.2023 को तीन टनल के निर्माण कार्य को बन्द करा दिया गया है।

महोदय, उल्लेखनीय है कि मुराकाटी शाखा नहर से जादूगोड़ा, मुसाबनी एवं डुमरिया प्रखण्ड के करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो मुख्यतः आदिवासी किसानों का है। गाजिया स्थित खरकई नदी पर वर्ष 2019-20 में रुपए 500 करोड़ की लागत से बैराज बनकर तैयार है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में यदि मुराकाटी शाखा नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया होता तो गरीब किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो गई होती। विगत चार वर्षों से औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग, रांची द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

मैने दिनांक 12.09.2023 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली को टनल के तीनों इकरारनामों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था, परंतु 2,000 की अनुसूचित दर पर, टनल का निर्माण कार्य पूरा कर, इकरारनामा जीवित कर 2,000 की अनुसूचित दर पर पूरा करने का निर्णय किया गया था।

अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुराकाटी शाखा नहर के टनल के तीनों इकरारनामाओं को पुनर्जीवित करने हेतु झारखण्ड सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति : इतना विस्तार से बोलना अपेक्षित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कुलदीप राय शर्मा जी।

… (व्यवधान)

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

सर, मेरे क्षेत्र अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक ही म्यूनिसिपल काउंसिल है, जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल है। इस म्यूनिसिपल काउंसिल में करीब चार हजार मजदूर काम करते हैं। इसमें रेगुलर मजदूर हैं, कैजुअल मजदूर हैं और डेली वेजर मजदूर हैं।

सर, वर्ष 1999 में म्यूनिसिपेलिटी ने कचरे की सफाई करने के लिए वहां करीब 1,195 डेली वेजर मजदूरों को लिया था, जिनको एक दिन में सिर्फ 50 रुपए दिए जाते थे। ये 1,195 जो डेली वेजर मजदूर हैं, इनको वर्ष 2015, 2017 और 2020 में बैच-वाइज़ कैजुअल किया गया था।

सर, मेरी आपके द्वारा सरकार से यह मांग है कि ये जो हमारे 1,195 मजदूर भाई हैं, जो वर्ष 1999 से काम कर रहे हैं और अब वर्ष 2023 हो गया है, करीब 24 सालों की उनकी सर्विस हो गई है। वे लोग कचरा साफ करते-करते बीमार हो गए, उनकी हेल्थ की कन्डीशन ठीक नहीं है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। एक-एक आदमी आज 20 सालों से ज्यादा काम कर चुका है। उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे 1,195 डेली वेजर मजदूर भाई हैं, उनको जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट एज भी पास आ चुकी है। यदि उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा, तो उनके साथ यह बहुत ही ज्यादती होगी। इन इंसानों ने अपनी पूरी जिंदगी अंडमान और निकोबार के लोगों की सेवा में बिताई है। कोरोना के समय भी इन लोगों ने बहुत काम किया था। यही मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र में लगभग दस हजार परिवारों का घर उजाड़ने की एक साजिश की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश में चार करोड़ बेघरों को छत देते हैं, वह योजना दिल्ली में रोकी जाती है। ऊपर से जहां दिल्ली के बुराड़ी और तीमारपुर विधान सभा में दस हजार परिवार 40 सालों से बसे हैं, उन पर दिल्ली सरकार ऑर्डर करती है कि इनको तोड़ दिया जाए और उसे evacuee land घोषित किया जाता है।

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वह खाली लैंड है, जबकि 40 सालों से लोग वहां बसे हुए हैं। पीएम-उदय योजना में जहां दिल्ली की सभी अनाधिकृत कालोनियों को हमारे

प्रधान मंत्री जी ने 'As is, where is' मान्यता दे दी है, उसमें शामिल है, उसके बाद भी वहां के लोगों को पता ही नहीं कि उनका केस चला और वे हार गए हैं। हमें दोबारा हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब स्टे मिला है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे अत्याचार के खिलाफ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

(1235/CS/SNT)

आखिर किसको फायदा पहुँचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 40 साल से बने मकानों को तोड़ने की साजिश की और ऐसा घोर निन्दनीय कृत्य करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए भी कार्रवाई की जाए। सरकार हस्तक्षेप कर इन 10 हजार गरीब परिवारों को बचाने की कोशिश करे। यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir.

My Zero Hour submission is relating to Anganwadi workers and Anganwadi helpers. I hope that the entire House will associate with my submission because the life of Anganwadi workers and helpers is in a very pathetic situation. The salaries and benefits of Anganwadi workers are meagre and they are not able to meet their essential day-to-day expenses. At the same time, the responsibility of the Anganwadi workers and helpers are very high but the benefits available to them are very, very less. It is negligible. Even in my State, salary of the Anganwadi workers is less than Rs. 13,000 per month. This is a meagre allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers.

So, my submission is this. A Private Member Bill has already been introduced in which I have demanded for extending ESI benefit to the Anganwadi workers. It has not been considered so far. The responsibility is very high and they have to retire without getting any pension. There is no retirement benefit. Nothing is there. After 20 years or 30 years of service, an Anganwadi worker and helper has to retire without getting a single paisa as pension or gratuity or insurance. Nothing is there. There is no medical benefit. Nothing is there.

So, I request the Government to come out with an official Bill providing a number of facilities. Minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers and helpers. Not less than Rs. 25,000 for the workers and a minimum Rs. 20,000 to the helpers should be provided. The second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. The third one is, retired Anganwadi workers and helpers may be provided with a minimum

pension of not less than Rs. 5,000. For this, I urge upon the Government to come out with a Government Bill so as to provide all these benefits to our Anganwadi workers and helpers. I request the hon. Government to respond to it. … (*Interruptions*)

Sir, this is a very important matter. I hope that the Government will respond to it. Cabinet Ministers are here. Unfortunately, they are not even listening to it. It is quite unfortunate. We are seeking a response from the Government regarding extending benefits to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. That has to be taken very seriously because it is a Central as well as a State-sponsored scheme. They have to be protected. They are a major workforce of our country. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): जो भी माननीय सदस्य इस विषय के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, कृपया वे अपनी स्लिप भेज दें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, once again, I urge upon the Government to consider this request. Thank you very much, Sir.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman Sir.

The tussle between the Governor of Kerala and the State Government has put the entire higher education administration and governance on a standstill and it is impacting the delivery of quality learning and critical areas of research. The lack of appointment of Vice Chancellors in almost all universities is causing a total halt in continuity of administration and academics. This situation demands an immediate resolution.

The educational excellence achieved in the higher education sector is under question as the political tension between the Governor and the State Government led by the Chief Minister is impacting the quality of education in the universities of the State of Kerala. Posts of academic significance, like that of Vice Chancellor, are being used and exploited for satisfying political points, which is a blatant violation of UGC norms and guidelines. The controversy surrounding the appointment of Dr. Gopinath Ravindran is the latest of such shameful incidents that erode the quality of higher education in Kerala. The same is the experience with appointment of Vice Chancellors in Kerala Technical University, Fisheries University, and other universities.

(1240/AK/IND)

There are at least 14 Universities that do not have regular Vice-Chancellors. The purpose of educational excellence and research output of national importance is not achieved as these institutions have become battlegrounds for political contests and people of loyalty rather than academic quality are being appointed through the backdoor. This is a very serious situation in Kerala.

The higher education in Kerala is also facing a serious problem because the Governor and the State Government are going different ways. The Governor is appointing a Vice-Chancellor and the State Government is appointing another Vice-Chancellor. So, the entire higher education system is totally paralysed. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please put your demand now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Yes. Now, the students are going abroad because of this issue. Dropouts issue is also there in colleges and universities of Kerala. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Next is Shri Vincent H. Pala.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): A number of students are going out of the State. This is a very serious matter. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Every issue raised in this Parliament is very serious.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Yes. This issue is related to education. Everybody is aware that education system in Kerala is appreciated by everyone, but the recent situation in Kerala -- where the Governor and the State Government are going in different ways -- is causing the entire system to collapse. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Yes. I would like to request the Government of India, especially the Ministry of Education, to interfere in this matter and ensure that quality education in higher education sector is provided to the students in Kerala. Thank you.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Chairman Sir, I urgently seek your intervention in urging the Government of India to make a decisive determination on the implementation of the In-Line Permit (ILP) in the State of Meghalaya.

In 2019, the State Assembly of Meghalaya had passed a Resolution that the ILP be implemented as soon as possible. Regrettably, the citizens of Meghalaya continue to grapple with uncertainty as the Government of India is yet to provide clarity on the matter, causing unrest and confusion.

I respectfully implore you to leverage your esteemed position to prompt the Government of India to make a clear and timely decision regarding Meghalaya's inclusion under the ILP thereby offering much needed clarity to the people of Meghalaya.

The establishment of ILP was intended to protect the people from exploitation and alienation. Over time, the ILP system has undergone a significant evolution. Regulations have been relaxed and diverse categories of permits have been introduced to cater to various needs, making the system adaptable.

The implementation of ILP in Meghalaya will protect the tribal communities and will also contribute to sustainable development of the region by regulating resource mobilization and equal distribution to the people. Thank you, Sir.

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): सभापति जी, मेरे लोक सभा अहमदनगर के निर्वाचन क्षेत्र में भिंगार कंटोनमेंट का निर्माण सन् 1879 में किया गया और आज वर्ष 2023 तक करीब 25 हजार सिविलियन पापुलेशन उस कंटोनमेंट एरिया में रिसाइड करते हैं। कंटोनमेंट एरिया डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से सिविलियन्स को काफी दिक्कत होती है जैसे कि ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई है, एफएसआई की दिक्कत है, एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आदि हैं। पिछले 25-50 सालों से यहां जितनी भी सिविलियन पापुलेशन है, उनके द्वारा इतनी दिक्कतों का सामना किया गया है कि हर बार मांग हुई कि हमें म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में लिया जाए। इसी के तहत हमारे देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी की पहल से 16.10.2023 और 26.11.2023 को दो उच्च स्तरीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आफिशियल्स के मीटिंग्स की गईं और यह तय किया गया कि भिंगार कंटोनमेंट एरिया एबोलिश करके इसकी सिविलियन पापुलेशन को अहमदनगर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में समायोजित किया जाए। इसी के तहत 3.12.2023, पिछले सप्ताह एक मीटिंग अहमदनगर में की गई, जिसमें सारे सिविलियन्स को विश्वास में लेते हुए सभी ने इस बात से सहमति दी और सभी ने यही राय जताई कि हमें अहमदनगर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में आना है।

(1245/RV/UB)

सभापति जी, इसी के तहत मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय से यह विनती करना चाहूंगा कि excision of Bhingar Cantonment area from Cantonment Board, and inclusion in Ahmednagar Municipal Corporation की जो प्रक्रिया है, वह जल्द से जल्द पूरी की जाए और तीन महीने में इन सिविलियन्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में समायोजित करके इनकी सारी समस्याओं का हल ढूंढ़ा जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, मैं आज बिहार के 14 करोड़ लोगों का दर्द उठाने के लिए, उनका विषय उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदना इस विषय के साथ होगी।

महोदय, इस देश में कहीं एक मौत हो जाती है तो लोग चिंता व्यक्त करते हैं। तीन दिन पहले कर्नाटक के विजयपुरा जिले में सात मजदूर, जो हमारे यहां बेलदार कहलाते हैं, उनकी मौत हो गयी। एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मक्के के ढेर लगे हुए थे, उसमें उनकी मौत हो गयी। आप इसका अनुमान लगाइए। मैं उनकी चीख लेकर, बिहार के गरीबों की चीख लेकर इस सदन में आया हूं। वहां गोदाम में बोरे गिरने से सात मजदूर चीख-चीख कर मर जाते हैं। आप अनुमान लगाइए कि कैसी व्यवस्था रही होगी। ये हमारे बिहार के मजदूर हैं। ये बेलदार थे, जो बोरियां उठा-उठा कर रखते थे। वे एक ही जाति के थे। हम लोग यहां सदन में देश के भविष्य के बारे में और नौजवानों की बात करते हैं। उनकी आयु क्या थी? एक की आयु 18 वर्ष थी, दूसरे की आयु 20 वर्ष थी, तीसरे की आयु 33 वर्ष थी, चौथे की आयु 44 वर्ष थी। इसमें मरने वाले कौन-कौन हैं? एक का नाम राजेश मुखिया है, जो पिछड़े समाज से आते थे, खगड़िया से थे। उसमें शम्भु मुखिया बेगूसराय के थे, रामबृज समस्तीपुर के थे। आप इन गरीबों में पूरे बिहार का नक्शा देखिए। कृष्णा बेगूसराय से थे, लोकू यादव पटना के निकट के थे। दुलार चन्द बेगूसराय के थे, राम बुध मुखिया समस्तीपुर के थे।

महोदय, मैं इन गरीबों की पहचान नहीं बताना चाहता, बल्कि ये सब पिछड़े समाज के थे, जिस समाज की दुहाई बिहार सरकार लगातार देती रहती है, जिन गरीबों के वोट के सहारे लगातार पिछले 35 वर्षों से शासन कर रही है। पूरे भारतवर्ष में यही कहानी है। पुणे में स्लैब गिरता है तो वहां मरने वाला मजदूर बिहारी है। बेंगलुरु के सेप्टिक टैंक में सफाई करने वाला मजदूर बिहारी है। दिल्ली की मंडी में आग लगती है। उसमें 36 लोग जल कर मर जाते हैं। वह मजदूर बिहारी है। पंजाब के लुधियाना में खेत में काम करके अपने घरों में सोने वाले मजदूर बिहारी हैं। हैदराबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से मरने वाला बिहारी है। कश्मीर की घाटियों में वे अपना पेट भरने जाते हैं, वहां खोमचे लगाते हैं और आतंकियों की गोली से मरने वाला भी बिहारी है।

महोदय, मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि इसके साथ पूरे सदन की संवेदना होगी। बिहारी आगे है, पर बिहार पिछड़ा है। यह क्यों है? यह एक सवाल है। इसी सवाल के साथ इन मरने वाले मजदूरों की आवाज और चीख लेकर मैं यहां आया हूं। मैं बिहार से हूं। बिहार की 14 करोड़ आबादी में से किसी को यह बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़

कर चले गए हैं। उस 4 करोड़ में से तीन करोड़ वे लोग गए हैं, जिसकी जातीय जनगणना बिहार की सरकार कराती है और जिनके वोट की राजनीति करती है।

महोदय, मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं कि यह गिनती का धोखा है। आज मैं यहां से मांग करता हूं। यहां पर हमारे बहुत मित्र बैठे हैं, मलूक साहब बैठे हैं, बेगूसराय के हमारे पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अहलुवालिया साहब बैठे हैं, केरल के हमारे मित्र बैठे हैं।

महोदय, पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी की हालत में काम करते हैं। आप ट्रेनों में इनकी हालत देखिए। मैं कर्नाटक सरकार से कहूंगा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं उन मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार से दस लाख रुपये के मुआवजे की मांग करता हूं। बिहार की सरकार से मैं मांग करूंगा कि हर मरने वाले मजदूर को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएं। मैं यह भी मांग करूंगा कि आने वाले दिनों में अगर देश में कोई भी मजदूर मरता है तो उसे एक-एक करोड़ रुपये दिये जाएं, क्योंकि ये चार करोड़ लोग, जो बिहार से बाहर पूरे भारत में रहते हैं, ये बिहार सरकार का खर्च चलाते हैं। मेरी बिहार सरकार से मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। मैं पूरे भारत की इस संसद में यह विषय उठाना चाहता हूं कि आपकी संवेदना उस गरीब बिहारी के साथ होनी चाहिए, जिसकी बात मैं उठा रहा हूं।… (व्यवधान)

अगर सदन सहमत है तो ताली बजाकर सहमति व्यक्त करें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): नहीं, नहीं, ऐसी अपील नहीं करनी चाहिए।

(1250/GG/SRG)

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद एवं जोहार।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ प्रहार कर के देश को गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए अपनी सरकार चलाएंगे। जिसका परिणाम हुआ कि झारखण्ड के अंदर मुख्य मंत्री से ले कर अधिकारी तक सभी ईडी की ज़द में हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है और करोड़ों-करोड़ रुपये बरामद हो रहे हैं। मुख्य मंत्री के निकट की एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिसको पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके सीए के यहों से 20 करोड़ रुपये नग़द बरामद हुए। उसने कई सौ करोड़ रुपये लगा कर रांची में एक बड़ा अस्पताल बनाया था। उस अस्पताल को ईडी ने अटैच कर लिया है और संपत्ति ज़ब्त कर ली है। उस अस्पताल में हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, दिमाग संबंधी और कैंसर संबंधी बड़े-बड़े उपकरण लगे हैं। आपके माध्यम से मेरा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है कि उस अस्पताल को देवघर एम्स के साथ अटैच कर एक्सटेंशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि झारखण्ड के लोगों का भला हो सके और वहां पर रिम्स की जो कुव्यवस्था है, उस पर लगाम लगे तथा इस काली कमाई, जो झारखण्ड की जनता से कमाई गई है, उसका सदुपयोग हो सके।

यह आग्रह मैं आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से करना चाहता हूँ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I wish to draw the attention of the hon. Education Minister and the Chairman of the University Grants Commission towards the plight of the non-NET Ph.D. research fellows concerning the stipend they receive.

As you are aware, these are for researchers who do get scholarships through the UGC NET exam. However, the researches get a stipend of Rs. 8,000 a month with a contingency of Rs. 10,000 per annum for Science subjects, and Rs. 8,000 per annum for Humanities and Social Science subjects, which has remained the same since 2006. Unlike other fellowship programmes, the stipend is yet to be subject to revision. Normally, revisions take place every four years. There should normally have been four upward revisions in the fellowship amounts they are getting. UGC is responsible for ensuring a conducive environment for scholars to conduct research. However, delayed revisions have imposed a financial burden due to the rise in inflation. We all know how prices are rising in our country. Living costs are going up, impacting their daily lives and their commitment to doing meaningful, effective, impactful research. The fact is that money is only part of the problem. The research scholars are also facing difficulties due to insufficient resources in their institutions like the infrastructure of the research institutes, inadequate support from their supervisors, and the absence of grievance redressal committees. The Government must address these and also ensure regular disbursements of the stipend without delays.

I therefore, urge the Minister to consider hiking significantly the stipend amount of the non-NET fellows as their contributions are pivotal in advancing our nation's growth in research and development.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं, आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां राजस्थान के मूंग व चना किसानों की फसल के वर्ष 2020-21 के लगभग 2 करोड़ 25 लाख रूपए हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड (HIL) पर बकाया है। मेरे व्यक्तिगत रूप से अनेकों बार विभाग से अनुरोध करने पर भी मेरे संसदीय क्षेत्र के इन किसानों को अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं हो सका है। वर्ष 2020-21 में HIL द्वारा यहाँ के किसानों से लगभग 868 क्विंटल चना और लगभग 1710 क्विंटल मूंग खरीद की गई थी, जिनका भुगतान भी अभी तक बकाया पड़ा हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और ये सभी लोग मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हो रहे है।

इसी प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) के द्वारा खरीद किये गए गेहूँ की आढ़त राशि का भुगतान भी अभी तक मेरे लोक सभा क्षेत्र में व्यापारियों

को नहीं मिला है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में गेहूँ की खरीद की गई थी, जोकि 30 जून, 2023 को बंद हो गई थी, उसका पोर्टल बंद हो गया था। व्यापारियों ने इसके पहले आढ़त के बिल को एफसीआई के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी यहाँ के व्यापारियों को उनकी आढ़त का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण उन व्यापारियों को भी लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन और विभाग का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसानों और व्यापारियों उनके भुगतान की सम्पूर्ण बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने हेतु सम्बंधित विभागों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(1255/MY/RCP)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, आप हाउस एडजर्न करने वाले हैं, तब तक और कुछ जीरो आवर ले लीजिए। मेरी भी यही राय है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): इसे मैं ले रहा हूं, लेकिन कृपया आप एक मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए। इससे हमारे अधिक माननीय सदस्य अकॉमडेट हो पाएंगे।

*SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): I thank you, hon. Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on an important issue. Haridwar-Ganganagar Inter-City Express Train (Nos.14525 and 14526) has been discontinued. The reason given is that there will be fog during this time. But the commuters with monthly passes and season tickets who travel to and fro daily are facing a lot of problems. In my constituency Patiala, over 1000 people commute daily for job related purposes. So, I urge upon the hon. Railway Minister that this train be restored at the earliest, keeping in view the jobs of thousands of commuters.

Thank you.

* Original in Punjabi

माननीय सभापति: श्रीमती हेमामालिनी जी।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूं कि तीनों राज्यों में हमें अपार सफलता मिली है।

माननीय सभापति: तो फिर सभी को बधाई देनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): महोदय, मैं अपने नेता नरेन्द्र मोदी जी और उनके साथ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।
मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई।

I would like to draw the attention of this august House to the excitement with which Mirabai's 525th *Janmotsav* was celebrated in my constituency Mathura on 23rd November, 2023. On behalf of my *Brijwasis* and myself, I would like to thank our hon. Prime Minister for making the event so memorable by his solemn visit and presence.

It was a privilege to have our hon. Prime Minister who released a commemorative stamp on Mirabai and also a coin that marks her 525th Birth Anniversary. Mathura being such a culturally vibrant and dynamic region, we had to have a cultural presentation. And I am grateful to Modi ji for witnessing a dance ballet on Mira, on her life by my troupe and myself. It was a humble offering, but his appreciation and words of encouragement overwhelmed each one of us. So, we are truly fortunate. In fact, his presence at the *Janmotsav* brought alive the bhakti of our people towards Mira, who was given less importance in general by the seekers of the Lord.

Sant Mirabai's sojourn and stay in Vrindavan in the 16th century had contributed immensely towards the rejuvenation and enrichment of the Bhakti movement that would last for ages to come. Her unwavering devotion to Lord Krishna, despite facing great hurdles, is legendary and is a subject of folklore in our country.

The hon. Prime Minister in his brief address on the occasion had rightly captured Sant Meera Bai's impact on the cultural-religious significance in the country when he said that Mirabai had nurtured the consciousness of India with her devotion and spiritualism. The People of Braj are proud that our hon. Prime Minister has expressed his desire to support the all-round development of the land of Braj. My heartful gratitude to Modi ji for his consistent efforts and his tireless work for the people of Bharat. With his kind bhakti each one of us is certain that our rich heritage will be forever preserved.

Thank you so much.

(1300/CP/PS)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री राम कृपाल यादव जी।

कृपया समय का ध्यान रखें, नहीं तो अधिक माननीय सांसद नहीं बोल पायेंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण लोकहित के मामले पर बोलने के लिए इजाजत दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, पीड़ा के साथ रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में एक बहुत ही पुरानी परियोजना रेल से संबंधित है, वह है बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन। इससे केवल मेरे ही संसदीय क्षेत्र को लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि पाटलिपुत्र के अलावा, जहानाबाद, काराकाट, औरंगाबाद, चार संसदीय क्षेत्रों से होकर यह रेल लाइन जाएगी और लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। यह लगभग 118 किलोमीटर की योजना है। इसको वर्ष 2007 में स्वीकृति मिली। कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यह काम नहीं हुआ। वहां योजना को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर एजीटेशन चल रहा है। उस समय की तत्कालीन सरकार अगर वर्ष 2007 में धनराशि देती, तो शायद यह स्थिति नहीं होती। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा धनराशि नहीं देने के कारण यह लागू नहीं हो सका।

मैं आपके माध्यम से निवेदनपूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जन-आंदोलन को देखते हुए बिहटा-औरंगाबाद परियोजना को तुरंत लागू किया जाए। सरकार धनराशि आबंटित करे, ताकि वहां पर सपना साकार हो सके। उस इलाके में विकास की यह महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।… (व्यवधान)

*SHRIMATI PRAMILA BISOYI (ASKA): The Parliament has passed the Women's reservation bill which was much awaited during the last special session. However, there are several weaknesses that should be rectified at the earliest possible to make this Act robust.

It is well known that economic empowerment of women significantly contributes to their social and political empowerment. As such helping women to achieve economic independence by enabling them to be gainfully employed has been accorded the highest priority; and empowerment of women is one of the key development initiatives identified by the Government of Odisha. Therefore, promotion of Women's Self-Help Groups (WSHGs) under the aegis of 'Mission Shakti' programme was adopted in 2001 as a key strategy for achieving women's empowerment. The model has already been created by Hon'ble Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji to empower women economically through Women Self Help Groups under mission Shakti, which is a flagship programme of the Government, so that women can have a say in policy-making process at various levels. Just to give the hon. Members an estimate, more than 70 lakh women have been organized into more than six lakh Self Help Groups in all blocks and urban local bodies of my State Odisha. Sir, I myself am an example. I could become an elected Member of this august House representing the Self Helf Groups of Mission Shakti, which was envisioned by our visionary leader Naveen Patnaik way back in 2001. Further, to achieve the dream of USD 5 trillion economy of hon. Prime Minister, all-round empowerment of women is a must. My appeal to the Government of India is to implement this Act in letter and spirit for the upliftment of women, who have been marginalised since centuries, politically, socially and economically. Vande Utkal Janani. Jai Jagannath. (ends)

$SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): Respected Chairman Sir, I represent the Bardhaman-Durgapur Lok Sabha constituency. My area is known as the granary of West Bengal, i.e. it is the rice bowl of the country with its hundreds of rice mills. Last year, on 31st October 2022, to extend a helping hand to our neighbouring country Nepal, A notification has been issued to export 6 lakh metric tonnes of duty-free paddy to that nation. We all know that when paddy is thrashed, we get rice, broken rice, rice husk, rice bran. Bran oil is produced from bran and ethanol is manufactured from broken rice. After oil is extracted, the rice husk and rice cakes are used as fodder for animals. But due to the policy of export, the rice mills of the region have been adversely affected. The ethanol plants, solvent plants have been severely affected. Now again I have come to know that they are asking for additional ten lakh metric tonnes of paddy. Through you Sir, I humbly request the Central government, the Ministry of Commerce and Ministry of Finance that kindly look into this issue. Otherwise, thousands of people in this area will become jobless, all the mills will become dysfunctional and the price of paddy will increase in our region if the practice continues. It means cost of rice will shoot up, price of solvent oil and ethanol will also go up. To guard the people from such grave crisis, I request that the notification may be revoked and no new circular may be issued further. Thank you, Sir.

(ends)

---

* Original in Odia.

$ Original in Bengali.

(1305/SMN/NK)

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज बेमौसम बरसात के कारण अमरावती, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बहुत सारे किसान भाई-बहनों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं इस बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करती हूं। राज्य सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। हमारे यहां सोयाबीन, कपास, चना तूर, मूंग, प्याज, अंगूर, संतरा होता है। मैं उस दिन नासिक गई, नासिक में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज भी बेमौसम बरसात हो रही है। मैं आग्रह करना चाहती हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर हमारे महाराष्ट्र के किसान भाई-बहनों को आर्थिक मदद करे। आप कर्ज माफी या उनके नुकसान की भरपायी करके महाराष्ट्र के किसान भाई-बहनों की मदद कीजिए।

*Sir, in my constituency Amravati, due to heavy rains, the standing crops are destroyed completely and the farmers have incurred heavy losses. They have landed in a financial trouble. Hence, I would like to request the Union Government to come to their rescue and declare a complete loan waiver for these distressed and needy farmers of my constituency.

It is the need of the hour that the State and the Central Government should extend their support to these farmers. Otherwise, we would lose them permanently and repentance would be of no use later.

Thank You.

(ends)

* Original in Marathi.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I would like to point out the issues and concerns related to the plantation labourers of my Constituency. I have raised this matter here many times. Many of the plantation labourers are in severe crisis. Their management is not able to run day-to-day affairs. Workers are not getting their gratuity. For the last ten years, they are not getting their gratuity benefit. That is not a benefit. That is the right of the plantation labourers but the management is not giving it properly. That is why, I urge upon the Government to issue at least Rs. 50 crore so that the gratuity benefit can be released to plantation labourers of my constituency.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह संदेश आया कि हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 आइटम्स पर दिया जाता है। उसमें जूट का एक क्विंटल का भाव पांच हजार पचास रुपये तय हुआ है।

मैं हिन्दुस्तान के उस जिले से आता हूं, जिस जिले में सबसे ज्यादा जूट की पैदावार होती है। वहां लाखों की तादाद में किसान, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि सारे बंगाल में जूट ग्रोवर के रूप में वह माना जाता है। लेकिन जेसीआई उससे जूट की खरीद नहीं करते तो यह ब्योरा देने का क्या मतलब है? अगर जेसीआई जूट उन लोगों से न खरीदे तो वे बेचारे किसान कहां जाएं?

बाजार में बिचौलिया है, बाजार में महाजन लूट रहे हैं। इसके साथ-साथ नेशनल जूट बोर्ड बहुत बात करती है कि हम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाने में मदद देकर मार्केट एक्सपोजर देंगे। वहां के जो किसान जूट के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी धांधली कर रहे हैं। आज जूट ग्रोवर की हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है।

मैं सदन से गुजारिश करूंगा, मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त रहेगा कि जब सदन में बताया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पांच हजार पचास रुपये है। कितने किसानों ने पांच हजार पचास रुपये में कितना जूट बेचा है, इसका भी ब्योरा देना चाहिए।

(1310/SK/SM)

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय सभापति, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया, जिसमें ग्राम सभा से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति मैरिट के आधार पर शिक्षा मित्र बनता है। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पिछले 23 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार द्वारा सभी शिक्षा मंत्रियों को दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से कराया गया था। वर्तमान में शिक्षक की योग्यता के मानक एनसीटी द्वारा निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शिक्षा मित्रों ने मानक पूरे कर लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस महंगाई में शिक्षा मित्रों से 10,000 प्रति माह मानदेय पर कार्य करा रही है, जबकि बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में शिक्षा मित्रों

को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन एवं अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान करे।

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): माननीय सभापति जी, मैंने इससे पहले भी कई बार सदन में यह मुद्दा उठाया है कि मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दरंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि नोडल डिस्ट्रिक्ट भी है, अभी तक रेल लाईन की कोई कनैक्टिविटी नहीं है। मैं इस विषय को बार-बार उठा रहा हूं, सुना है इसका सर्वे भी हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका स्टेटस क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दरंग डिस्ट्रिक्ट को रेल लाईन मैप में सम्मिलित किया जाए।

31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2024 में देवघर में ऋत्विक कांफ्रेंस हो रही है। नॉर्थ-ईस्ट से काफी संख्या में डिवोटीज़ आते हैं, उनके लिए 29 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से 3 जनवरी को देवघर से गुवाहाटी तक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में जनरल मैनेजर एनएफ रेलवे से भी एक प्रपोजल आया हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I rise to bring your attention the alarming surge in violence and abuse against children in our country. It is disheartening to see that the recent data of National Crime Records Bureau paints a grim picture of the vulnerability of our children.

According to NCRB data, the situation reveals a distressing reality with staggering 409 crimes against children every day. Crimes against children are majorly dominated by two heads – kidnapping and abduction, accounting for 45 per cent of cases and the Protection of Children from Sexual Offences (POSCO) Act, 2012 cases accounting for 39.7 per cent, which includes child rape.

In this situation, I urgently call upon the Government to take swift and decisive action to enforce the existing laws rigorously, expedite the rapid solution of cases and advocate for immediate legislative measures which aim at introducing child-friendly methods for evidence gathering.

Additionally, it is imperative to conduct extensive capacity building and sensitisation programmes by law enforcement agencies to ensure that they can promptly and effectively handle the cases related to crimes against children.

Lastly, I would request for establishment of comprehensive rehabilitation programmes including the provision of dedicated psychologists to aid in the recovery and well-being of affected children. Thank you.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने पूरे भारत वर्ष में रेलों का जाल बिछवाया है और पिछले दिनों नौ 'वंदे भारत' का उद्घाटन किया। मेरे संसदीय क्षेत्र में पांच अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं और स्टॉपेज भी मिले हैं। मेरा इलाका हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हरियाणा को बने 57 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा संसदीय क्षेत्र राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ा नहीं है।

(1315/KDS/RP)

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि सिरसा, फतेहाबाद और नरवाना विधान सभा को चंडीगढ़, जो हमारी राजधानी है, उससे जोड़ा जाए। टोहाना में श्रीगंगानगर से लेकर दिल्ली तक की जो इंटरसिटी है, उसके लिए बार-बार मेरे संसदीय क्षेत्र से मांग आती रहती है। अत: वहां पर यदि इंटरसिटी का स्टॉपेज मिलेगा, तो बहुत मेहरबानी होगी।

महोदय, ऐलनाबाद से लेकर सिरसा तक एक छोटा-सा टुकड़ा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि अगर वहां पर नई रेल लाइन बन जाती है, तो मेरे इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I would like to bring to the notice of the Central Government the issue of farmers and the drought situation in the State of Andhra Pradesh. As expected, the drought came because there was 25 per cent less rainfall in the Kharif Season. It is not just the natural side of the calamity but this is also a manmade calamity. It is because of the inefficiency, incapability, and irresponsibility of the State Government which has not looked after the situation of the farmers.

Sir, regarding drought, if you look at the season that has just happened, the State Government was supposed to complete a lot of projects in the last four and a half years but not a single project has been completed. Also, the canal system has not been properly maintained. If you go into the State, you cannot even find any canal system right now. The canals are completely covered with silt and greenery. So, in this situation, farmers have not sown in 25 lakh acres of land because of the inability of the State Government.

Secondly, whenever there was drought during the former Chief Minister Nara Chandrababu Naidu's time, he used to use technology like sprinklers, drip irrigation, and also rain guns to wet the crops in that critical time. If the present Government had used these kinds of systems, they could have saved the crops. But, none of these kinds of systems have been utilised by the State Government. One of the important points is that no report has been prepared with respect to

the drought situation. Even though more than 50 per cent of the area in the State including 650 Mandals has been affected by drought only 100 Mandals have been put in the list of drought affected areas. I know this fact because my constituency Ichchapuram has received 60 per cent less rainfall. Areas like Sompeta, Palasa, Vajrapu Kotturu, and Kaviti have been affected by drought but they are not listed in the drought affected areas list. If this is the kind of attitude, then the farmers would not get any input subsidy; they would not get any insurance; and they would not get any incentive for the next Rabi Crop. The situation is so bad that the State Government is now telling the farmers: "Do not even sow any Rabi crop." If this is the situation, how is the farmer going to come out of this crisis? On top of this, some farmers are fortunate enough to save their crops but, now, the Gods have been angered again and they have been affected by Michaung Cyclone. Whatever little crop is ready for harvest, it has been submerged and damaged. Whatever crop was harvested, even that has been damaged because of lack of storage.

So, I request the Central Government to send proper teams which can make good assessment of the loss of the farmers and then provide assistance of Rs. 5000 crore for the State of Andhra Pradesh immediately.

Thank you, Sir.

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। हावड़ा मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां की तकलीफ के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। साउथ हावड़ा के बक्सारा में लोग इधर से उधर जा नहीं सकते हैं। संतरागाछी में ट्रेन एक-एक घंटा खड़ी रहती है। कोविड काल में वहां एम्बुलेंस खड़ी रहने के कारण करीब दो सौ आदमी मर गए। अत: मेरी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनती है कि जल्दी से जल्दी वहां एक अंडरपास का निर्माण कराया जाए। वहां अंडरपास की सख्त जरूरत है। धन्यवाद।

(1320/MK/NKL)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललितग्राम से फारबिसगंज रेल खंड का सीआरएस इंस्पेक्शन दिनांक 11.01.2023 को ही हो चुका है, किन्तु उक्त खंड पर अभी तक रेल परिचालन प्रारंभ नहीं किया गया है। फलस्वरूप, बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है। जोगबनी से दानापुर तथा जोगबनी से सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा टाइम टेबल भी निर्गत किया गया है, किन्तु अभी तक इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। साथ ही राजरानी ट्रेन नं. 12567/ 12568 पटना सहरसा का विस्तार सरायगढ़ या सुपौल तक किया जाए अथवा कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सरायगढ़ या सुपौल से

पटना तक प्रतिदिन किया जाए। इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कई बार ट्रेन चलाने का आग्रह किया है, किन्तु अभी तक यह नहीं हो पाया है।

आज मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों का परिचालन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, हर रोज देश भर में लाखों डिपॉजिटर्स के करोड़ों रुपये कैसे लूटे जा रहे हैं, इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के कुछ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में देकर बताना चाहता हूं, जो लोगों के कम से कम 2 हजार करोड़ रुपये के डिपॉजिट्स को लेकर फरार हो गईं। आदर्श नागरी पतसंस्था में 62 हजार डिपॉजिटर्स हैं। रुकमणि, यशस्वीनी और नैनोबा सोसाइटी में जो 80 परसेंट डिपॉजिटर्स हैं, वे एक्स आर्मीमैन हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स के अंदर लगाया। देवलई महिला, मलकापुर अर्बन, अमरावती की अनुग्रह, मुम्बई की नागरी पतसंस्था, ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपये लिए गए हैं।

सभापति महोदय, न तो आरबीआई का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है न को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। आदर्श नागरी पतसंस्था, औरंगाबाद मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है। वहां 62 हजार डिपॉजिटर्स हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, जिनकी जिंदगी भर की कमाई दो लाख रुपये है। उन्होंने दो लाख रुपये सिर्फ इस वजह से उस संस्था के अंदर लगाये, क्योंकि वहां पर इंट्रेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। यह लालच दिखा कर लोगों के पीएफ का पैसा लिया जाता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट का पैसा लिया जाता है। वे इनिशियली तो उन्हें पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में फरार हो जाते हैं।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आरबीआई को फौरन इस तरह की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश देना चाहिए कि छ: महीने के अंदर उनका पैसा वापस मिलना चाहिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, hon. Chairman Sir, for giving me this opportunity.

A large number of pilgrims from Odisha visit Deoghar, which is also known as Baidyanath Dham, an important Hindu pilgrimage site. It is one of the twelve Jyotirlinga sites of Hinduism which is famous for the *mela* of Shrawan. Along with Srisailam, it is one of the few places in India where the Jyotirlinga and the Shaktipeeth are lying together side by side. In Bhubaneswar, we have Harihara, the famous Lingaraja temple. A large number of devotees also visit Baidyanath Dham via Kolkata.

As has already been mentioned, there has been a long-pending demand from the devotees of Thakur Anukulchandra regarding layover of Bhubaneswar-Patna flight at Deoghar. I would urge upon the Government to take immediate

necessary steps for layover of Bhubaneswar-Patna flight at Deoghar Airport without further delay in the interest of public at large. Thank you.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में हो रही वृद्धि की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरूआत की थी, जिसके माध्यम से अब तक 9 करोड़ 60 लाख परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रह रहीं महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की देन है कि आज देश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी उपयोगकर्ता की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु, सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में आज बिहार सहित पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, जो चिंता की बात है।

(1325/SJN/MMN)

कई बार गैस कंपनियों या डीलरों द्वारा एक्सपायरी डेट पार कर चुके सिलेंडरों की भी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जिसके बारे में अधिकतर ग्राहकों को पता ही नहीं होता है। गैस लीकेज के कारण आए दिन कहीं न कहीं सिलेंडर विस्फोट की सूचना मिलती ही रहती है। अभी हाल ही में बिहार के चंपारण क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में लगभग 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिनमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी।

यह भी देखा गया है कि ऐसी घटनाओं के बाद जिम्मेदार कंपनी या डीलर द्वारा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में भी काफी देर की जाती है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि देश में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम के लिए ठोस उपाए किए जाएं। इसके साथ ही एलपीजी सुरक्षात्मक उपयोग के बारे में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कंपनियों तथा डीलरों द्वारा समय-समय पर जागरुकता अभियान भी सुनिश्चित कराया जाए।

*DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam, Thank you for this opportunity. In my Krishnagiri parliamentary constituency, as many as 15000 people belonging to Banjara Lambadi community live in places like Kachwadi, Kundalam, Paalegu, Anjetti and Virugam, As many as 2 lakh people of this Lambadi community live in Dharmapuri, Tiruvannamalai and Salem districts of Tamil Nadu. They are mostly tribal people. They are earning their livelihood working as daily wagers or unskilled labourers. They are very much suffering as they do not have proper housing, drinking water and road facilities. Children in these Lambadi communities study only upto 5th or 6th

* Original in Tamil

Standard or upto a maximum of 10th Standard. Then they become dropouts. Degree holders are very less in number from this community. Less than 100 persons from this community may be in government jobs. In Tamil Nadu the people belonging to this Banjara Lambadi are considered as those of Backward caste. At the same time. they are listed as SC in Karnataka and ST in Andhra Pradesh. I urge upon the Union Government through you Sir that this Banjara Lambadi community people should be included in the ST List as against the present list of BC in Tamil Nadu in order to uplift them economically in the society by way of providing them their livelihood. Thank you Sir.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अयोध्या धाम विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल व धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षण का केन्द्र बनने जा रहा है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से ग्वालियर से सीधे अयोध्या के लिए ट्रेन सुविधा हेतु आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में ग्वालियर से अयोध्या के लिए एकमात्र साप्ताहिक ट्रेन मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस है, किंतु वर्तमान में यह सुविधा अपर्याप्त है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्वालियर-बरौनी मेल ग्वालियर से चलकर बाराबंकी जंक्शन होते हुए बुढ़वल-कर्नलगंज-गोंडा होते हुए मनकापुर पहुंचती है। इस लाइन पर अन्य गाड़ियां भी चलती हैं।

यदि उक्त ग्वालियर-बरौनी मेल को बाराबंकी से अयोध्या होते हुए मनकापुर पहुंचने का रूट कर देते हैं, तो ग्वालियर, डबरा, दतिया एवं झांसी सहित संपूर्ण चंबल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम पहुंचने के लिए एक अच्छा साधन मिल सकेगा।

दूसरा, झांसी से अयोध्या के लिए जाने वाली गाड़ियां क्रमशः अहमदाबाद-दरभंगा, साबरमती एक्सप्रेस, यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस, मुंबई एलटीटी-छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस, अहमदाबाद-वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस वाया कानपुर होकर अयोध्या से गुजरती है। यदि इनमें से कुछ ट्रेनों को झांसी से वाया ग्वालियर, भिंड, इटावा, कानपुर होकर चलाया जाए, तो ग्वालियर अंचल व इसके आस-पास के यात्रियों को अयोध्या के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी ट्रेन सुविधा में बढ़ोतरी हो सकेगी।

महोदय, मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्वालियर लोक सभा क्षेत्रवासियों को अयोध्या के लिए रेल सुविधा प्रदान कर अनुगृहित करने की कृपा करें।

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you hon. Chairman Sir, I would like to raise a very serious problem of my Arambagh Lok Sabha constituency, which I have been raising in this august House for the last ten years. In this area, flooding is a major problem whenever there is even slightest rainfall. Khanakul is such an area which is very easily flooded if there is rain because when the water of Mundeswari river reaches Rupnarayan river, the water immediately flows back and the villages are completely submerged. So when Khanakul Block 1 and Block 2 are flooded, the entire area becomes disconnected. There is a bamboo bridge over Mundeswari to connect Natibpur and Ganeshpur. Several times the Central government has been requested to address this issue but so far, nothing has been done. If this bridge is strengthened it will serve as a nice connection between Howrah and Hooghly. Along with that, Khanakul Blocks 1 and 2 will also be connected. Moreover, another bridge to join Khanakul and West Midnapore, the Garer Ghat bridge, which is over Rupnarayan river is also very important. These two bridges are urgently needed. These bridges will prove to be highly beneficial to the people of my Khanakul and Arambagh parliamentary constituency; the common people or the farmers of the region who have to travel to Howrah or West Midnapore for various purposes regularly will get the advantage. So through you Sir I request Hon. Irrigation Minister of Central government to immediately take up the project without further delay. Thank you Sir.

(1330/SPS/VR)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और आप स्वयं अवगत हैं कि सिद्धार्थनगर और नेपाल की उस तराई में जहां भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, जब बुद्ध जी थे, तो बुद्ध के प्रसाद के रूप में वहां काला नमक चावल दिया करते थे। आज वह काला नमक चावल देश और दुनिया के बाजारों में जिस तरह से बुद्ध के प्रसाद के रूप में गया है, उससे उसकी मांग बढ़ी। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' में भी शामिल कर दिया है। आप स्वयं काला नमक चावल के बारे में जानते हैं। जल संसाधन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी मेरी कॉन्स्टीट्यूवेंसी में गए थे। इन्होंने वहां काला नमक चावल के बारे में किसानों से सुना और वह 2700 हेक्टेयर बढ़कर 15000 हेक्टेयर हो गया, जिओ टैग हो गया और वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट हो रहा है। वह निर्यात हो रहा था, लेकिन अभी

---

* Original in Bengali

बासमती को छोड़कर काला नमक चावल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां के किसान ऋण ले रहे थे। वहां के किसानों के पास सिंगापुर का ऑर्डर होगा, यूरोपियन ऑर्डर होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि काला नमक चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध को समाप्त किया जाए, जिससे सिद्धार्थनगर के किसानों को एक नया जीवन मिल सके और वे उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियर डॉलर इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, Sir. Today, I want to bring forth the plea of anganwadi workers in India, an initiative under ICDS by the Indian Government, where women as frontline workers are providing essential services of additional and supplementary healthcare, and nutritional services including community-level immunization to children and pregnant women. They are the ones who drove the vaccination drive in thousands of villages of the country as frontline workers during the pandemic.

Yet they struggle with low financial support provided to them which is referred to as either an honorarium or required incentive for their contribution. The financial support provided to them is meagre and is even less than the wages of a Grade-IV government servant. Sir, in the absence of these anganwadi workers, it would be almost impossible for such a big country as India to provide essential primary healthcare services to children and women at the grassroots level.

The Government has taken advantage of more than 24 lakh anganwadi workers, their hard work and is yet giving them duties related to elections and surveys thereby adding more to their existing burden of work. Time and again the anganwadi workers went to the court demanding social security benefits, facilities, increased wages, gratuity, post-retirement benefits and many more but with no tangible results.

Therefore, I request the Government to change the nomenclature of the compensation category of anganwadi workers from 'honorarium' to 'salary' and provide requisite resultant benefits to them. Thank you very much, Sir.

श्री मलूक नागर (बिजनौर) : सर, गन्ने के किसान बहुत परेशान हैं। मेरे क्षेत्र और आपके क्षेत्र, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में गन्ने के बहुत किसान हैं। अगर हम पिछले सात साल में देखें तो एक बार दस रुपये का रेट बढ़ा है और दूसरी बार 25 रुपये रेट बढ़ा है, जबकि सात साल की सरकार की बढ़ी हुई महंगाई मानें तो कभी 8 पॉइंट कुछ परसेंट, कभी 7 पॉइंट कुछ परसेंट, कभी 9 परसेंट तो इस हिसाब से 60 परसेंट बैठती है, जो करीब 300 रुपये है। मैं गन्ने का रेट कम से कम 550 रुपये बढ़ाने की मांग करता हूं।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र में सोजत मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। यहां की मेहंदी का अनोखा रंग इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है और यह विशेष रंगद्रव्य इस क्षेत्र की मिट्टी एवं विशेष जलवायु से मिलता है। सोजत की मेहंदी के उद्योग में 160 से अधिक फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और यही इनकी जीवन रेखा है। सोजत के साथ जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, बिलाड़ा क्षेत्र में भी मेहंदी की खेती होती है। यहां के लोगों ने सोजत को मेहंदी नगर बनाने हेतु बहुत मेहनत की, जिसका बाजार एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है।

महोदय, हमारे सोजत की मेहंदी को जीआई टैग का हक देने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनकी बदौलत यहां के उद्योग को एक और नई उड़ान मिलेगी।

(1335/MM/SAN)

महोदय, सोजत मेहंदी उद्योग एक बढ़ता हुआ उद्योग है और पिछले वर्ष में तेजी से बढ़ा।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप अपनी मांग रखिए।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): जीआई टैग प्राप्त होने के बाद इस उद्योग में कार्यरत लोगों की संख्या में बहुत बढ़त हुई है और बढ़ रही है। यहां के हजारों श्रमिकों के इलाज एवं सुरक्षा हेतु कोई इम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अस्पताल नहीं है। यहां पर ईएसआईएस और ईएसआईसी का कोई भी अस्पताल नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सौजत में एक ईएसआईएस और ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना की जाए।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Sadashiv Kisan Lokhande	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Mahabali Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Vinayak Bhaurao Raut Shri Arvind Sawant Shri Om Pavan Rajenimbalkar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Arvind Sawant

	Shri Vinayak Bhaurao Raut Shri Rajan Baburao Vichare
Shri Rajan Baburao Vichare	Shri Arvind Sawant Shri Vinayak Bhaurao Raut Shri Om Pavan Rajenimbalkar Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. S.T. Hasan	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri K. Muraleedharan	Dr. Shashi Tharoor Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri N.K. Premachandran	Dr. Shashi Tharoor Shri Malook Nagar Shri Syed Imtiaz Jaleels Shrimati Navneet Ravi Rana Shrimati Supriya Sadanand Sule Adv. Adoor Prakash Shri S.S. Palanimanickam Shri K. Muraleedharan Shri M.K. Raghavan Dr. Pon Gautham Sigamani Adv. Dean Kuriakose Shri Benny Behanan Shri Thomas Chazhikadan Shri Om Pavan Rajenimbalkar Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu Shri Shrirang Appa Barne DR. DNV Senthilkumar S. Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Dharambir Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ashok Kumar Rawat	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bidyut Baran Mahato	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra

Shri S.R. Parthiban	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Manoj Tiwari	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Kuldeep Rai Sharma	Shri Malook Nagar
Shri Rajiv Pratap Rudy	Shri S.S. Ahluwalia Shri Ram Kripal Yadav Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary Shri Sudheer Gupta
Dr. Sujay Vikhe Patil	Shri Shrirang Appa Barne Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vincent H. Pala	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Shashi Tharoor	DR. DNV Senthilkumar S. Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sanjay Seth	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Sudheer Gupta
Shri Nihal Chand Chouhan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Girish Chandra	Shri Malook Nagar
Shrimati Preneet Kaur	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Hemamalini	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shri Ram Kripal Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Pramila Bisoyi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri S.S. Ahluwalia	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Navneet Ravi Rana	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

	Shri Malook Nagar
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	DR. DNV Senthilkumar S. Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Adv. Dean Kuriakose	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Benny Behanan	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Kaushlendra Kumar	Shri N.K. Premachandran
Shrimati Rama Devi	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jagdambika Pal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Malook Nagar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri P. P. Chaudhary	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dilip Saikia	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Sushri Sunita Duggal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Syed Imtiaz Jaleels	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Bhartruhari Mahtab	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajmohan Unnithan	DR. DNV Senthilkumar S.
Dr.A. Chellakumar	DR. DNV Senthilkumar S.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): सभा की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1335 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चौदह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1430/YSH/SNT)

1433 hours

The Lok Sabha re-assembled at thirty-three minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Construction of pit line at Latur Railway station, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): जनता की मांग पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। महोदय, लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से कई गुणा बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइन के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए यहां से आवश्यक नई रेल शुरू करना संभव हो जाएगा। मैं सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का आबंटन का प्रावधान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

(इति)

Re: Opening of Agriculture Universities at Majhi and Bhagwanpur Haat Krishi Vigyan Kendras in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा बिहार एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सारण छपरा जिला के मांझी एवं सिवान जिला के भगवानपुरहाट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा स्थापित एक-एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि बावली क्षेत्र होने के नाते यहां के किसान एवं जनता की इच्छा होती है कि आज की आधुनिक युग में अपने बच्चों को कृषि से संबंधित शिक्षा दिलवाई जाए जिससे कि उनके बच्चे कृषि के क्षेत्र में ही अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हुए किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि उपर्युक्त दोनों कृषि विज्ञान केदो में कृषि महाविद्यालय खुलवाया जाए। इन केन्द्रों के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। अतः महोदय के माध्यम से माननीय कृषि कल्याण मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मांझी और भगवानपुर हाट में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों में एक-एक कृषि महाविद्यालय खुलवाया जाए।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Bihta – Aurangabad railway line and extension of the railway line upto Hazaribagh in Jharkhand

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): पूर्व मध्य रेल के अन्तर्गत बिहटा – औरंगाबाद नई रेल परियोजना स्वीकृत है परियोजना का कार्य 2011 -12 में पूरा होना था। परियोजना के क्रियान्वयन मे विलम्ब होने से प्राक्कलन राशि 326 करोड़ रूपये से बढ़कर 2800 करोड़ रूपये हो गई। इस मामले को मैंने पहले भी कई बार सदन मे उठाया लेकिन सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए राशि आवंटन मे बिलम्ब से परियोजना का कार्य लंबित है। मेरी मांग है कि इस परियोजना का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो तथा औरंगाबाद, अम्बा, देव, डुमरिया,इमामगंज एवं चतरा होते हुए हजारीबाग तक इस रेल लाइन का विस्तार किया जाए जिससे बिहार और झारखंड राज्यों के आधा दर्जन उग्रवाद प्रभावित और आकांक्षी जिले बेहतर रेल संपर्क से जुड़ सकें और इस पिछड़े इलाके मे बढ़ती आवादी की जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए और विकास की गति को त्वरित करने हेतु सरकार परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करें|

(इति)

Re: Land erosion caused by rivers in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र माल्दहा उत्तर (पश्चिम बंगाल) के रतुवा वन ब्लॉक महानंदा टोला जीपी में अधिकतर ग्रामों की काफी गंभीर स्थिति है ये गाँव कभी भी नदी में समाहित हो सकते हैं जिन्हें बचाना नितांत आवश्यक है। इसी तरह श्रीकांत टोला, मुनिरामटोला जीतू टोला वीरूटोला छवि टोला खासबोर्ना, नयाभिलाइमारी, बोधराम टोला, पोटोलडांगा इन सभी गाँव में लगभग 3000 घर हैं एवं 18 प्राइमरी स्कूल और 2 हाई स्कूल और दो बड़ी मार्किट हैं, 5 फल्ड सेन्टर हैं तथा मिलाईमारी जीपी रामायणपुर, रूहिमारी, दारोग टोला, गंगाराम टोला इन ग्रामों में लगभग 1500 घर है तथा 8 प्राइमरी पाठशाला एवं एक हाई स्कूल 2 फल्ड सेन्टर है और एक बड़ा बाजार भी है। हरिशचंद्रपुर ब्लॉक दो में उत्तर भकुरिया, दक्षिण भाकुरिया, रसीदपुर ग्राम कावाडोल, मिरापारा तातीपारा आदि ग्रामों की काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार इस मामले पर विचार नहीं कर रही है नदियों के कटान से तत्काल प्रभाव से बचाना अति आवश्यक है। (इति)

Re: Enactment of a Uniform Civil Code in the country

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): हमारे सविंधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना की थी, देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश और समाज को सैकड़ो जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी और अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानूनों से न्याय पालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसके साथ देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी एवं राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कानून के समर्थक थे। हाल ही में दिल्ली एंव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की है।महोदय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है, और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है। (इति)

Re: Need to pay maturity amount to the farmers and labourers of West Singbhum district, Jharkhand under Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): केंद्र सरकार द्वारा सीमांत किसान एवं मजदूरो के आर्थिक लाभ एवं उनका जीवन सुधारने के उदेश्य से एक महत्वकांक्षी योजना कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना LIC के माध्यम से चलाई गई थी। इस योजना में किसान एवं श्रमिकों का 1 रुपया प्रति दिन तथा 2 रुपया केंद्र सरकार की ओर से बीमा के रूप में दिया जाना था जिसमे पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत नोवामुंडी ब्लॉक के क्षेत्र में सूचीबद्ध कर योजना चलाई गई थी। योजना के तहत 2002 में 750 सदस्यों से 1 रुपया प्रतिदिन अंशदान के रूप में वर्ष 2012 तक लिया गया। वर्ष 2012 में प्रिमियम लेना बंद कर दिया गया तथा योजना बंद होने के बाद कई समूहों को 10 साल के maturity Amount का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। 11 समूह का भुगतान अब तक नहीं किया गया। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि पश्चिम सिंहभूम के नोवामुंडी ब्लॉक आसपास के कृषक एवं श्रमिक समूह के साथ राज्य एवं अन्य राज्य में इस योजना के लाभार्थियों को शीघ्र Maturity Amount भुगतान किया जाए जिससे इस योजना के उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। (इति)

Re: Stoppage of trains at Bommidi and Morappur stations in Tamil Nadu

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): I write to you with a collective request regarding train stoppages at Bommidi (BQI) & Morappur stations, requested by the people of my constituency. My constituency residents mainly rely on railway network for their daily commute & significant engagements. Scheduled stoppages at these stations would not only immensely benefit the local populace but also stimulate economic growth & enhance overall connectivity. Despite our previous communications with the O/o Hon'ble Minister of Railways & DRM these appeals remain unaddressed. For clarity & prompt action, I list the trains for which stoppages are required. Sl No. Train No/Name Required Stoppage 1 02675/02676 MAS-CBE-MAS Exp Bommidi RS (BQI) 2 16525/16526 SBC Exp Bommidi RS (BQI) 3 12695/12696 MAS-TVC-MAS Bommidi RS (BQI) 4 22616 CBE-TPTY Exp Bommidi RS (BQI) Also I am placing a new request for Vande Bharat Exp (20644 MAS-CBE-MAS) stopping at Morappur for a brief 2-minute halt. Notably, the requested stoppage of Vande Bharat Express at Morappur stands crucial as it is the only potential stop in Dharmapuri District, offering considerable relief & convenience to its residents. I am optimistic that these modifications if granted will resonate positively with the public & reaffirm our commitment to their welfare. I thank you for your diligent attention to this combined appeal. We ardently await a favourable action.

(ends)

Re: Merger of primary and upper primary schools with the nearby high schools in Andhra Pradesh under New Education Policy

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the kind attention of the House to the Government of India New Education Policy to merge the primary and upper primary schools with the nearby high schools in the radius of 3 km. These guidelines are creating some implementational problems in the country.

For example, as per the guidelines, AP Government has mapped nearly 5919 schools for this merger. Due to increasing distance of the school due to this merger of schools, parents are finding problems in joining their children in faraway schools. Nearly, 11 lakhs students refrained from taking admissions because of irrational merger of schools. There is an apprehension that the merger decision will certainly increase the dropout rate of the students, particularly from SC, ST, BC, Minority Communities and girl students from rural areas.

Taking these guidelines, AP Government is trying to reduce the number of schools and teachers in schools along with doing away with the Telugu Medium from Class-1 to Class-VIII.

The Andhra Pradesh High Court prima facie found fault with the rationalisation of merging schools. The High Court observed that the GO 117 issued by the State Government is in violation of the provisions of the Right to Education Act (RTE Act).

Keeping in view of all the above, I urge upon the Government of India to intervene in the matter of implementation of NEP without creating any problems to the students in the name of merger of schools that will increase the dropout ratio.

(ends)

Re: Need to issue strong guidelines for curbing online financial frauds

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): The recent survey by FCRF, IIT Kanpur found that 23,000 crimes happen a day and nearly 1,000 crimes an hour. Online financial fraud has accounted for 77.4% of the cybercrimes from January 2020 to June 2023. Recently a young employee from automobile company demanded a home loan from his Bank and was shocked to know that he was not eligible as he had poor CIBIL score. The bank told him that he had already taken loans worth Rs.5 lakh from various private banks and financial institutions. Fraudsters used his PAN details and his bank customer identification number to secure these loans. Fraudsters allegedly took out several financial details and transactions through CIBIL report. Surprisingly, he never got intimation from any source regarding payment of loan instalments. The police suspect fraudsters accessed victim's PAN card and bank identification number from the support documents and replaced someone else's photo and availed loans. Due to this innocent people opting for PM Central Government Schemes of small loans are deprived of benefits. We need a strong law to tackle these frauds and punish these criminals as they dupe hard earned money of innocent people. Hence, I urge upon the Minister of Finance to issue strong guidelines on the matter.

(ends)

Re: Need to expedite construction of Maheshkunt – Saharsa – Purnia Highway (NH-107) and other incomplete projects

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य के NH-107 महेशखूँट-सहरसा-पूर्णियाँ पथ का निर्माण कार्य वर्ष-2018 में शुरू हुआ था। एजेन्सी को दो साल में कार्य पूर्ण करना था, लेकिन धीमी गति से कार्य चलने के कारण लगता है कि कार्य पूर्ण होने में कई साल और लगेगा। मुख्यालय द्वारा समीक्षा में कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 2022 फिर वर्ष-2023 तय की गयी। सोनवर्षा राज एवं बैजनाथपुर अन्डर-पास पुल का निर्माण दो साल पूर्व करा दिया गया है, लेकिन अब तक एप्रोच का कार्य शुरू नहीं किया गया है। सिमरी-बख्तियारपुर, सहरसा (सर्वाढ़ाला) एवं मिठाई में ROB निर्माण शुरू नहीं किया गया है। सिमरी-बख्तियारपुर सोनवर्षा राज, सहरसा एवं मिठाई में बाईपास में आंशिक कार्य कर छोड़ दिया गया है। पथ निर्माण नहीं होने से आम लोग परेशान है।

अतः माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह है कि कार्य में शिथिलता बरतने वाले एजेन्सी पर कार्यवाही करते हुए जनहित में उक्त पथ का निर्माण शीघ्र पूरा करा दें।

(इति)

Re: Need to fill up vacant government posts under Union and Uttar Pradesh Governments

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) ओ.बी.सी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बीच बेरोजगारी का मुद्दा एक गहरी चिंता का विषय है और इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एससी और एसटी (एसटी) ओ.बी.सी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के समुदायों के बीच बेरोजगारी की लगातार उच्च दरें एक समावेशी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हैं जिसे हम अब हल करना चाहते हैं।अगर हम पूर्व में देखें तो उत्तर-प्रदेश में 2007-2012 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लाखों रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्तियों का आयोजन किया था ताकि सभी को एक न्यायपूर्ण एवं सम्मानित जीवन जीने का मौका मिल सके। इसलिए, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि केंद्र सरकार और उत्तर-प्रदेश सरकार में एससी एसटी ओबीसी एवं EWS के लिये 2022 -2023 तक कितने स्थायी रोज़गार मिले हैं, कितने पद रिक्त हैं, और अब तक कितने रोज़गार के लिये विज्ञापन निकाले गए हैं, और सरकार इसमें क्यों देरी कर रही है क्योंकि अन्य राज्यों में सरकारी रिक्त पदों को तत्परता से भरा जा रहा है, किन्तु उत्तर-प्रदेश में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अतः मेरी जानकारी में केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करोडो पद रिक्त हैं, जिन्हें विशेष-अभियान चलाकर नौजवानों को स्थायी रोजगार प्रदान करने का कष्ट करे। (इति)

Re: Fixing of Minimum Support Price (MSP) for rubber at Rs. 250/per kg

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): I want raise the issues faced by farmers. Rubber producers in Kerala do not get adequate price for their product vis-à-vis cost production. Several times in the past, I had raised the issue of declaring rubber an agricultural produce. Raw Jute which is similar to natural rubber, is a agricultural product which is used for industrial purposes and jute growers are getting Minimum Support Price as declared by the Union Government. In the same manner, natural rubber should also be declared as an agricultural produce which will benefit around 10 lakhs rubber growers. As per the MS Swaminathan Commission Report, the rubber should get at least 1.5 times of the cost of production. The cost of production per kg is 172 Rs/kg, however, the rubber growers are getting below 100 Rs/kg. I urge upon the Government to fix the Minimum Support Price of rubber at Rs 250/kg.

(ends)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक – जारी

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन): आइटम नम्बर 10, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023.

श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

1434 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति जी, मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे बोलने का पूरा समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आपसे उसे पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं कल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था, जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है। मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो हम देखें अक्तूबर 2014, 2015, 2016, 2018 और 2023 में माननीय प्रधान मंत्री जी का एम्स में कन्वोकेशन एड्रेस था। जम्मू में शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में एड्रेस था, पीजीआई के मेडिकल कॉलेज में एड्रेस था। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी सिंधिया स्कूल में गए थे, वहां पर एड्रेस था। वर्ष 2016 में कटरा में कन्वोकेशन एड्रेस था तथा माननीय प्रधान मंत्री जी आईआईटी मुम्बई में भी गए थे, वहां पर भी कन्वोकेशन एड्रेस था।

(1435/RAJ/AK)

मुझे लगता है कि उन सभी विषयों को पढ़ लिया जाए, तो शिक्षा जगत की सोच की क्या प्रणाली होनी चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधान मंत्री जी ने इन कनवोकेशंस में कहा है। मैं वहीं से प्रेरणा लेकर बात आगे बढ़ाऊंगा।

जब कल मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था, तो सभापति महोदय मैंने कहा था, आखिर में, मैंने बिहार के बारे में चर्चा संदर्भित करते हुए बताया था कि वहां सेशन लेट है और आज अधिकांश बच्चे कोचिंग-इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। आज साढ़े सात लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरे हुए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं। अगर डिग्री की बाध्यता न हो, तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से ही परीक्षा देकर पास कर जाएं, लेकिन बाध्यता के कारण यह नहीं होता है। हमारे यहां एग्जामिनेशन कंट्रोलर का सिस्टम है। एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाले होते हैं और पढ़ाने वाले भी उसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिले होता है।

मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों की परीक्षा अलग होती है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को शिक्षा से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ताकि उसकी डेट निर्धारित हो और वे परीक्षा लें। बच्चे वहां पहुंचें। यूनिवर्सिटीज की जिम्मेवारी हो कि वे उनको पढ़ा कर भेजें। यह एक प्रस्ताव था। मैं अपने प्रस्ताव के साथ-साथ अपने विषय में आगे बढ़ूंगा।

महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बनाने जा रहे हैं। मैं इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं। शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है, मैं कभी वहां गया था, तो देख कर आया हूं। A Member of Parliament in this House has a college. जिसमें 80 हजार ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी क्लास से लेकर 80 हजार बच्चे

बढ़ते हैं। वहां उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। वहां उनके खाने और कपड़े की व्यवस्था है। हमारे एक माननीय सांसद अच्युतानंद जी है, जो इनके भी मित्र हैं। उसके पीछे चाहे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन इस देश में 80 हजार बच्चों को एक व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा एक व्यवसाय है। इस सदन में तो नहीं, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) वैसे-वैसे भी लोग आए, जिन्होंने शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपए कमाए। मैं उन पोलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वे माननीय सदस्य हैं। इस देश में वैसे भी लोग हैं, जो शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वे … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) में पहुंचे हैं, उसका कारण स्पष्ट है।…(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आप राज्य का नाम ले सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): वे पंजाब से हों, दिल्ली से हों, उसमें कई लोग जेल चले गए। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं। जो आज … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) में पहुंचे हैं। हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे।…(व्यवधान) जिस राज्य में वह यूनिवर्सिटी है?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आप उस राज्य का नाम ले सकते हैं, जिस राज्य में वह यूनिवर्सिटी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): वह ओडिशा में है। उस व्यक्ति और उस राज्य का भी उसमें जरूर श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80 हजार बच्चों को पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय है। अगर आपको मंदिर देखना है, तो वह विश्वविद्यालय जा कर देखिए, जहां गरीब, छोटे-छोटे बच्चे अपने कपड़े भी ठीक से पहन नहीं पाते हैं, वहां वैसे 80 हजार बच्चे नि:शुल्क पढ़ते हैं। खाना खिलाना और कपड़े देने की भी वहां व्यवस्था है। वे इस सदन के माननीय सदस्य हैं। वे दिखते भी नहीं है और बोलते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। औपचारिक शिक्षा के बारे में यूनिवर्सिटी में बात होती है। आप बिहार की शिक्षा के हालात के बारे में जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर, दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वह इशिता हो या गरिमा हो, वे दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट हैं, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है। मैंने आपको दो उदाहरण दे दिए कि आखिर में किस प्रकार से होता है?

महोदय, आज भारत की सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी ने एनईपी के तहत एक बड़ी नीति लाई है। उन्होंने उसे एंडोमेंट कहा। अगर हम इसे हिंदी में कहे तो चंदा होता है। अगर आप देखना चाहे कि इस देश में आज की तारीख में बड़े विश्वविद्यालय को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। जब से यह नीति लागू हुई है, तब से आईआईएम, दिल्ली, मुंबई-दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट आया, वे 160 करोड़ रुपए हैं। मैं दुनिया के वैसे संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा, जहां बच्चे पढ़ कर इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 50 बिलियन यूएस डालर, लगभग चार हजार करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी, उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं।

(1440/KN/UB)

टेक्सास यूनिवर्सिटी, युनाइटेड स्टेट्स – 42 बिलियन यूएस डॉलर, वहां से पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए देते हैं। They gave 41 billion US dollars as an endowment to the university they have passed out from. Look at the number of 36 billion US dollars. हमारी भी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश की शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। भारत में भी एक और चीज हो रही है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। लेकिन हम लोगों ने टॉप-हेवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यह प्रेरणा रहती है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा दें। दुनिया में 10 प्रतिशत लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी अंडर ग्रेजुएशन करते हैं। हम लोग जो भी शिक्षा की नीति बनाते हैं, यह मूलत: इसलिए बनाई जाती है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े और वही आधार होता है। एक से दो प्रतिशत लोग अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयेबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? अगर हम देश की परीक्षा को देखें, आज अगर मेरिट की बात हो, तो कायदे से पहले एक समय होता था कि परीक्षा की डिग्री लेकर जाइये और मार्क्स पर नौकरी ले लीजिए। उसे खत्म किया गया, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी और उसी का परिणाम है कि आपने केन्द्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू कीं, राज्य की परीक्षा सेवाएं शुरू कीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम हों, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70-80 प्रतिशत वे कैंडीडेट्स हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छी होती है, वहां रोजगार अच्छा मिलता है। उसका जीता-जागता परिणाम है कि देश के 50 से 60 प्रतिशत यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास होते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को, अगर हम दूसरे रूप से देखें, क्योंकि हम लोग भारत में विश्वविद्यालय खोलते हैं, भारत के विश्वविद्यालय में तैयारी करवाते हैं, भारत के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसका हमें निश्चित रूप से निदान निकालना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के बारे में देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? आपने मुझे बोलने के लिए समय कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप यह होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े-लिखे लोग भी नहीं करते हैं, अगर शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, तो उससे बड़ी शिक्षा धरती पर कोई नहीं होती है।

इन चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए। यह मेरा सोचना है। धन्यवाद। (इति)

1443

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): While supporting the Bill, I must also raise my concerns about the disappointing situation in which the SC and ST students and research scholars of this country are going through.

The House was stunned in to silence as an answer given yesterday exposed and revealed the alarming dropout rate of students belonging to the SC and ST community and OBC category from Central universities and higher education institutions such as IITs and IIMs in the last five years alone.

The shocking data revealed that about 13,500 students of the SC, ST and OBC students have dropped out and stopped studying without completing their courses in the last five years. The dataset reveals that from the Central universities, the total dropout number in the last five years with regard to SC students is 2,424, ST students is 2,622, and OBC students is 4,596. They all have discontinued their studies.

In IITs, the dropout number with regard to SC students is 1,068, ST students is 408, and OBC students is 2,066. And for IIMs, the dropout number with regard to SC students is 163, ST students is 188 and OBC students is 91 students.

(1445/SRG/PC)

This data is for the last five academic years, and we can only imagine in absolute disappointment that the figures would be much higher in coming years as discrimination from students as well as faculty members against Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class students has increased in these days of hatred and intolerance being promoted by the Government itself.

Sir, it is also important to note that the number of students who committed suicide in IIMs and IITs in the last year is 33, and the number of students who committed suicide in higher education institutions between 2014 and 2021 stood at 122. This is not a small number by any means. So, instead of establishing a university and creating another unchecked avenue for discrimination, it is important that effective mechanism against caste

discrimination is established. The universities and higher education institutions have become increasingly hostile towards Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. What is the reason? Could it be pure hatred fuelled by the polarizing rhetoric of the Government that rewards such racists? If yes, then I must say on this holy day of remembrance of Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, the Government must take steps in preventing caste-based discrimination in the higher education campuses as a policy priority and ensure strict punishment to the bigots who divide people and push them to committing suicide in prestigious campuses. Many faculty members have become so senseless and shameless that they start justifying the discriminatory practices as normal. Therefore, I demand that every university, higher education institutions and colleges as well as IITs, IIMs and other such institutions must have active and dedicated bodies with quasi- judicial powers to deal with the menace of atrocities against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students. And these communities must have representation from dalit academicians and eminent persons to ensure justice.

Sir, in Kerala we have one Central university. I propose that the Central University in Kerala must be named after Ayyankali, the famous social reformer from Dalit community. Apart from these points, I would further highlight the glaring lack of representation in University leadership by Dalits in the country. In many of the Central universities, among academicians, Vice Chancellors and other faculties there is no proper representation from the Scheduled Caste or Scheduled Tribe community. So, I would like to request the hon. Minister to ensure representation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

During the tenure of the previous Government, a Committee was constituted in the higher education sector. Academicians, Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were there. But that Committee was abolished. When that Committee was there, we had discussed various issues. There were representatives from IITs, IIMs, UGC as well as other academicians. That chance is gone because this

Government came to power and that Committee was abolished. So, I would like to request the hon. Minister to reinstate that higher level Committee in the Ministry to discuss the various issues from time to time in various higher education institutions.

Sir, I am not going into all the details. I would further request that the Government must take steps to increase the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Vice Chancellors in universities, and there must be a system of mandatory provisions that would ensure Dalit academic leaders in universities in India. In many of the Central universities, there is no Vice Chancellor from Scheduled Caste and Scheduled Tribe community. I will request the hon. Minister to seriously consider this issue. I would also like to take this opportunity to pay my last respect to Dr. Kunjaman, an eminent Dalit scholar who faced discrimination and talked about institutional discrimination in Kerala.

(1450/RCP/CS)

Dr. Kunjaman was a towering figure in the academic circles who was denied an opportunity for growth as the wall of discrimination prevented an access and denied him opportunities. Such types of Scheduled Caste and Scheduled Tribe economists and also prominent Dalit academicians are denied an opportunity throughout India. I would also request the Government, through your good self, to ensure filling vacancies of Assistant Professors and Associate Professors from SC, ST communities in higher education institutions and Central universities as the huge gap that exists in filling vacancies is denying them their rightful opportunities. I would also request the Government to declare the present status and position of the steps taken for filling up the vacancies and for creating vacancies in these institutions. With these words, once again, I would request the hon. Minister to take necessary steps to protect the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe students as well as the eminent academicians from Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Universities.

Thank you, Sir.

(ends)

1451 बजे

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद।

माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा तेलंगाना में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं आपको केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह विधेयक तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। महोदय, यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। यह देश में आदिवासी कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान संविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। महोदय, विविधता में एकता भारत की जनसंख्या की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9 प्रतिशत है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति-रिवाजों के साथ समृद्ध परम्पराएं, संस्कृतियाँ और विरासत है। महोदय, जनजातीय आन्दोलन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय हैं। गोंड महारानी वीर दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश इसे भूल नहीं सकता। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और बलिदान देने वाले वीर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे कई आदिवासी नायक हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 5 नवम्बर, 2021 से महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयन्ती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया गया है। केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का अभिनन्दन करता हूँ। महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय नामक एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। महोदय, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों की साक्षरता दर केवल 65 परसेंट है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। (इति)

(1455/IND/PS)

1455 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): सभापति जी, मैं सैंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का मकसद तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना है जो सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसका मकसद तालीम देना है और तालीम रोजगार के मवाके पैदा करने में कंट्रीब्यूट करेगी। इसका एंड ऑब्जेक्ट रोजगार के मौके पैदा करने का है। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेढ़ करोड़ सय्याह जम्मू-कश्मीर में आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इज़ाफा होने की तवक्को है। माना जाता है कि शायद अगले साल जैसे सरकार की उम्मीदें हैं कि तीन करोड़ के करीब सय्याह जम्मू-कश्मीर का रुख करेंगे। मेरा कहना है कि इस आमद के साथ-साथ जहां एकोमोडेशन है, होटल्स हैं या अन्य अरेंजमेंट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्को है। टूरिज्म इंडस्ट्री को, होस्पिटैलिटी को जो मैनपॉवर की जरूरत होती है, तीन करोड़ सय्याहों या चार करोड़ सय्याहों के लिए जो व्यवस्था है, इंतजाम करना या देख-रेख करना है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्को है। जो होटल रूम्स हैं, उनमें भी कई सौ गुना इजाफा होगा और साथ-साथ जो ट्रेंड मैनपॉवर टूरिज्म इंडस्ट्री में है, उनकी संख्या में भी इजाफा होगा। आप सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 के तहत भारतीय सरकार यह अहतमाम करती हैं कि जो नेग्लेक्टेड सैग्मेंट्स हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी कायम हो ताकि इस इंडस्ट्री की जो भी जरूरतें हैं, वे भी पूरी हो सकें। मेरा कहना है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज्म, होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी अनंतनाग, कश्मीर में कायम की जाए ताकि हमारी मैनपॉवर के जो तकाजे होंगे और आने वाले समय में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, वे पूरी हो सकें। इस वक्त तक हमने ऐसी डेडीकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। अनंतनाग में पहलगाम भी है, बेरीनाग भी है, रिजार्ट्स हैं, और आपको मालूम है कि तीर्थ यात्री, डेस्टीनेशन टूरिज्म, ईवेंट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और कई तरह के अन्य टूरिज्म के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। दिन प्रतिदिन डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर का टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैनपॉवर की कमी है। कश्मीर के अलावा कोई जगह सारे मुल्क में नहीं है, जहां टूरिज्म और होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया जाए और हम टूरिस्ट्स को ज्यादा सुविधाएं दे सकें, इसके लिए मैनपॉवर की जरूरत होगी। विदेशी टूरिस्टों से फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है और डोमेस्टिक टूरिस्ट्स से हमारी लोकल इकोनॉमी को फायदा मिलता है। मेरा सुझाव है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 के तहत एक होस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म होस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम किया जाए। इसके लिए प्रपोजल किया जाए, जो अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर में एस्टेब्लिश हो और आने वाले जो तकाजे या चैलेंजेज हैं, हम उन्हें एड्रेस कर सकें। मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर में या दुनिया के दूसरे देशों में होस्पिटेलिटी हमारे से ज्यादा एहतमाम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति होनी चाहिए। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। एक तो आप सहूलियात पैदा कीजिए, ट्रेंड मैनपॉवर मुहैया कराएं और साथ-साथ ही रोजगार का बंदोबस्त कीजिए, यही तालीम का एंड ऑब्जेक्ट है। मैं इस सुझाव के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (इति)

جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): چیرمین صاحب، میں سینٹرل یونیورسٹیز امینڈمینٹ ایکٹ، 2023 کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ اس بِل کا مقصد تیلنگانہ میں ٹرائبل یونیورسٹی بنانا ہے جو سممکا ساراکا مرکزی جن جا تئے یونیورسیٹی کے نام سے جانی جائے گی۔ جیسا معزّز ممبر نے کہا کہ اس کا مقصد تعلیم دینا ہے اور تعلیم روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کنٹریبیوٹ کریگی۔ اس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ہے۔ اس سال سرکاری آنکڑوں کے مطابق ڈیڑھ کروڑ سیاح جموں کشمیر میں آئے اور آنے والے سالوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ مانا جاتا ہے کہ شاید اگلے سال جیسے سرکار کی امیدیں ہیں کہ تین کروڑ کے قریب سیاح جموں کشمیر کا رُخ کریں گے۔ میرا کہنا ہے کہ اس آمد کے ساتھ ساتھ جہاں ایکوموڈیشن ہے، ہوٹلز ہیں، دوسرے انتظامات ہیں، ان میں بڑھوتری کی ایک توقع ہے۔ ٹورزم انڈسٹری کو، ہوسپِٹیلیٹی کو جو مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، تین کروڑ سیاحوں یا چار کروڑ سیاحوں جو انتظامات ہیں، انتظام کرنا یا دیکھ ریکھ کرنا ہے، اس میں بھی بڑھوتری کی توقع ہے۔ جو ہوٹل رومس ہیں، ان میں بھی کئی گُنا اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ٹرینڈ مین پاور ٹورزم انڈسٹری میں ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ 2009 کے تحت بھارتیہ سرکار یہ اہتمام کرتی ہے کہ جو نیگلیکٹڈِ سیگمینٹس ہیں، وہاں پر یونیورسٹی قائم ہو تاکہ اس انڈسٹری کی جو بھی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں۔ میرا کہنا ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ کے تحت ایک ٹورزم ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی اننت ناگ، کشمیر میں قائم کی جائے تاکہ ہماری مین پاور کے جو تقاضے ہوں گے اور آنے والے وقت میں جو ریکوائرمینٹ ہوگی وہ پوری ہو سکیں۔ اس وقت تک ہم نے ایسی ڈیڈیکیٹڈِ یونیورسٹی نہیں بنائی ہے۔ اننت ناگ میں پہلگام بھی ہے، بیری ناگ بھی ہے، ریزورٹس ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیرتھ یاتری، ڈیسٹِنیشن ٹورزم، ایوینٹ ٹورزم، میڈیکل ٹورزم اور کئی طرح کے مختلف آسپیکٹس ہیں۔ دن بہ دن ڈومیسٹِک ٹورزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، باہر کا ٹورزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مین پاور کی کمی ہے۔ کشمیر کے علاوہ کوئی جگہ پورے ملک میں نہیں ہے، جہاں ٹورزم اور ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی کو قائم کیا جا ئے۔ اور ہم ٹورسٹ کو زیادہ سہولیات دے سکیں اس کے لئے مین پاور کی ضرورت ہوگی۔ غیر ملکی ٹورسٹوں فورن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے اور ڈومیسٹک ٹورسٹوں لوکل ایکونومی کو فائدہ ملتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ 2009 کے تحت ایک ہوسپِٹیلیٹی اینڈ ٹورزم ہوسپِٹیلیٹی یونیورسٹی کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لئے پروپوزل کیا جائے، جہ اننت ناگ، جموں کشمیر میں قائم ہو، اور آنے والے جو تقاضے یا چیلینجز ہیں ہم انہیں ایڈریس کر سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ سنگاپور میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہوسپِٹیلیٹی کا ہمارے سے زیادہ اہتمام ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو کوئی دِقت یا اعتراض ہونا چاہئیے۔ منتری جی یہاں موجود ہیں۔ ایک تو آپ سہولیات پیدا کیجیئے، ٹرینڈ مین پاور مہیا کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کا بندوبست کیجیئے، یہی تعلیم کا اینڈ اوبجیکٹ ہے۔ میں اس مشورے کےساتھ اس بِل کی تائید کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں

(ختم شد)

(1500/SMN/RV)

1500 hours

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Mr. Chairman, Sir, any decision, any Bill that aims at promoting education in the country is always welcome. The Central University (Amendment) Bill, 2023 which aims at establishing a University specifically and specially for the tribal population is definitely a welcome move and the basic idea behind it is to provide avenues of higher education and research facilities among the tribal population.

Mr. Chairman, there are over 800 tribes in this country and we value their contribution in our growth story. At a time, when we are establishing one more university, we need to ask some tough questions. Mr. Minister, there are 1,182 universities in this country out of which 56 are Central Universities. Why is it so that none of these, we have 1,182 universities, universities feature among the top 200 universities of the world? Not a single one is among the top 200 universities of the world and among them, we have even 56 Central Universities. We proudly claim that we have 56 Central Universities. Our only university that features is ranked somewhere around 320. So, the big question is, are we not compromising on quality and stressing more on quantity कि देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे कॉलेजेज़ खोल दिए। We need to compete at the international level.

Mr. Minister, can you apprise us of the number of Scheduled Tribe students who are availing higher education? Is it not a fact that just like the Muslim community, the Scheduled Tribes have the highest number of drop outs in this country, almost about 25 per cent? Please correct me if I am wrong. Is it not a fact that those Scheduled Tribe students who have got all the education are not getting jobs because of the contractual system that you have adopted? So, there is no question of reservation for SCs/STs because there is a new contractual system. I admit there have been a number of Commissions and Committees that were constituted by the Government to address the economic and social plight of the Scheduled Tribes and education of the tribal population. Why is it that it continues to be dismal Mr. Chairman?

Is it not a fact that 19,000 SC, ST and OBC students have had to drop out of the premier institutes like IITs, IIMs and Central Universities. What was the reason? Among those 19000 students, 2,622 students were ST students. Is it because of the rampant casteism and discriminatory practices which is why 32 students from these elite institutes committed suicide? This data was provided to us by the Union Minister of State for Education Subhash Sarkar in April, this year.

Mr. Chairman, Sir, I was listening to a number of speakers from the Ruling Party yesterday. I would especially like to mention one lady Member of Parliament who proudly said that see it is our Government, the Government of Mr. Narendra Modi that made Mr. A.P.J. Abdul Kalam, a Muslim, the President of India. No, he deserved that place, which is why, he rose to the rank of the President of India. Then, she said that we made a Scheduled Caste, Mr. Ramnath Kovind the President of India. He deserved that. What have you done for their community? The third thing that she said was this. She very proudly said we made a Scheduled Tribe, a tribal woman as the President of India. Mr. Minister, I would like to ask one question. The President of India lives next to this palatial building that has been built by you. My question to you is this. Why was she not invited for the inauguration of this Parliament building? She happens to be the custodian of the Parliament building. She lives next door and there were heroines that were roaming around in this Parliament building when it was inaugurated and you do not invite a tribal President of India.

Mr. Chairman, Sir, I would just conclude by saying कि आपने एक ट्राइबल महिला को कुर्सी तो दे दी, पर उस समाज को सम्मान देना भी सीखिए।

धन्यवाद।

(इति)

1504 hours

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Thank you, hon. Chairman, Sir.

I rise to support the Central University (Amendment) Bill, 2023 जिसके माध्यम से हम तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तेलंगाना के ट्राइबल्स की ओर से और देश भर के ट्राइबल्स की ओर से मोदी साहब, धर्मेन्द्र प्रधान और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप ट्राइबल्स के लिए एक और सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं।

(1505/GG/SM)

साथ में लैण्ड एलॉटमेंट हो गया और पैसा भी एलॉट हो गया है। Within three-four years, the tribal community is going to enjoy the benefits of this Central Tribal University in Telangana. मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में कौन जाएंगे? इसमें क्लास वन से बीए तक की पढ़ाई पास कर के ही छात्र जाएंगे। Tribal society and tribal community need to be studied very deeply. The dropout rate from class 1 to class 10 is almost 70 per cent. इसका कारण क्या है? Lack of socio-economic development और दूसरा, ये घने जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए मोदी साहब ने एक स्टेप लिया। फ्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण इनकी लाइफ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मोदी साहब ले कर आए हैं। अब ट्राइबल छात्रों को शिक्षा में आगे ले जाने के लिए यह यूनिवर्सिटी हेल्पफुल होगी। अगर उनके कल्चर और सोशियो-इकोनॉमिक डेवल्पमेंट को साथ में नहीं जोड़ेंगे तो हमारे ट्राइबल छात्र पीछे रह जाएंगे। उनको बहुत दूर-दराज़ से स्कूलों में जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि एक ऐसी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें आईटी की सुविधा और फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई भी हो। साथ ही, हर्बल मेडिसिन की स्टडीज़ भी इसमें हो, क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया में जड़ी-बूटी से मेडिसिन बना कर टूटी हुई हड्डी जोड़ दी जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में टीटी इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन गांव में हर्बल मेडिसन से यह काम हो जाता है क्योंकि यह हर्बल मेडिसिन हम ट्राइबल्स के बीच में है। वहां इस पर भी स्टडी होनी चाहिए। साथ में, स्पोर्ट्स की सुविधाएं पूरी तरह से होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से आने वाले माननीय सदस्य मसूदी साहब ने ठीक कहा कि इसी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी की पढ़ाई भी होनी चाहिए। साथ में यहां ऐसा एटमोस्फेयर हो, इसका ईको सिस्टम ऐसा हो कि tribals should not feel isolated after having the Central Tribal University in Telangana. वहां ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेजिस की भी स्टडी होनी चाहिए। साथ ही, आईआईएम और आईआईटी की सुविधा भी उस यूनिवर्सिटी में हो। जब तक हम ट्राइबल्स के साथ दूरियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में we need to incorporate the tribal cultures and tribal values. तब जा कर हमारे ट्राइबल्स वहां जा कर अपनापन महसूस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे

मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करुंगा आज कोचिंग बिज़नस को हम कैसे बंद करें? जैसा कि रूडी साहब ने भी इसका उल्लेख किया है। कोचिंग बिज़नेस के कारण हमारे ट्राइबल लोगों के पास उसकी फीस देने लायक पैसा नहीं होता है और इसलिए ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है and they are bound to be the bonded labour in other parts of the country. इसलिए ट्राइबल्स को अच्छी

दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब के सपने को साकार करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए कोचिंग सेंटर की जगह पर तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की कोचिंग की भी सुविधा होनी चाहिए, ताकि हमारे ट्राइबल छात्र वहां आईएएस और आईपीएस के लिए फ्री शिक्षा पा सकें। हमारा यह टारगेट इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए।

(1510/MY/RP)

सर, मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा। हम ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपये से कभी आगे नहीं बढ़े हैं। आज हम एक ट्राइबल स्टूडेंट को एक महीने में 225 रुपये की स्टाइपेंड देते हैं। यह हमें कहाँ तक सहायता दे सकता है, इससे हम न अच्छे किताब खरीद पाएंगे, न ही खाने-पीने की कुछ अच्छी चीज मिल पाएगी। इस 225 रुपये से हमारे ट्राइबेल स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए, मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस 225 रुपये से आगे बढ़ने का एक प्लान बनाइए। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ताकि जंगल और पहाड़ों में रहने वाला ट्राइबल स्टूडेंट आगे आ जाए।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस मौके पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को 'वन नेशन वन सिलेबस' पॉलिसी के बारे में भी सोचना होगा। जब तक देश में 'वन नेशन वन सिलेबस' नहीं होगा, तब तक इंटेग्रिटी और देश की ताकत में कमी आएगी। पूरे देश का एक ही सिलेबस हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिलनाडु के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो। Then, there would not be any discrimination among the students of the society. 'वन नेशन वन सिलेबस' के अभाव में आज हमारे देश के हर स्टेट में अपना-अपना बोर्ड है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और ट्राइबल के स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पीछे रह जाते हैं।

मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब और सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि देश में ट्राइबल्स आईआईटी और आईआईएम इंस्टीट्यूट में भी आने चाहिए। इस कॉम्पिटिशन में हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं। इस देश के हर कोने में आईआईटी, आईआईएम और ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए।

ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ ही असम में भी 30 परसेंट ट्राइबल्स हैं। हमारा नॉर्थ-ईस्ट रीजन एक ट्राइबल जोन है। इसलिए, मैं ऑनरेबल मोदी साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी पूरे नॉर्थ-ईस्ट रीजन के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, for the entire North-Eastern Region because Arunachal is no more a backward State. अभी यह एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है, मोदी साहब ने चाइना बॉर्डj तक टू लेन रोड बनाया है। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाए। थैंक यू, सर।

(इति)

1514 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Central Universities (Amendment) Bill which envisages setting up of a tribal university in Telangana possibly in Warangal which is a district town of Telangana. The Minister must be lamenting why this Bill was not passed earlier. If it was done before Telangana elections, maybe his party would have got a few more seats. But that is neither here nor there. Mr. Dharmendra Pradhan, as the HRD Minister, is in control of the best institutes of India like IIT, IIM, and IISER. They are all under him.

(1515/NKL/CP)

So, here is really an opportunity of improving the quality of higher education in India. It is a matter of some wonder that in spite of all the money allotted, none of the Indian Institutes are among the top 200 institutions in the world. What can we do to improve the academic standards and make them comparable to the universities in England, America, France and even Singapore, leave alone China? That is the main question. Anyway, he has proposed this university for tribals. He is eminently suitable because he was a student of anthropology, and the study of tribals is done in anthropology. There is social anthropology, political anthropology which should be studied.

Mr. Mahtab gave me one idea. As has been mentioned by Kumari Agatha K. Sangma, in the North-Eastern Hill University, local languages like Khasi and Garo are taught. So, in this Tribal University, I hope, the tribal languages like Santali and Mundari will be taught. My idea is, since you are spending so much money, let the university be set up at one place but it can have campuses in several tribal dominated areas. For example, in Bengal, we have two tribal dominated areas – Jhargram and Dooars. If we set up some campuses outside, this will also give a boost to tribal education. But may I mention that in spite of striving for excellence in central universities, the situation is still bad. The cases of suicides are taking place among students in these higher education institutes. Students are dropping out of their courses.

Sir, we have a University called the University of Hyderabad in the State of Telangana. We all know about the suicide case of Rohith Vemula. It rattled the whole country how a Scheduled Caste boy felt so frustrated in a Central University that he had to commit suicide. It created a lot of dispute in the whole country.

Mr. Minister is from Odisha. In Odisha, one Central University was set up in Koraput which is totally a tribal dominated district. But it has no faculty at all. I know a lady who used to be the Vice Chancellor and never went to Koraput. She used to commute from Kolkata to Bhubaneswar and back. I will request the hon. Minister to give attention to this University in tribal dominated area in his own home State. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): That Vice Chancellor was during the UPA regime. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Whatever it is, let him have a good Vice Chancellor. There is nothing to prevent it. He has got all the power.

The other thing is, there are 36 Central Universities but I often hear a complaint that the scholarships given to the students are not sufficient. Some students from Puducherry approached me. There is a Central University there. They said that they ask their parents to send money to them so that they can continue their research. If you want to improve the quality of research, then you have to increase the scholarship amount.

(1520/MMN/NK)

Further, I would say that it is a good idea as I said, but the Minister has the chance. Now he is also a very important man in his own Party. He has got a decent clout. Let him put his clout to good use for the improvement of the central institutions. Some of the central universities are very good like the Delhi University and the JNU. They are very good. They are high standard universities. Even the Hyderabad University is also very good. But some universities are not up to the mark.

Lastly, I will ask him one thing. There is a single central university in West Bengal. In 1857, that was the first university in Calcutta. But Visva-Bharati is in shambles. The last Vice-Chancellor, who claimed to be close

to the BJP, has destroyed it. Now he had even set up a flex board depicting Visva-Bharati being given a heritage status by the UNESCO. Only the names of the Vice-Chancellor and the Prime Minister were there. The name of Rabindranath Tagore was not there. Now that has been removed by the local people. But why did Mr. Dharmendra Pradhan not remove it? Why did they allow the Vice-Chancellor to run riot? Will there be an inquiry held against the previous Chancellor over his acts of omission and commission?

As I said, I support this Bill. The tribal people deserve even more. We have not been able to give them enough, at least, educationally. If we can improve their condition, if we can keep the tribal students in the campuses, prevent their suicides, and give them more scholarships, then it would be a good thing. In this regard, I remember the contribution made by Mr. Bibhu Prasad Das who did a study of the tribes in the North-East. He suggested setting up of universities for the tribals. You can go into the archives and look into his recommendations. Due to his recommendations, the North-Eastern Hill University (NEHU) was formed just as the Rabindranath Tagore's Institute was converted into a Visva-Bharati Central University with Jawaharlal Nehru's intervention.

With these words, I again support the Bill which is a forward step towards uplifting the cause of the tribals in this country. Thank you, Sir.

(ends)

1523 hours

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this very important discussion. I think we have to approach the very concept of university with a comprehensive outlook. As this very concept of knowledge is universal, we have to approach the concept of university also with a universal mind and a universal attitude. Now-a-days, there is an increasing tendency of reducing and limiting knowledge to the corridors of subjects. That is growing as an unhealthy tendency. I would like to draw the attention of the hon. Minister and this august House to the recommendations and the suggestions made by the Yash Pal Committee in this regard. The trend of universities limiting to a singular subject, for example, medicine, engineering, teachers' education, sports, etc., will not be fruitful for realising the very aims and objectives of the universities. It may be bringing administrative convenience but it will not help the academic accommodation of different subjects thereby opening the horizons of knowledge into various vistas of wisdom.

(1525/VR/SK)

Sir, science, humanities, philosophy, aesthetics – all have to be made available under the same umbrella, that means, various subjects, various disciplines in a singular centre. Sir, research experience in science may be leading to an area belonging to the realm of philosophy. Likewise, a philosophical quest may be ending in an arena of metaphysics or cosmology. Variety of subjects will only help the richness of a university. The world-famous linguist scientist, Noam Chomsky was working in Massachusetts Institute of Technology. Harvard University was founded by a priest named John Harvard. It was founded for theological studies. I mean, flourishing in their main subjects, these universities were spreading their wings to the horizon of plurality and variety of various disciplines. Nowadays, we have to look into our surroundings when we think of a new university. Humankind is going through unprecedented changes and revolutions. All our stories are crumbling. We should have a clearcut outlook, clearcut decision and solution – what we should provide in a university, and what kind of skills we should inculcate in the coming generations, which should not merely be to get a job but to conquer life, to stand face to face with life.

Sir, I am reminded of a couplet of our famous poet Akbar Allahabadi –

हम क्या कहें अहबाब क्या कार-ए-नुमायां कर गए
बी-ए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए।

This is what is happening nowadays. Just for a job - 'बी-ए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए।' आजकल तो पेंशन भी खत्म हो गई है।

Sir, what I mean, the university should have a higher aim of understanding life situations all around. Studying textbooks only will not be enough for our students. The student will have to make his own self, go beyond the text to the context of life. Our surroundings are flooded by not only information but misinformation, prejudices and a lot of irrelevancies. So, a healthy campus has to address these kinds of problems. A healthy campus can be made only by debates, dissents and by differences of opinion, and a culture of pluralism. Both knowledge and culture are composite. Knowledge is composite and every culture is essentially and basically composite. Various American universities teaching artificial intelligence and robotics are nowadays including ethics and philosophy in their curriculum, and in their research projects. We have to prepare the learners to foster ethical, rational, compassionate, caring and healthy individuals. What is happening nowadays all over the world is exploitation, injustice, social inequalities and even aggression and killings of innocent children and mothers in various parts of the world. Wherever it is happening and whoever is responsible for this catastrophe, their problem is not lack of education, their problem is not that they do not have any degree or any academic qualification, their problem is lack of humanity. So, we will have to rise above the caste, class, creed, gender, religion and language for realising a real campus, a real university. During the formation of a university, we will have to think above the commercial and economic levels - at the human level. Absence of humanity in the society should lead to a kind of idealism, multiculturism and pluralism. I have to request the hon. Minister to keep in mind the need of using emotional intelligence, utilising the ethos and norms of emotional education so that a kind of holistic education can be imparted, taking into consideration all aspects of the learner, including his mind, heart and soul.

With these words, I support this Bill. Thank you so much. (ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Today, there is no concluding couplet!

(1530/KDS/SAN)

1530 बजे

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लाए गए इस बिल का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसको समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएगा। मैं देश की 8.6 परसेंट ट्राइबल कम्यूनिटी पॉपुलेशन की ओर से इसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने ट्राइबल कम्यूनिटी के लिए 9 सालों के कार्यकाल में बहुत-कुछ किया है। एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करके जनजातीय समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ-साथ मॉर्डन एजुकेशन दिया। जिस तरह से अभी मेरे से पहले तापिर गाव साहब बता रहे थे कि हम सभी चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्यूनिटी का कल्चर, ट्रेडीशन, पहचान के बारे में तो स्टडी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी, आईआईएम हो, दुनिया भर की एजुकेशन ट्राइबल कम्यूनिटी को मिले तथा नॉन ट्राइबल कम्यूनिटी के लोग भी आकर ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें।

महोदय, आज प्रधान मंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम मां समक्का सरक्का देवी जी के नाम से रखा गया है, जिसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर से मनाना शुरू किया था। इसके जरिए भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्यूनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्यूनिटी के चाहे फ्रीडम फाइटर्स हों या इस देश को बनाने वाले हों, ट्राइबल कम्यूनिटी के योगदान को संवारा। इस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन 9 सालों में ट्राइबल कम्यूनिटी के विकास के लिए वर्ष 2014 से 2023 तक 4 हजार 495 से लेकर 12 हजार 462 करोड़ रुपये का बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च किया, चाहे वह लोअर एजुकेशन के लिए हो, हायर एजुकेशन के लिए हो या ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो। उन्होंने इसके लिए बहुत-कुछ किया।

महोदय, मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख की 96 परसेंट पॉपुलेशन ट्राइबल कम्यूनिटी से आती है। पूरे लद्दाख की कम्यूनिटी और ट्राइबल कम्यूनिटी भी चाहती है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसे ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। लद्दाख के लिए अलग से बिल लाकर सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें दी गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दी गई, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इतना काम वर्तमान

में लद्दाख की ट्राइबल कम्यूनिटी की एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है।

(1535/MK/SNT)

मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, मैंने जिस तरह बताया कि लद्दाख में ट्राइबल कम्युनिटी काफी हैं। उनमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में हैं, जैसे जो आर्यन कम्युनिटी, सिन्ना कम्युनिटी और बाल्टी कम्युनिटी हैं, ये अब खत्म होने के कगार पर हैं। इनकी आबादी बहुत कम है। आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, पूरे देश और दुनिया से टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वे अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट हैं और उनका अलग-अलग इतिहास है। उनकी पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनकी भाषा, पहचान और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए लद्दाख में ट्राइबल रिसर्च सेंटर होना बहुत जरूरी है।

महोदय, साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, जो खत्म होने के कगार पर हैं, जो वलनरेबल हैं, उनको यूनेस्को में इनटैंजिबल हैरिटेज के नाम से घोषित करें। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। पूरे हिमालयन रीजन में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, वे ज्यादातर भोटी भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि भोटी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शाामिल करने के साथ-साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज की भाषाएं हैं, जैसे आर्य, सिन्ना, बाल्टी या पुरगी भाषा, ऐसी जुबानों को प्रमोट करने और प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह मांग रखता हूं।

महोदय, यहां शिक्षा की बात हो रही है तो मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हालांकि, यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि देश में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को काफी संख्या में बढ़ाकर उनमें स्कॉलरशिप, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन, नये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20 हजार पॉपुलेशन होना आवश्यक है। यह हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे अरुणाचल प्रदश में 26 मेजर ट्राइब्स हैं, उनके यहां एक डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी पूरी आबादी केवल पाँच-छ: हजार है। अब एक ब्लॉक में 20 हजार पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में तीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं। उनकी कुल

आबादी 13 हजार है। मेरे यहां नुब्रा में कुल 13-14 हजार पॉपुलेशन है। वहां पर भी तीन ब्लॉक्स हैं।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन): नामग्याल जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदय, हम चाहते हैं कि उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे द्रास में, वहां पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए जितनी पॉपुलेशन की क्राइटेरिया रखी गई है, वह कभी फुलफिल नहीं होती है। उसके कारण हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वंचित रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए क्राइटेरिया को थोड़ा रिलेक्स करके पॉपुलेशन की संख्या को कम किया जाए।

सर, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जब हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो लद्दाख में तीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज आते हैं, जो चांगतांग, नुब्रा और काराकोरम हैं। वे अभी बनने की प्रोसीजर में हैं। यह वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज तक नहीं गया है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आईएफएस और आईएएस का ही झगड़ा है, जिसकी वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं।

माननीय सभापति: वह अलग सब्जेक्ट है।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सर, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं।

माननीय सभापति: वह अलग सब्जेक्ट है।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सर, मुझे डिमांड रखने दीजिए। मैं पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, केवल डिमांड रखूंगा। हिमीज नेशनल पार्क का टोटल एरिया 3 हजार 350 स्कॉयर किलोमीटर है, जिसको ग्राउंड पर 5 हजार स्कॉयर किलोमीटर रखा है। चांगतांग कोल्ड रिजर्व वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के लिए 4 हजार स्कॉयर किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड पर 18 हजार स्कॉयर किलोमीटर कैप्चर करके रखा है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के लिए 5 हजार स्कॉयर किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड पर 15 हजार स्कॉयर किलोमीटर कैप्चर करके रखा है। उससे केवल वहां के रेजिडेंट, डोमिसाइल, इंडिजेनस को ही नहीं बल्कि देश के स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी हमें दिक्कत हो रही है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसको रेशनलाइज किया जाए और जहां-जहां ह्यूमेन हैबिटेशन है, वहां इसको एक्सक्लूड करके एजुकेशन में आगे बढ़ने में हमें मौका दिया जाए। इकोनॉमी अफेयर्स में भी हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। … (व्यवधान)

(इति)

(1540/SJN/AK)

1540 बजे

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं और समाजवादी पार्टी हर उस बिल का सपोर्ट करती है, जिसमें तालीम और एजुकेशन को बढ़ावा मिले। मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमें मालूम है कि इस देश के लिए रक्षा के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं पिछले कुछ सालों से यह देख रहा हूं कि हमारा जो बजट है, वह शिक्षा के लिए कितना है और बाकी चीजों के लिए कितना है। मैं अफ़सोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 15 प्रतिशत कम कर दिया गया है, जबकि अन्य यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ा दिया गया है। मुझे इस पर ऐतराज़ नहीं है, उसे और बढ़ाएं। 15 प्रतिशत बजट कम करने की वजह से रिसर्च प्रोसेस, एजुकेशन और एकेडेमिक्स में समस्या आने लगी है।

महोदय, वर्ष 2014-15 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 1,520 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में वह 1,214 करोड़ रुपये हो गया है। 306 करोड़ रुपये का बजट कम कर दिया गया है, जबकि जेएनयू का बजट 70 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। बीएचयू का बजट डबल कर दिया और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। मुझे उस पर ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस पर ऐतराज़ है कि इस देश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बजट कम कर दिया गया है।

महोदय, आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, यह खुशी की बात है। आप 7 सालों तक लगभग 900 करोड़ रुपये देंगे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। यहां सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा तो यह कहना है कि हर 2-3 मंडल में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 3 प्रतिशत एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसा विकसित देश अपनी जीडीपी का 5 प्रतिशत खर्च करता है, जर्मनी 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है और साउथ अफ्रीका 7 प्रतिशत खर्च कर रहा है। इसकी वजह से उनके यहां डेवलेपमेंट तेजी से हो रहा है और शिक्षा बढ़ती चली जा रही है।

महोदय, मुझे मालूम है कि एजुकेशन इंसान को इंसान को बनाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हर यूनिवर्सिटी में मोरल वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आज इंसान की मोरल वैल्यूज़ गिरती चली जा रही हैं। यहां पर पैरेन्ट्स-चाइल्ड रिलेशनशिप कम होती जा रही है। हमारे कल्चर में अपने मां-बाप की अदब और सेवा अनिवार्य है, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। देश की कम्युनल हार्मोनी कहां जा रही है, जिसकी आज देश को सख्त जरूरत है। हमारे देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो स्टूडेन्ट-टीचर्स रिलेशनशिप है, वह डेट्रिओरेट कर गई है। मां-बाप के बाद गुरु का दर्जा होता था, लेकिन आज लोग गुरु की ही पिटाई कर रहे हैं, उनका मर्डर कर रहे हैं। आज हम किस जगह पर पहुंच गए हैं?

महोदय, हम संस्थान बनाएं, लेकिन हम उन संस्थानों में कम से कम इंसान बनाएं, हिन्दुस्तानी बनाएं। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो हिन्दुस्तान दिया है, वह प्यार-मोहब्बत का हिन्दुस्तान, अपनी तहज़ीब का हिन्दुस्तान, एक-दूसरे के काम आने के जज़्बे का हिन्दुस्तान है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे संस्थानों से भी यही मैसेज जनता और हमारे बच्चों में जाना चाहिए।

(इति)

1543 बजे

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने यह कहा था कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इससे जीवन उच्च बनता है, शिक्षा से व्यक्तिगत जीवन भी उच्च बनता है, समाज का जीवन भी उच्च बनता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, ऐसा कोई वर्ग न बचे, जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सकें।

शिक्षा की जो महत्ता है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन में एक श्लोक याद करते थे –

न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि ।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।।

ये धन ऐसा है, जिसको चोर नहीं ले जा सकता, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं, उतनी विद्या बढ़ती है। अगर दुनिया में कोई धन सबसे बड़ा है, अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, तो उसका नाम विद्या है, उसका नाम शिक्षा है।

(1545/SPS/UB)

सभापति महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें कहना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा क्या हो, मैं इसलिए बताना चाहता हूं और यहां पर हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है – 'सा विद्या या विमुक्तये'। शिक्षा वह है, जो हमको बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्ति दिला सके और मुक्ति दिलाने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बना सके। हमें 'मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्', अर्थात् हमें अच्छा इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सकें, वह शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

हम लोग कई बार कहते हैं कि हमें लंबाई नापनी हो तो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज का वजन नापना हो तो किलोग्राम और टनों में नापना पड़ता है, अगर आदमी, किसी समाज की उन्नति, प्रगति का पैमाना नापना हो और किसी राष्ट्र की प्रगति का कोई पैमाना है तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा कि वह कैसा होना चाहिए और उसका पैमाना क्या है। उन्होंने कहा कि आदमी के आनन्द का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में यह बात आती है :-

युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्ठो दृधिष्ठो बलिष्ठ,
तस्येयं पृथिवे सर्व वित्तस्य पूर्ण स्यात्; सा एको मानुष आनन्दः।

हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो अच्छा चरित्रवान बना सके, अच्छे शिक्षक सुसंस्कृत बना सके, शरीर, मन, आत्मा से बलिष्ठ बना सके। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य है, जिससे सबसे पहले कोई भी देश नापते हैं कि देश कितना प्रगतिशील है। हम लोग कई बार अपने देश के बारे में बोलते हैं तथा नालंदा और तक्षशिला की बात करते हैं। नालंदा और तक्षशिला हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में यह बताना चाहता हूं कि यह वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो पाकिस्तान के गांधार के अंदर है। यह महाभारतकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें ऋषि धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुणि और वेद ने शिक्षा ग्रहण की। इस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य, पाणिनी, चरक, जीवक और लगभग साढ़े दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे तथा दो हजार आचार्य होते थे।

सभापति जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तक्षशिला और नालंदा थे, उसी प्रकार से कल्हण-राजतरंगिनी में जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा है, उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था, जिसमें 15 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। गुजरात सौराष्ट्र का वल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा के ओदन्तपुरी, जगदल्ला, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी और कलिंग का पुष्पगिरी बहुत बड़े विद्यालय थे। इसी तरह से बंगाल के नवद्वीप, सोमपुरा, विक्रमपुर विद्यालय थे। नवद्वीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रचलित रहा कि वहां से हलायुध, धोयी, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदीप जैसे विद्वान पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एन्नेरियम, बेलग्राम, सालोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेरियूर, नगड़, भुजबलेश्वर, बीजापुर, मनगोली, अग्रहार, नागार्जुनकोंडा, मणिषेत जैसे बड़े-बड़े विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे।

कई बारे हमारे लोग यह कहते हैं कि लोगों में एक इम्प्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहां पर शिक्षा दी, लेकिन मैं इस सम्माननीय सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। उन्होंने वर्ष 1822 के अंदर एक सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय गांव-गांव में पाठशालाएं थीं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे। उसमें 30 परसेंट शिक्षक दलित वर्ग से आते थे, 60 परसेंट विद्यार्थी शूद्र या पिछड़े वर्गों से आते थे। इसी तरह का सर्वे मुंबई में किया गया था। जी. एल. प्रेंडरगैस और डॉ. जी. डब्ल्यू लीटनर ने वर्ष 1838 और 1882 में मुंबई में सर्वे किया था। विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार हम बोलते हैं कि देश में लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई, वह सावित्री बाई फूले ने की थी, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने लिखा है और द हिन्दूज का फोर्थ वॉल्यूम हिस्ट्री लिटरेचर एंड माइथोलॉजी है, जो वर्ष 1811 में लंदन में पब्लिश हुई था। उसमें उन्होंने लिखा है कि जशोमतराय की पत्नी होती विद्यालंकार ने वर्ष 1805 में बनारस के अंदर शुरू किया। … (व्यवधान) सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : सत्यपाल सिंह जी, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

(1550/MM/SRG)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): वर्ष 1805 में उन्होंने इसको शुरू किया। मैं शिक्षा की बात कर रहा था। आर्य समाज ने वर्ष 1890 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से हमारे पास इतने उदाहरण हैं कि हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर विद्या की कितनी कीमत थी। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं उनसे जरूर यह निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, यह मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को पूरे देश की जनता को पांच प्रण दिलवाए थे और उस पांच प्रण में एक प्रण यह भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमें खत्म करनी है। जब हम कहते हैं, यह आदिवासी है, इसका मतलब यह है कि बाकी सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब यह है कि वे यहां के मूल निवासी हैं। गैर आदिवासी का मतलब यह है कि वे यहां के मूल निवासी नहीं हैं। यह जो डिविजन, यह जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया गया है, मुझे लगता है कि इस पर भी फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह बात शुरू हुई थी कि विल्हण ने जो बात शुरू की थी कि सिंधु घाटी में बाहर से लोग आए और आर्यों ने आकर सिंधु घाटी पर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं दो नाम जरूर लेना चाहूंगा- डॉ. रामजी सिंह, जिनको देश में डीएनए का फादर माना जाता है। उनका वर्ष 2011 नेचर पत्रिका, जो कि साइंस की प्रसिद्ध मैगजीन है, में इंडियन डीएनए का प्रोफाइल पब्लिश हुआ था। डॉ. वसंत शिंदे का वर्ष 2019 में पब्लिश हुआ था। हम सब लोगों का डीएनए एक ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब लोग एक हैं। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से और यह निवेदन मैंने बागपत में भी किया था। हमारा सौ साल से पुराना एक कॉलेज है, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसका उच्चकरण किया जाए और उसको सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1552 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, thank you for giving me this opportunity. I am supporting the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 because the tribal population of the State of Telangana is very much benefited. The Central University Act, 2009 was a seminal legislation of the UPA Government that established 15 universities in one single go. The objective of the parent Act is to create autonomous Centres of learning that will become Centres of Excellence in due course. In that sense, in Kerala, we also got one Central University at Kasaragod, and it will also get benefited.

The Statement of Objects of Reasons of the Bill clearly states that the purpose of this Bill is to increase access and quality of higher education and facilitate and promote higher education and research facilities for the people of the State. It will also promote advanced knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs, and advancement in technology to the tribal population of India.

The tribal population of India is the most marginalized and backward community in India. Hence, studying their life, art, culture and customs is integral to ensuring inclusive development in our nation. This is true for the tribals from Kerala as well.

For an inclusive development policy, the development of tribal community is the major agenda which has to be adopted. We can make sure of the development of tribal community only through education. Most of the tribal community people are traditionally living in remote areas, mostly inside forests. In my constituency also, there is a Panchayat called Edamalakudy, which is situated 30 kilometres away from Munnar and is inside Eravikulam National Park. Road connectivity is very less. Now only that kind of development is coming. The school facilities are very less. That is why, I personally took initiative and I channelized CSR fund through Cochin Shipyard. Now, a new school building is going to be constructed and there will be full-fledged facilities for schooling.

Sir, we noticed that after schooling, the tribal people are not willing to join college education also. In my constituency, in my district, comparatively there is more tribal population in Kerala. We only have one Eklavya Model Residential

School. We want more such schools, not only in Idukki but also in the nearby district Ernakulam. At Kuttanpuzha also another school is needed.

(1555/RCP/YSH)

After school education, most of the tribal students are not interested to join colleges. They cannot continue their studies in colleges and universities due to their own valid reasons. Sometimes SC or ST students are discriminated in the premier universities of our country. The unfortunate suicide by Rohith Vemula should not be forgotten. It is a matter of shame that a lot of tribal students are made to drop out from our top universities due to discrimination and hostility. The Government should carefully manage and stop dropout of our students.

The tribal culture has literally saved millions of lives in our country. The story of Padmashri Lakshmikutty Amma, the noted traditional healer is a case in point. Singers like Nanjiyamma and numerous other tribal artists have contributed to the richness of our culture. We should not forget that.

Opening up the avenues of higher education to tribal population has a potential to change their lives for the better. The case of young tribal IAS officer from Kerala Ms. Sreedhanya has inspired thousands of tribal students to take up higher education and prepare for joining the highest level of Government services.

For the overall development of tribal people of the whole country, opening up of a tribal university in every State should be a priority of this Government. I appeal that a tribal university in Kerala, especially in my constituency be allocated. That will be a great achievement for tribal community of Kerala.

According to other research and other reports, we can also see that the development of tribal community through more studies and more initiatives by the Government will be welcomed. For these reasons, I welcome the amendment Act. Thank you, Sir.

(ends)

1557 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाएं पूरी होंगी। वहां पर जनजातीय कला, संस्कृति, परम्पराओं तथा जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधाओं के साथ-साथ उन्नत जानकारी को बढ़ावा देने का भी कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ-साथ पूरे देश के जनजाति समुदाय को इसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं अपने बिहार राज्य में वर्तमान में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 और वर्ष 2016 में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह काम स्वागत योग्य था। किन्तु वहां पर राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिमय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केन्द्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाए हैं। वहां पर अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अत: इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, ज्ञान की नगरी, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, वह वर्ष 2010 में माननीय मुख्य मंत्री जी नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों से स्थापित हुआ। यह एक मात्र आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन की खोज की पढ़ाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है।

सभापति महोदय, यहां की बिल्डिंग काफी बड़ी है। मैं समझता हूँ कि वहां पर जो पढ़ाई हो रही है, उसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी वहां पर उप राष्ट्रपति महोदय गए थे, हम भी गए थे। वहां पर स्थानीय लोगों ने, वहां के लेक्चरर ने, सभी ने इस बात को रखा था कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, उनके अनुसार उतने विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमें उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप नालंदा विश्वविद्यालय पर जरूर ध्यान दें।

(1600/RAJ/PS)

जब माननीय प्रधान मंत्री जी पटना गए थे तब उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी थी। यह पूरे बिहारवासियों की डिमांड है। जब बिहार, ओडिशा और झारखंड साथ में थे, उस समय वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय था। यह बहुत ही पुराना है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1601 hours

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

First of all, I heartily welcome this Bill. This is one of the best opportunities given to the tribal community. While welcoming this Bill, I would like to iterate some poetic statements made by Mahatma Phule, which is in Marathi language. And I quote:

"Vidyevina mati geli,
Mativina niti geli,
Nitivina gati geli,
Gativina vitta gele,
Vittavina shudra khachale,
Itke anarth eka avidyene kele."

This is in Marathi language. It means that if education is not there, you will lose everything. You will lose thinking. And you will lose everything in life. So, education is the most important thing. Our young leader, Shri Aditya Thakre once gave an example of the British Prime Minister. He said that while addressing in the UK Parliament, the Prime Minister of UK was asked as to what were his priorities, and the Prime Minister said, 'Education, education and education'. So, that is what is the priority of that country. But culture and priority are being mixed right now, and we are having serious problems with regard to the same.

The Central Universities (Amendment) Bill proposes to establish Sammakka Sarakka Central Tribal University in the Mulugu District of Telangana. I really appreciate this step for the tribal people. But this is rather delayed. You must be aware of the same also. In 2014, when the State of Andhra Pradesh was reorganised, and it was your commitment that you will do this. But anyhow, better late than never. You are doing it right now. This is a welcome act. But at the same time, the University is named under the names of Goddesses 'Sammakka Sarakka'. What does it mean? It means

courage and sacrifice. Now, both the things are required while imparting education. Who is showing courage and doing sacrifice? These are the moral things. We have to set an example. Charity begins at home. The political arena right now is showing that we are not ready to sacrifice anything. We do not want to show the courage to fight against all the odds. And that is what is education. The universities are being established.

Dharmendra Pradhan ji, I would like to request one thing. What is the resource for higher education? I think an hon. Member has said that he has been saying this for the last ten years that there has been discrimination and disparity in every State, which you have also mentioned. Disparity is by virtue of the schools where they are situated. You have a single teacher school where you do not have teachers to go there. Discrimination is by virtue of curriculum and syllabus. So, the student who is going to a university is discriminated by virtue of a syllabus. When Javadekar was there, I insisted him this for a long time. I said that, at least, let it be in any language. But the syllabus for, at least, two or three subjects like science, maths, and English should be uniform because these are the subjects which are required for clearing Joint Entrance Examinations. You have SSC Board, ICSE Board, CBSE Board, International Board, etc. I am talking about the primary education. That is not healthy. How can you expect a child to go to the university and show that he has talent? But these universities are going to provide other things also -- cultural activities, art and culture, tribal art, etc. You have provided a substantial fund also for that. I have just quoted Mahatma Phule’s poetic words. Who did it?

(1605/SMN/KN)

In Maharashtra, Karmaveer Bhaurao Patil, Prabodhankar Thakre, Shahu Maharaj ji inspired the people for education, they inspired the people to come for education. We also tried it. In Maharashtra, we tried it to give basic education by asking them to come to the class.

Dharmendra Ji, you have been called for something.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Sawant Ji, you please address the Chair.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, he is my good friend.

HON. CHAIRPERSON: You can address him through the Chair.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): You have to see the potential of tribal people. Tribal people are very good in sports. They are very good in running and aiming. These universities should have multiple things and not that they confine to academic one. You have said that vocational and skill development also will be given to them. But then, this university has to be there where all these things are included in it. Some hostels should also be given to them. Why do these children drop out of the university? Why do these students from the Scheduled Castes or from the Scheduled Tribe communities drop out when they go to IITs and IIMs? It is because there is discrimination in basic education. They fear whether they will be able to complete it or not. Even after that, some bold steps have been taken by the Government and I feel you have launched it right now. Tribal art, traditional knowledge system and culture will be priority of the university. It will give a chance for the children to expose their potential and vocational and skill development will also be given.

Once again, I welcome this Bill but I would like to emphasise that unless you remove the discrimination in the curriculum of the primary education, you will not get the children updated and up to the mark to cope up with the studies in the university.

Thank you so much. Once again, I support the Bill, Sir.

(ends)

1607 hours

*DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): Hon. Chairman, Sir, I rise to support and welcome the Central Universities Amendment Bill, 2023. On behalf of *Thalapathy* Shri M.K. Stalin who is at the helm of affairs of Dravidian Model of Government which upholds education and medicine as its two eyes, I wholeheartedly support the Bill aimed to provide a Tribal University in Telangana. Education is an asset for us which is not detachable. The vision of *Thanthai* Periyar, *Perarignar* Anna and Dr *Kalaignar* was to provide education, that too quality education to everyone in the society and on their footsteps presently the Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathy* Shri M.K. Stalin is heading a Dravidian Model of Government providing good governance to the people of Tamil Nadu. Shri M.K. Stalin has introduced a scheme to provide breakfast to children in elementary schools aimed to provide quality education. Our Leader is making Tamil Nadu a pioneer in education particularly in women's education by providing Rs. 1000 per month to girl student pursuing higher education in Tamil Nadu. On behalf of our leader, we welcome the move to start new Universities in India. Our request to you is that not only the number of universities should increase but also the quality of higher education in these Universities should also drastically improve. Although there are more than 1100 Universities in India, only 300 Indian Universities are able to provide education of world standard. I should say it is the right time to assess and analyse our standard of education. Similarly, the Gross Enrolment Ratio as regards higher education in India stands at 27 per cent. At the same time, this Gross Enrolment Ratio for higher education is more than 47 per cent in Tamil Nadu. This is due to the efforts of Dravidian Model of Government in Tamil Nadu giving importance to higher education starting from elementary level. Along with the basic needs such as food, shelter to live and dresses to wear, education also plays a major role in development.

---

* Original in Tamil.

(1610/SM/PC)

I wish to state with pride that due to the unwavering efforts of the Dravidian Model of Government in Tamil Nadu, the Gross Enrolment Ratio of higher education is more than 47 per cent making it a progressive State in imparting quality education in India. During the last 5 years, almost 19000 students belonging to SC, ST and OBC communities have become dropouts making them unable to continue their studies in the Central Universities. Out of that, 2622 students are ST students. More than 35 students have ended their lives. In Tamil Nadu, particularly in IIT Chennai, many such incidents of students committing suicides have taken place due to caste discrimination shown by the Professors working there. We have raised this issue several times in this House but no action has been taken against the erring teachers. I once again want to flag this issue here. Everyone should come together to work hard to provide quality education to everyone. I wish to make an important demand that education should be taken out of the Union List and kept only in the State List. Only then education can be provided to all communities of the society including SCs, STs and OBCs. Due to NEET, more than 40 students have committed suicide in Tamil Nadu. This is not only an issue pertinent to Tamil Nadu. In Kota district of Rajasthan, more than 20 students have committed suicide opposing NEET. These students belong to SC, ST and OBC communities. When these students want to pursue higher education, such entrance exams conducted to test their ability stop them from pursuing higher studies as they create depression in them and lead them to commit suicide. Entrance exams like NEET should be stopped and banned. Only then we can save the precious lives of our students and ensure that the students belonging to SC, ST and OBC communities pursue higher education. With this I conclude by supporting the Bill. Thank you.

(ends)

1613 hours

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. On behalf of YSRCP, I support the Bill.

The Bill proposes to establish Sammakka Sarakka Central Tribal University in Telangana by amending the Central Universities Act of 2009. Crores of people revere Goddess Sammakka Sarakka and this gesture will respect local sentiments.

Sammakka Sarakka is Goddess of courage and sacrifice and this will hopefully empower ST population. Their literacy rate as of now is 59 per cent, whereas the national literacy average is 73 per cent. I hope that such bills will empower ST population.

Sir, I take this opportunity to highlight certain issues plaguing Indian higher education system. As per all-India survey on higher education, gross enrolment ratio in higher education is 27 per cent. It is very low when compared to global average of 40 per cent. At the same time, paradoxically, lakhs of our children are pursing higher education in foreign universities. This may be called as brain drain and economic drain.

There are regional imbalances in location of premier institutions. Concentration of premier institutions in urban areas exacerbates this regional divide. There is deficiency of experienced faculty in higher educational institutions. The ratio of pupil and teacher is nearly 30 per cent whereas in USA, it is 12.5 per cent and 19.5 per cent in China and Brazil.

There is a huge skill gap between teachers and students of rural background. A bridge course may be added in the curriculum to help the rural students. Insufficient research and development fund is taking us backwards. Our investment in R and D is very meagre. It is only 0.6 per cent of GDP whereas it is 2.5 per cent in USA and 2 per cent in China.

The quality of Indian education also needs improvement. Rote learning phenomenon of India is worrisome. This impedes critical thinking and creativity. Question pattern and examination pattern should be

revamped. Outdated curriculum creates substantial gap between needs of industry and job seekers. This limits creativity and innovation. This decreases the employability of graduates. So, curriculum should be updated as per the need of industry.

(1615/RP/CS)

Every year, nearly 10 lakh youths are coming out of colleges but industry is in search of good workers. This paradox is because of questionable quality of our education. Both, teachers and students, should be given industrial exposure. Less than 25 per cent of the total institutions of India have NAAC accreditation and only 30 per cent of universities and 45 per cent of colleges have reached 'A' level.

Sir, we have a few suggestions for the hon. Minister of Education. The financial aid in the form of scholarship, grants, and low-rate interest loans may be provided to the deprived students. Support systems like mentorship programmes, counselling services, and targeted assistance to downtrodden communities are needed. The budgetary allocation should also be increased. India is allocating around 2.9 per cent of the Budget whereas countries like USA and China have allocated around 6 per cent. Training of teachers is very crucial for quality outcomes. Incentives may be given to the teachers to boost their morale. Likewise, research and innovation need to be promoted. In the same way, collaboration between the universities and private sector is the need of the hour.

In conclusion, I would like to further put a few facts before this august House. India ranks 33rd in the world with regard to quality of education. We know that education is the most powerful weapon to change the world and it is a fundamental catalyst for growth. Around 140 crore Indians are eagerly waiting to be called *vishwaguru*. The historical Nalanda University attracted thousands of students from all over the globe. Such good days should come back to India because we are the most populous country of the world. India is blessed with a demographic dividend of having a young population. This can become a demographic time bomb if we do not provide facilities to our educational institutions and increase the employability of our graduates.

Today, thousands of our children are migrating to foreign universities. This trend should be reversed. We hope that under the able leadership of living legends like hon. CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji and hon. PM, Shri Narendra Modi ji, India will achieve this in the near future. Sir, it is sad to note that ours is a labour-driven economy. Let us make this a knowledge-driven economy. We have very few world patents. This is a testimony to this fact.

The Government of Andhra Pradesh under the able leadership of Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, Sir, has allocated Rs. 20,000 crore for setting up Amma Vodi Scheme and Rs. 4000 crore for renovation of schools and colleges under the Nadu Nedu Scheme. These schemes may be replicated at the national level.

Sir, establishing a tribal university in Telangana honours the Thirteenth Schedule of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Likewise, there are many unkept promises with regard to Andhra Pradesh. I, once again, request the Government of India to honour the AP Reorganisation Act, 2014 once again and keep the promises made in favour of Andhra Pradesh.

With these words, our party YSRCP supports the Bill. Thank you.

(ends)

1618 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, किसी भी देश की तरक्की की नींव उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। हमें खुशी है कि यह सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदय, हमारे देश में पिछले 68-70 वर्षों से बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गयी है व मौजूदा सरकार से जो उम्मीद थी, वह भी पूरी नहीं हो पायी। पिछले 68-70 सालों को देखें तो जो भी सरकार सत्ता में रही, वह हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात करती रही, लेकिन आरक्षण को लागू करने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया है।

महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नहीं मिल रहे संविधान सम्मत आरक्षण की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

महोदय, देश में जितने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं लागू होने के कारण अलग-अलग विभागों/विषयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी से आने वाले प्राचार्य, शिक्षक, प्रोफेसर आदि की भारी कमी है। यदि किसी विशेष विषय में प्रोफेसर/शिक्षक की नियुक्ति करनी हो तो बड़े ही शातिराना अंदाज में मात्र एक-एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराकर एक विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

(1620/IND/NKL)

सभापति जी, यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि समग्र नियुक्तियां एक साथ प्रकाशित की जाती हैं तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है, लेकिन एक पद के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार विगत सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो देश भर में हो रही इस गंभीर अनियमितता को मन से दूर करने का काम करे। वर्तमान समय में छात्रों की फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखे जिससे इन वर्गों के छात्र-छात्राएं अधिक से अधिक शिक्षित हों और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

महोदय, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग एक साल से अधिक समय से वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे वहां के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार से मेरी मांग है कि जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं या खाली पड़ी हुई हैं वहां यथाशीघ्र वाइस चांसलर की नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ ही मैं आपसे यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से सन् 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के रहते हुए जीरो बैलेंस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को चाहे एमटेक हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, बीटीसी हो या बीएड हो, सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पर गरीब छात्रों का एडमिशन करवा कर आगे बढ़ाने का मौका देने का काम किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप भी एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो विश्वविद्यालय आप खोलने जा रहे हैं, इसमें पिछड़े, दलित, कमजोर बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1623 hours

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

I support the establishment of Central Tribal University in Telangana. It is a very good step for the tribals in India. But at the same time, I am concerned about what is happening to education in India. कई सालों से, खास कर जब यूपीए की सरकार थी तो जीडीपी 3 परसेंट से 6 परसेंट बढ़ाने की बात थी लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे यह परसेंटेज कम होती जा रही है। खास कर जो यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, यदि हम किशनगंज की बात करें तो पिछले साढ़े चार साल से माननीय मंत्री जी से और बाकी रिलेटिड मंत्रालय जैसे फाइनेंस, माइनोरिटी मंत्रालयों से मिलकर भी, लिखकर भी और संसद में भी हमने कई बार कहा कि भारत सरकार की तरफ से जो 136 करोड़ रुपये एलोकेट किये गये थे, उनमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही एलोकेट किए गए। हम स्वागत करते हैं कि आप नई-नई यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं लेकिन जो पहले से खुली हुई हैं, उनके लिए आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? एएमयू ने 352 करोड़ रुपये क्लासेज और बिल्डिंग के लिए एडिशनल मांगे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा जो यूजीसी सैंक्शंड 29 टीचिंग, 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जरूरत है, मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में दिया गया है, वह भी किशनगंज में नहीं दिया गया है। एक तरफ तो आप नई यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें बंद करने की कोशिश में हैं। ऐसा क्यों है? जैसा कि हमारे बिहार के साथी ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। मैं उनका समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि उसे भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी किया जाए और जो भेदभाव एएमयू से किया जा रहा है या जामिया से, उसके एलोकेशन को कम करके, यह बंद होना चाहिए। जिस तरह जेएनयू और बीएचयू का एलोकेशन बढ़ाया गया है, उसी के आधार पर एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जहां के भी हों, उन्हें अच्छी सुविधा मिले ताकि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में उनका भी सहयोग रहे और हिंदुस्तान आगे बढ़े।

(1625/RV/MMN)

सर, जैसा कि बीजेपी के हमारे साथी रूडी साहब ने कहा कि बिहार वह बिहार है, जहां के नालन्दा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। हम सब उसके बारे में जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्वालिटी-ऑफ-एजुकेशन की कमी की वज़ह से बिहार छोड़ कर अलग-अलग राज्यों में जाकर तालीम हासिल करनी पड़ती है।

I would like to request the hon. Minister, through you, Sir, that education in Bihar should be taken very seriously. Bihar lacks medical colleges. यहां पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे हैं।

इसके अलावा, बिहार में आई.आई.टी. नहीं है, आई.टी.आईज़. नहीं हैं। इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। हिन्दुस्तान की कुल आबादी का दसवां भाग बिहार में है। यहां पर ऑपॉर्च्यूनिटीज़ नहीं होने के कारण, जैसा कि बीजेपी के हमारे साथी ने कहा कि हमारे बिहार के लगभग चार करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अलग-अलग कोने में काम करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक हादसे के बारे में भी बताया कि बेंगलुरु में एक जगह बिहार के सात मजदूर मारे गए। इसी तरह, हर महीने कहीं न कहीं हमारे मजदूर मारे जाते हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश होगी कि किशनगंज ए.एम.यू. सेन्टर पर ध्यान दें।

सर, आपने भी मुझे देखा होगा कि बैनर लेकर पिछले साढ़े चार सालों से लगातार मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़ा हूं। लोगों की जो जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करें। हमारा जो हक़ है, वह हमें मिले। हमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ मिले। जो एलोकेटेड फंड्स हैं और हमारी जो डिमांड है, वह हमें मिले।

(इति)

1627 बजे

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय सभापति जी, तेलंगाना राज्य में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित इस संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

1627 hours (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

महोदय, सबसे पहले, मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का और हमारे एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे एक महत्वपूर्ण विधेयक लाये हैं। यह पूरा विधेयक जनजातीय समाज के हमारे बालक-बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए है। आज मैं देश के 11 करोड़ जनजातीय बंधुओं की तरफ से भी देश के प्रधान मंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज को एक गौरव प्रदान किया है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से 15 नवम्बर को 'जनजातीय गौरव दिवस' की घोषणा करने का काम भी देश की सरकार और देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है।

महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे जो हेतु है, उसमें सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' है। इस शब्द के साथ जनजातीय समुदाय का जो विश्वास देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति है और इस समाज को जोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी को लेकर तेलंगाना में यह केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

हमारा जो आदिवासी समुदाय है, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला समुदाय, जिन्हें शिक्षा के नाम पर कोई भी चीज प्राप्त नहीं थी, ऐसे तमाम प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2014 से लेकर अभी तक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरक्की हुई है। देश के अनेक प्रकार के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है।

महोदय, इस विधेयक के अन्तर्गत, नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत भी हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हुआ है। पहाड़ पर रहने वाला हमारा जो समुदाय है, वह शिक्षा के लिए तरसता है। वह वहां पर मजदूरी करता है। तेलंगाना जैसा प्रदेश, जहां हमारा आदिवासी समुदाय निवास करता है, वह शिक्षा की उन्नति के प्रयास में आगे बढ़े।

हमारे जनजातीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, जिसके मुखिया आदरणीय शिवराज जी हैं, वहां पर अमरकंटक एक स्थान है, जहां पर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है।

(1630/GG/VR)

मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम से एक स्थान है, जहां पर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, उस अमरकंटक में भी एक जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वहां पर हमारे आदिवासी बच्चों की उन्नत शिक्षा की पहल की शुरूआत हुई है। वहीं पर मध्य प्रदेश में ऐसे शोध केंद्र स्थापित हुए हैं। जिस प्रकार से तेलंगाना की धरती पर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, इसमें हमारे आदिवासी बच्चों हायर एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। वे चित्रकला भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। उनकी बहुत सारी पुरानी कला पद्धति है। हमारी नृत्य कलाएं हैं, वहां पर उनका भी अध्ययन किया जाएगा। आज भी देश भर में देखा जाए तो सबसे अच्छी कला पूरे देश भर में आदिवासी समुदाय की रहती है। कला और संस्कृति के साथ हमारे आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, जो रीति-रिवाज़ हैं, जो अन्य समाज के वर्ग भी देखते हैं कि किस प्रकार की पूजा पद्धति यह समुदाय करता है, इस विश्वविद्यालय में उसका भी अध्ययन कराया जाएगा। मुझे लगता है कि यह देश के जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात भी है कि हमारी संस्कृति, कला, हमारी पुरानी परंपराएं, पूजा पद्धति, हम प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार से पूजा पद्धति करते हैं, उसका अध्ययन करने का भी यह शोध केंद्र कहलाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि हमारी पुरानी परंपराओं का भी अध्ययन कराया जाए।

मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम हमारी जनजातीय माता के नाम पर, सम्मक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इस विश्वविद्यालय के कारण हमारे तेलंगाना के कई जनजातीय बंधुओं को शिक्षा में लाभ भी मिलेगा। मैं इस बात का विश्वास भी व्यक्त करता हूँ कि पूरे देश में 2014 से ले कर अभी तक जनजातीय समुदाय ने ग्रामीण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय हमारे जनजातीय बंधुओं के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। मैं आज इस सदन में हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1633 बजे

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, इस बिल का मूल उद्देश्य तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। हम अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करते हैं। सरकार का प्रयास आदिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।

महोदय, तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पर्याप्त बजट जारी करना चाहिए, जिससे इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य निश्चित समय में पूर्ण किया जा सके। यह विधेयक प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

महोदय, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कला, संस्कृति और रीति-रिवाज़ों में शिक्षण और अनुसंधान प्रदान कर उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अनिवार्य है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही, पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था को भी लागू किया जाए। भारत सरकार और शिक्षा मंत्री जी से यह मेरी विशेष रूप से मांग है। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

(इति)

(1635/MY/SAN)

1635 बजे

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर, यह सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अपने आप में हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी समाज और देश के लिए गौरव का क्षण है। हमारे मोदी जी और उनकी सरकार ने एक बार फिर से अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया है। हम बार-बार कहते हैं कि हमारी यह सरकार आदिवासी, जनजाति, महिला, गरीब और हमारे युवा साथियों के प्रति समर्पित है। यह भाव एक बार फिर से हम सबको यहां देखने को मिलता है। आँकड़े भी इसी चीज की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वैसे तो कल से लेकर आज तक हमारे बंगाल के बहुत सारे सांसद जोर-जोर से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा और आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा। साढ़े नौ साल से मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षण इसके लिए कोशिश हुई है। आजादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारें रही हैं, प्रमुखता से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग पिछड़ गए थे। उनको आगे बढ़ाना हमारी सरकार का एकमात्र ध्येय था, इसलिए मैं पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं।

सर, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के विषय के बारे में थोड़ा रखना चाहूंगा। पूरा नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई-डूवर्स का इलाका है। वहां पर बहुत सारे हमारे जनजाति और आदिवासी समाज का घर है। नॉर्थ बंगाल के अंदर, विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा इलाके आते हैं। हमारे क्षेत्र की करीब तीन करोड़ के आसपास आबादी है। यहां के चाय बागान और सिनकोना बागान में हमारी श्रमिक माताएं काम करती हैं। उनमें ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। चाय बागान में करीब 6000 रुपये उनके महीने की कमाई रहती है। उनको बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, दार्जिलिंग में एक हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ऐसी माँग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका कारण भी है। देखिए, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है और कोलकाता से नॉर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, उसने हमेशा नॉर्थ बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वहां पर एक एम्स अस्पताल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी हो गई थी और वह नॉर्थ बंगाल में बनना था, लेकिन बाद में टीएमसी सरकार उसको भी साउथ बंगाल ले गई। इस प्रकार नॉर्थ बंगाल कई सारे मायने में पिछड़ा है। हमारे पास क्षमताएं बहुत थीं। क्षमताएं होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के लोगों को

बहुत अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा है। इसीलिए, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहता हूं कि वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाए।

सर, दार्जिलिंग की एक विशेषता रही है। दार्जिलिंग में सिर्फ बंगाल या आसपास के ही नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बच्चे भी आकर शिक्षा लेते रहे हैं। हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान हो, राजशाही परिवार के बहुत सारे लोगों ने दार्जिलिंग में आकर शिक्षा ग्रहण की है। अगर हम दार्जिलिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए हमारे पास जमीन भी है और स्ट्रटेजिक लोकेशन भी है। अभी बंगाल सरकार ने कोशिश की थी कि एक हिल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनायी जाए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सिर्फ कागज़ों में ही बनी है।

(1640/CP/SNT)

फिजिकली आज तक उसकी न कोई बिल्डिंग है, न वहां कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है। …(व्यवधान) यह मंकू में है। देखिए, हमारे टीएमसी के सांसद को पता भी नहीं है कि इन्होंने घोषणा की है। इनकी घोषणायें सिर्फ कागजों में रह गई हैं। कुछ बच्चों ने वहां पर एडमीशन लिया था। आज तक उनकी फिजिकल क्लास नहीं हुई। उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है। हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग हमेशा एजुकेशन हब था। अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी वहां बन जाती है तो वह उस क्षेत्र के लिए, पश्चिम बंगाल और पूरे देश के लिए बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1641 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir, for giving me this chance to take part in the discussion on a very important Bill, namely, the Central University (Amendment) Bill, 2023.

I rise to fully support the Central University (Amendment) Bill, 2023 providing for setting up Sammakka Sarakka Central Tribal University in the State of Telangana. This is to be appreciated in two ways. Firstly, it is honouring the commitment made by the Andhra Pradesh State Reorganisation Act in the year 2014 for which we have witnessed a series of agitations in this House. One of the demands of that State is being fulfilled. In that way it is to be appreciated. Secondly, according to me this is a very good move because it will achieve the goal of social justice, that too among the tribal population in the country. The tribal population is a marginalised section of the society and is a suffering community. They have been deprived of the basic human rights since long. After Independence, we have been trying our level best to put them in the mainstream of our country. But even after 75 years of our independence we are not able to bring them into the mainstream because of so many reasons. I am not going into all the reasons because of which for ages the tribal population is deprived. The basic reason is that access to higher education or access to quality education is not there. We all know that education is the strongest weapon in the world to transform a society. Here, as far as the tribal population is concerned, access to quality education is very, very remote. That is the basic reason why the tribal population of our country is not able to uplift themselves.

As far as this Bill is concerned, this will definitely be providing an opportunity to have access to quality higher education in the Central University in the State of Telangana, and that too exclusively for the tribal population. Therefore, this has to be appreciated. Why it is being established only in the State of Telangana is also justified. The literacy rate in the tribal population is very low when compared to the national average. The national average literacy rate is 73 per cent. But unfortunately, as far as the tribal

population is concerned, this is only 59 per cent. If you see the gross enrolment ratio, the national average is 18.9 per cent but in Telangana it is only 7.8 per cent. So, a Central Tribal University in the State of Telangana is well justified. It is not only providing an avenue for the educational opportunities but it is also promoting economic empowerment of the marginalised section of the society, that is, the tribal population. Therefore, I fully agree, appreciate, and support the Central University (Amendment) Bill providing for a Central University exclusively for the tribal population.

I would like to seek certain clarifications from the Minister and the Government. Since this is exclusively for the tribal population, I would like to know what would be the mode of admission for this University. Also, regarding the curriculum, what are the courses to be offered? What is the curriculum of this University? A detailed explanation is required on this. Also, the mode of admission has to be explained. Most of the hon. Members in this House during the interventions have expressed their concerns regarding the quality of our higher education.

(1645/AK/NK)

I would also like to stress on it. Prof. Saugata Ray ji has also mentioned that point. We are celebrating the *Amrit Kaal Mahotsav.* At this time we are having 56 Central Universities and more than 1,000 Universities. But even after 75 years of our Independence, we are not able to have a single university within the list of 200 universities having international or global standards. What is the reason for it? Why is it so? This issue has to be taken care.

We all have been demanding since long for having not less than six per cent of the GDP to be spent or allocated for education purposes. But unfortunately, as was just now stated, year after year the allocation or contribution for education is getting diminished in one way or the other. So, not less than six per cent of the GDP has to be spent for education and that too in particular for higher education.

The quality of education is very low. What societal impact is there? A big impact is there. In my State also it is well known to me that after Class

12 almost all the students are going for higher education to Europe, Canada, UK, US, Ireland and many other countries. Nowadays, the young and adolescent people are missing from our State. A statistical report about the State of Kerala has proved that by 2030 the State of Kerala will be an old-age home because students will not be there, and young and adolescent population will be missing from there. It is because we are not able to provide quality education in our country.

Some of the State Governments are taking it as an achievement that they are able to provide foreign education for this much number of students. One thing has to be kept in mind that those students who are migrating from India to Canada, Europe, US, UK and all these countries are not coming back. They will get the citizenship there and they will stay there only. It means that the brain drain is happening in a big way. So, that issue has to be addressed. How do we address it? We have to improve the quality of higher education in our State. This is the way by which we can address the issue of migration.

At the time when this Government came to power in 2014, so many programmes and projects were announced like the Government is going to have tie-ups with foreign universities and have better higher quality education in our country so that our student community will get better education of international standards. But unfortunately, even after nine-and-a-half years or even after conclusion of the 10^{th} year of this Government, are we able to achieve that standard of higher education in our country? The answer is No.

There was another argument that since these are public institutions and they are under the Government, we are not able to have good standard of education. We have privatised higher education. Not only higher education, but the entire education system is privatised. The commercialisation of education is going on. But even after indiscriminate and rampant privatisation of education we are not able to have international standard of education in our educational institutions. This means that we

have to think about it in a threadbare manner so as to improve the quality of education in our country.

What is the main reason for it? I will conclude after mentioning the main reason. One of the main reasons for the low quality of education is politicising the educational system in our country. Sir, you are well aware about the universities. You also spoke today morning during the '*Zero Hour*' submission about politicisation of universities. In the State of Kerala there is Governor *v/s*. the State Government going on in the education sector. There is no Vice-Chancellor in nine universities for the last two years, and in-charge Vice-Chancellors will be provided and the Party-political administration is going on. So, the highest form of politicisation of the education system is taking place. The University Grants Commission has issued a Circular. Yesterday, a question was asked by Shrimati Supriya Sule ji and the Minister has also admitted that a direction has been given to all the universities by way of a Circular that a 'selfie point' has to be installed in all the university campuses with the background of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. If this will happen in the country, then definitely all the Chief Ministers in the State will also issue Circulars that in all the public educational institutions as well as in all the colleges and schools a selfie point of the Chief Minister has to be installed so as to propagate the political, popular image of the Chief Minister and the political leadership in our country.

(1650/UB/SK)

As far as the education system is concerned, this is absolute politicisation of education which is the main reason for the lowering of standard of education in our country. Just like the Scheduled Tribes in our country, one of the marginalised communities is the coastal and marine fishermen community in our country. We have a big coastline and their standard of living is very poor. So, I would like to urge upon the Government to have a Central Marine University to give preferential treatment to the fishermen community, and it would be better if you established it in the State of Kerala which has a coastline of more than 600 kms. (ends)

1651 hours

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, the hon. Prime Minister announced in Telangana that a university in the name of Tribal Goddess, “Sammakka and Sarakka”, would be set up in the heartland of Telangana where a large tribal population is living. It would not only cater to the tribal people of Telangana, it is also a big boon for the tribals in the country. I think the utmost priority is to be given to only tribals unlike small percentage of reservation given to them in the other institutes. They will get the top priority for tribals alone. This would pave the way for 100 per cent literacy among tribals in the country.

For the first time, we have a President of India from a tribal community and we would see many more scientists and political leaders with this great initiative of hon. Modi ji to set up Sammakka Sarakka University.

I wholeheartedly support this Bill. As it is a part of the A. P. Reorganisation Act, there are some of the issues which have to be settled as per the Act, though it is out of the subject to mention right now. I would request the Government of India to look into the issues as far as the A. P. Reorganisation Act is concerned. Thank you Modi ji for giving this wonderful university to Telangana.

(ends)

1653 बजे

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से इस सदन में सैल्फी प्वाइंट का और माननीय प्रधान मंत्री जी का डिसकशन चल रही है। मुझे निराशा होती है कि यह देश कैसा हो गया? हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि प्रधान मंत्री किसी पोलिटिकल पार्टी का आदमी है और यदि कोई उनके साथ सैल्फी ले लेगा, उनकी फोटो के साथ सैल्फी ले लेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। इस देश की इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा। हम सबने बचपन में बाबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा, गजनी के बारे में पढ़ा और गौरी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी बहू-बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने और बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन यदि वह माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या हम इसी मानसिकता के साथ पार्लियामेंट में आए हैं?

महोदय, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल्स के भगवान हैं।

(1655/KDS/SRG)

आजादी के आंदोलन में बिरसा मुंडा जी ने बहुत बड़ा काम किया। 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। पूरा का पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस को मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। क्या आपने कभी भी 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया? हम 15 सालों से यहां पार्लियामेंट में हैं। वर्ष 2014 के बाद की सिचुएशन अलग है। रूडी जी तो मुझसे पहले आ गए थे। क्या इससे पहले किसी को पता है कि इस संसद भवन में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगी हुई है? क्या किसी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर कभी माल्यार्पण किया है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम तो करते ही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहां प्रधान मंत्री जन-मन कार्यक्रम चालू किया और उसी का यह नतीजा है। जब पार्लियामेंट में कोई कमिटमेंट होता है, तो वह कमिटमेंट पूरा करने का काम सक्सेसिव गवर्नमेंट का होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए सोचते हैं कि जो भी कमिटमेंट हुआ है, वह पूरा हो। वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2023 में हम इस बिल को लेकर आए हैं। क्या कभी इसके बारे में सोचा है कि 9 साल कैसे लग गए?

महोदय, मैंने कई लोगों को देखा कि इलेक्शन का समय था, तो आपने बोल दिया, कर दिया। इलेक्शन तो खत्म हो गए न, तेलंगाना में अब तो कोई इलेक्शन नहीं है न, इस यूनिवर्सिटी से इलेक्शन में कोई वोट नहीं मिलता न। 9 साल इसलिए लग गए, क्योंकि राज्य सरकार ने

जमीन नहीं दी। यदि जमीन नहीं मिलेगी, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो या भारत की संसद बनानी हो, नहीं बन सकती है। मैं केवल दो-तीन शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। इस सदन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, जहां मेरे पूर्वज हैं, जहां मेरे माता-पिता रहते हैं, वह एक बड़ा राज्य है। अशोका द ग्रेट के अलावा धर्म की बात करें, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिक्खिज्म तीनों धर्म उसी बिहार से निकले हैं, लेकिन कितने लोगों ने बुद्ध की भूमि देखी है? कितने लोगों ने जैन की भूमि देखी है? कितने लोगों ने सिक्ख की भूमि देखी है? कितने लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना है, जो महान राजा था? अशोका डायनेस्टी के बाद जिसने इस देश को इकट्ठा किया, क्या हमने उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया है? कितने लोगों ने चोल वंश को देखा है? आप कंबोडिया, सिंगापुर, बैंकाक जाइए तो आपको चोल डायनेस्टी के बारे में विस्तार से दिखेगा, लेकिन नॉर्थ-साउथ में, पॉलिटिक्स में, हिंदू-मुस्लिम में, जैन में हमने ऐसा बांट दिया कि हमको बाबर याद आ रहा है, अकबर याद आ रहा है, लेकिन चोल डायनेस्टी नहीं याद आ रही है। पुष्यमित्र शुंग, अशोक द ग्रेट आज याद नहीं आ रहे हैं। यही एक पीड़ा है।

सर, मैं दो-तीन बातें और बोलना चाहता था। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यहां पर ड्रॉप-आउट की बहुत चर्चा हुई। जहां तक मेरी जानकारी है, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या तो उनकी अच्छी नौकरी लग गई है या एक कॉलेज छोड़कर वे दूसरे कॉलेज में चले गए हैं। अत: मुझे लगता है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो ड्रॉप-आउट बच्चे हैं, वे ड्रॉप आउट होकर घर में बैठ रहे हैं या वे कहीं नौकरी पा रहे हैं, जिससे ड्रॉप-आउट का डिस्कशन खत्म हो। मैं एक छोटे-से पॉइंट के लिए खड़ा हुआ था। मेरा गांव विक्रमशिला है। रूडी जी से कल मैंने आग्रह किया था कि वह विक्रमशिला गए हैं, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बोलें। मैंने कांग्रेस के वक्ता को भी सुना। सभी कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नालंदा यूनविर्सिटी से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे गांव का विक्रमशिला यूनविर्सिटी है। वहां जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, जो यह कहता है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी में नालंदा यूनविर्सिटी का कोर्स विक्रमशिला यूनविर्सिटी गाइड करती थी। वह ओरिजनल यूनविर्सिटी थी। विक्रमशिला यूनविर्सिटी वह है, जिसने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया। भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी साल जला। प्रेमचंद्रन जी से मुझे निराशा हुई। वह कह रहे थे कि हम दो सौ विश्वविद्यालयों में नहीं हैं। नहीं हैं, तो क्या हो गया? आज गूगल का हेड कौन है? आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सुंदर पिचई कौन है? सत्या नडेला कौन है? हमारे लोग देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्यों परेशानी हो रही है?

(1700/MK/RCP)

यदि माननीय प्रधानमंत्री जी 'मेक इन इंडिया' कहते हैं, वे यदि 'वोकल फॉर लोकल' की बात करते हैं तो आपको अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं हैं, तब भी वे आगे बढ़ रहे हैं। उस विक्रमशीला विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 415 करोड़ रुपये दिये।

सर, अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आज तक पिछले 9 सालों से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए। दुनिया को विक्रमशीला के बारे में बताइए कि विक्रमशीला वह विश्वविद्यालय है, जिसको वर्ष 1189 में बख्तियार खिलजी जला रहा था, वही ऐसा साल है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार और विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि वेस्ट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए विक्रमशीला विश्वविद्यालय को रीस्टोर कीजिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, Prime Minister's selfie should not appear … (*Interruptions*) It is not correct. … (*Interruptions*)

1701 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak. First of all, on behalf of Telugu Desam Party, I would like to whole-heartedly support the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 which facilitates setting up of 'Sammakka Sarakka Central Tribal University' in the State of Telangana. Even after the bifurcation of the two States, Andhra Pradesh and Telangana, no matter how the political parties converse with each other, the people of both the States have always maintained brotherhood, have always maintained love, peace and harmony between each other. Maintaining that spirit, I would like to mention in this august House that Andhra Pradesh will be the first State which is happy when something good is happening in the State of Telangana. Considering that, bringing the Tribal University to the State of Telangana is a very happy issue for the State of Andhra Pradesh also.

Considering the tribals also, it is high time that the Government also took responsibility in giving them social, economic and political representation that is duly required for them. How do you address all these three different sectors which are very important for a community or a group? It is by providing them education. Education is the primal weapon which can give you that kind of boost which is required in the society. Definitely, this University is going to help them achieve that. On top of that, it is also important for us to study the art, literature, culture and also the customs of the tribal population. Today, when the whole world, especially the planet is looking towards the environment and climate and also the nature, we are looking at it very, very strongly. No matter how much we say that the tribals are very innocent or tribals are very backward, we are on

the verge of a revolution where we are going to adapt more and more of the customs that the tribals have been following. That revolution is definitely going to come. The Central Universities that we are talking about regarding the tribals, I think they have a very distinct and important role to play in this kind of a revolution. So, definitely studying of the art, culture and customs is also very, very important as indicated by the Bill also.

But why exactly are we discussing this Bill now? This is because of the Andhra Pradesh Reorganisation Act which dedicates two Universities, one for Telangana and one for Andhra Pradesh. We are currently discussing regarding Telangana. I would like to go into the brief history regarding the Central Tribal University for Andhra Pradesh also. When Telugu Desam Party was in power and Chandrababu Naidu was the Chief Minister in the State, from 2014 we have been strongly pursuing with the Central Government for establishing the Tribal University in the State. Also, Uttarandhra has the most tribal population in Andhra Pradesh. So, we wanted to establish it in Vizianagaram district. We have provided 525 acres. The State Government took the responsibility of building the compound wall also by spending Rs.10 crore. Then, we strongly persuaded the Central Government at that time. In 2018, the Central Government had brought the Bill also. But just because we were on the verge of elections and it was the end of the 16th Lok Sabha, the Bill lapsed. But the Central Government keeping their commitment intact after coming back – it was the Modi Government which came back at the Centre – in July 2019, they brought back the Bill. We passed the Bill in this very House. We know that the site is also ready in Vizianagaram. But the present State Government which is there in Andhra Pradesh has a very strange way of working.

(1705/PS/SJN)

They work on political vindictiveness. Whatever the decisions were taken by the previous Government, they do not want to continue or they do not want to go forward on any of those decisions. So, just because the land was given during the TDP's rule, they went back on the decision and they sat on the decision. They wanted to change the land. But how much time have they taken? They have taken four years. The Bill got passed in July, 2019 in the Parliament, and the foundation stone for that University got laid in August, 2023. The hon. Minister has himself come and laid the foundation stone. If so, much of time was taken, once the Bill is passed, to lay the foundation stone only, then when are we going to see this University as a reality and when are the students actually going to see a physical campus there, and go and study there? So, this is my request to the Central Government to speed up this activity of setting up this Central Tribal University in Andhra Pradesh also. I know that this has happened because of the delay of the present Government in handing over the land. But it is a very strange behaviour that I am seeing. Usually, in these kinds of issues, the State Governments are the active pursuers. They run after the Central Government saying that as they are giving the land, why is the Central Government not setting up the University? But this time, we are seeing that the Central Government has sanctioned Rs. 823 crore and has given Rs. 400 crore for Phase-I, and the Central Government is the one which is pursuing with the State Government asking the State Government to provide land so as to set up a Tribal University for Andhra Pradesh. So, with this attitude only, please speed it up. We do not have any confidence in the State Government that they will actively pursue on this matter. Even though we are sitting in the Opposition, we want to

strongly fight for the rights of Andhra Pradesh. So, please establish this University as soon as possible. According to the A.P. Reorganisation Act, we have other institutions also. We have IIM in Vishakhapatnam and IIT in Tadepalligudem. NIT is also there. In NIT, there is no dedicated Director right now. There is an in-charge Director. There are some staff deficiencies also in all these institutions. Getting the Bill passed in this House is half the job done. But when we will have the right curriculum, right staff, and when we will maintain a full-fledged infrastructure at these campuses, then only the job will be fully done. Therefore, I request the Central Government to ensure that they walk the talk and complete all these institutions in time because we are into the final year of completion of A.P. Reorganisation Act. The Act has given only ten years to complete all these things. But so many issues are pending. The Central Government has the prime responsibility in completing this. Once again, on behalf of the State, we request the Ministry of Education, whatever comes under its ambit, to ensure that everything is completed in time and as has been decided.

Thank you very much for giving me time.

(ends)

1708 hours

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I would like to thank the Central Government for setting up a Tribal University in Telangana. It will be very helpful for the development of tribal people in the education sector. At the same time, the Central Government should assure some reservation for the tribal people of the States concerned.

Normally, the Central Universities do not have any reservation for the mother State or the concerned States. In Puducherry, there is a Central University. The Central University is the only university in Puducherry. There is no State University. At the same time, there is no reservation for the students of Puducherry, and it is attached with the Andaman and Nicobar Islands. There is no specific reservation for the students of Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. So, the very purpose of the University is totally defeated because the local people are not being developed for this purpose. If you are setting up a Tribal University in the concerned area, then you must assure some reservation for it. You can see the example of Ladakh. They started a separate university in Ladakh. But at the same time, there is no reservation for the students of Ladakh in the University. So, it is a pathetic condition for the State concerned. Therefore, the Central Government should consider to reserve some seats. A minimum of 25 per cent of the seats have to be assured for the tribal people or the people of the State concerned.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I would like to request the hon. Minister to consider this thing. Thank you, Sir.

(ends)

(1710/SPS/SMN)

1710 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत किए गए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बिल के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यहां बहुत से वक्ताओं ने बातें कही हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मेनडेट है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं केवल उन्हीं बिंदुओं तक कन्फाइन रहूंगा। मुझे लगता है कि इसके दो-तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है -Mandated by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. वर्ष 2014 का जो आन्ध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें इसको इस्टैब्लिश करने की बात थी तो यह हमारे लिए ऑब्लिगेटरी था।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 46 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। Article 46 of the Indian Constitution provides that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. आर्टिकल 46 का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उस आर्टिकल 46 या हमारे आदिवासियों के लिए न केवल एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान के इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पीएमजनमन स्कीम शुरू की है। इसमें भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने 24 हजार 104 करोड़ रुपये अप्रूव किए हैं। The PM-JANMAN is a Rs. 24,104 crore Tribal Welfare Scheme approved by the Union Cabinet. It is one of the largest Central Schemes and is targeting the largest tribal community in terms of outlay. आज आजादी के बाद देश के आदिवासियों के लिए इतने बड़े बजट का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इसके लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किन्हीं राज्यों में रहने वाले आदिवासी हमारी सरकार और भारत के प्रधान मंत्री का निश्चित तौर से स्वागत कर रहे हैं कि आज उस क्षेत्र और उस धारा को आगे किया गया है। The scheme focuses Particularly Vulnerable Tribal Groups to address their specific needs and aims to provide various facilities including housing, drinking water,

sanitation, education, health, nutrition, road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunities. झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, बिहार या पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्य में जिस तरह से एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है और वे सुदूर गांव के जंगलों में रहते थे, उनके लिए न हाउसेज़ हैं, न एजुकेशन है, न्यूट्रीशन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके में जीवन कितनी मिलेगी।

महोदय, आज पूरे देश के उन आदिवासियों के लिए इतना बड़ा आउटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का लाल किले से देश के लोगों को हाउसेज़ देने का संकल्प था कि जिसके सिर पर पक्की छत नहीं है, हमारी सरकार देश के गरीब, खेत-खलिहान में रहने वाले हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत देगी। आज उस कल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार ने जनमन स्कीम में यह तय किया। The scheme includes the construction of approximately 4.9 lakh *pucca* houses at a cost of Rs. 2.39 lakh per house. ये देश के उन आदिवासियों के लिए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो चाइल्डहुड में उन आदिवासी बच्चों को उन जंगलों, घरों से निकालकर देश की मुख्य धारा में लाएंगे। हमारे रूडी साहब ने अच्छा कहा था कि शिक्षा है, उसी के नाते हम सब यहां बैठे हैं और एजुकेशन ही है, जो हमें ज्ञान देती है।

(1715/MM/SM)

एजुकेशन ही हमको ज्ञान देता है। उसके नाते ही हमने शुरू किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसका ऑबजेक्ट है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, खास तौर से जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और उनको Not only to enable them to avail of reservation in high and professional education courses for jobs in public and private sectors but also to have access to the best opportunities in education at par with the non-ST population. आज यह यूनिवर्सिटी खोलने का लक्ष्य क्या है? हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि आज जो यह कहा जाता है कि जो नॉन एसटी पॉप्युलेशन है, जो शहर में रह रहे हैं, अभिजात लोग हैं, उनको अवसर और ऑपर्च्युनिटी मिली और वे आगे निकल गए। आज हमारी सरकार का संकल्प है कि उन लड़कों की तुलना में हमारे वे आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको भी इनके कम्पीटिशन में लाकर आगे कर सकें। यही नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को हम इस तरह से प्राप्त करेंगे कि हमारी सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तेलंगाना के ईस्टैबिलिशमेंट में है It

aims to cater to the regional aspirations of the State of Telangana. हमारे एकाध मैम्बर्स ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है? इसमें साफ दिया गया है कि जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, it will perform educational and other activities similar to any other central universities. मतलब, जो दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन्हीं के एटपार, उन्हीं की तरह से यह सेन्ट्रल ट्राईबल यूनिवर्सिटी भी रहेगी। क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता है? क्या आपको अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है? मेरे लिए देश है, लेकिन जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो वहां की मिट्टी हमें चंदन की तरह खुशबू देती है। वहां की पगडंडियों पर सरसों के जब पीले फूल देखते हैं तो लगता है कि जैसे जिंदगी में जन्नत मिल गयी है। आज हमारे उन ट्राइबल्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी क्योंकि पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी तो हमारे ट्राइबल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनायी गयी, जिसमें देश भर के ट्राइबल्स के बच्चे जा सकेंगे। एक सेन्ट्रल एकलव्य यूनिवर्सिटी शुरू की गयी है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं केवल उसी विषय से रिलेटेड बोल रहा हूं। आज उनकी एक्सैस क्या होगी?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Jagdambika Pal, please conclude now.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं एक लाइन बोलकर कनक्लूड कर रहा हूं। Focusing on tribal art, tribal culture and technology aims to promote advance knowledge about tribal art, culture, customs and technological advancement for the tribal population of India. अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आधा घंटा लगेगा। माननीय धर्मेन्द्र जी इसको अपने उत्तर में बताएंगे। मेरे ये सारे विषय देश में एक रेवोल्यूशन लाएंगे। इस बिल के पास होने के बाद आदिवासी बच्चों के आर्ट में, कल्चर में, एजुकेशन में, कस्टम में, टेक्नोलॉजी इत्यादि, सारी दुनिया में उनके पंख खुलेंगे और दुनिया में आकाश की क्षितिज की ऊंचाईयों तक वे पहुंचेंगे। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

(इति)

1718 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you Sir. I support the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. For ages, the tribal population are facing significant challenges in accessing higher education.

According to the Ministry of Tribal Affairs, in 2023, the literacy rate of tribal population is notably lower than the national average, standing at 59 per cent in comparison to overall rate of 73 per cent. This educational disparity further exacerbates their struggle for higher education. The enrolment rate in higher educational institutions is disproportionately low among tribal students.

Furthermore, the gross enrolment ratio in higher education in Telangana is 7.8 per cent, which is substantially lower than the national rate of 18.9 per cent as per the all-India survey on higher education of 2020-21.

The establishment of Sammakka Sarakka Tribal University, therefore, will address the huge regional and educational gap among the tribal population of the country in general and Telangana in particular. Therefore, I support the Bill.

Sir, there is a news in today's *Malayala Manorama*. One of the former Ministers of Karnataka, Shri Goolihatti Shekhar, belonging to ST community, has not been permitted to enter the Hedgewar Museum in Nagpur. It is reported in today's *Malayala Manorama*. He has not been permitted to enter the Hedgewar Museum in Nagpur.

(1720/RP/YSH)

When we are talking about encouragement of the tribal students or tribal people in India, at the same time, we are facing such type of discrimination. We have to understand and address this issue.

With these few points, I am concluding my speech and supporting the Central Universities (Amendment) Bill.

Thank you.

(ends)

1721 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस बिल का स्वागत करते हैं और ट्राइबल बच्चों के लिए इस व्यवस्था को देना अत्यन्त जरूरी था। इसको पिछले 10 सालों से किए गए एक वादे के दृष्टिगत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से आए सांसद आदरणीय राम नायडू जी की वर्षों से की गई यह मांग आज सकारात्मक रूप ले रही है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ।

इसके अन्दर जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वे तीन लेवल पर आती हैं। पहली, हमारे इन नवयुवकों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोग पहाड़ी इलाकों में और उसके साथ-साथ वन क्षेत्रों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में रहकर वहां की पढ़ाई करने के बाद इनको जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स रहते हैं, भाषा को लेकर जो बैरियर्स हैं, उसमें भी बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर अक्सर यह पाया गया है कि जो लोकल टीचर्स होते हैं, जो उनकी स्थानीय भाषाओं को समझते हैं, जिससे उनको उनके भावों को समझने में आसानी होती है, उनकी उपलब्धता ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में न होना कहीं न कहीं एक बड़ी खामी को दर्शाता है।

पूर्व में भी हमने यह देखा है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ को जो बजटरी एलोकेशन्स हुए हैं, उसको लेकर हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है। हालांकि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के बजट में 70 परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि काबिल-ए-तारीफ है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में यह सामने आया है कि इस क्षेत्र में ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ और ट्राइबल शिक्षा को लेकर न्यूनतम स्तर पर इनवेस्टमेंट होने का कार्य हुआ है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा।

हमने यह भी देखा है कि जो आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स और खराब होते जा रहे हैं। खासतौर से इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, वे इन्हीं स्कूल्स में से निकलकर, आगे बढ़कर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड बद से बदतर होता चला

जा रहा है। हाल ही में हमें देखने में आया था कि कुछ बच्चों को खास तौर से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं उचित नहीं थीं, बहुत ही अनुचित तरीके से उनको वहां पर रहना पड़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे ट्राइबल बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और वे आगे जाकर जब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे तो उनके अंदर उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की वे सारी की सारी तकनीकी व्यवस्थाएं हों, उनका दृष्टिकोण उस हिसाब से तैयार हो जाए। उसके लिए हमें ऐसे आश्रम स्कूल्स में, एकलव्य स्कूल्स में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है, जो हाल में हमें देखने को नहीं मिलती हैं।

वर्ष 2014 में हमने देखा था कि 793 बच्चों की इन आश्रम स्कूल्स में मृत्यु हो गई थी। हमें महाराष्ट्र का एक केस इस तरह का देखने को मिला था। इसी के साथ-साथ ऐसे स्कूल्स में हमें यह भी देखने को मिलता है कि किसी बिच्छू के काटने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है या किसी की सिर में दर्द से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे विद्यालयों की आज दयनीय स्थिति है।

मुझे इससे आशा और उम्मीद है कि आगे चलकर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इतना बड़ा प्रावधान कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो करीब-करीब 800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे केसेज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी ने निरंतर यह कहा है कि इनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इनकी लोकल भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और ये जो दूर-दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, वहां आश्रम स्कूल्स और एकलव्य स्कूल्स में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनको सुदृढ करने की आवश्यकता है। जब तक बेसिक चीजें नहीं सुधरेंगी, तब तक ऐसी उच्च यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचकर वे अपने लेवल को हासिल नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1725/NKL/RAJ)

1725 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the inception, I do not have any qualms or dithering in according my unqualified support to this legislative document under the title, the Central Universities (Amendment) Bill, 2023.

Sir, today, it is a sheer providence and a coincidence that when the new Government in Telangana is going to be sworn in, today's legislation will certainly add a new jewel to the crown of Telangana itself. In pursuance of the commitment that has been made by the predecessor Government, it was committed that one Central Tribal University in the State of Telangana will be established. In pursuance of that obligation, the Central Tribal University in the State of Telangana under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 is going to be established. The fact is that all the Members across the spectrum are subscribing to the contents of this legislation.

1727 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, it is a fact that education is a key determinant to the growth and development of tribal population in our country. India is a multilingual and a multiracial country. We are boasting 574 tribal groups in our country. Across the world, out of the total tribal population, we share nine per cent of the population. But at the same time, the seamy side of all our development agenda is that there is still a conspicuous absence of our tribal pupils in higher education in our country. So, more participation of tribal students in higher education is an imperative need for the growth of the tribal society of our country. So, I would like to know from the hon. Minister what the current gross enrollment ratio of tribal pupils in our country is, which may suggest the growth of the tribal people along with their education.

Sir, in our educational system, already 7.5 per cent has been reserved for tribals. May I like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the number of vacant faculty posts in Central Universities disproportionately impacts candidates' eligibility under reservation quotas? 65.61 per cent of vacant posts are those which are reserved for the marginalized communities.

(1730/MMN/KN)

Out of that, the percentage of ST is 5.76. It clearly suggests that more priority should be given to enhance the participation of the tribal population not only in education but also in faculty so as to ensure their presence in each and every sector.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another issue. According to the Minister of State for Education, who is also present here in the House, about 13,626 students from the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class communities have dropped out of the central universities, Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management in the last five years. Again, I would like to be enlightened by the Minister concerned whether the Government has carried out any study to understand the reason behind such high dropout rates in these institutions.

It was stated that out of the total dropped out students in various institutions, around 4,596 OBC students, 2,424 Scheduled Caste students, and 2,622 Scheduled Tribe students dropped out from the central universities, while as many as 2,066 OBC students, 1,066 SC students and 408 ST students dropped out of the IITs, and 163 OBC students, 188 SC students and 91 ST students dropped out of the IIMs in the same period. So, certainly, I think it is a matter of grave concern to be noted.

It is even noted that elite institutions like the IIT, IIM have been hitting the headlines in the wake of alleged rampant casteism and other discriminatory practices faced by the students belonging to these communities in the campus. More than 33 students had died by suicide at various IIT and IIM campuses. In December, 2021, the Union Government had told Parliament that 122 students had died by suicide at the central higher educational institutions between 2014 and 2021. Out of the 122 students, 24 belonged to the Scheduled Caste community, three belonged to the Scheduled Tribes and 41 belonged to be OBCs.

In our country, since the Independence, a plethora of measures have been taken in order to bring, assimilate and include those isolated communities of our society, namely, the tribals, aborigines, primitive, *girijan* and *vanajati* to the mainstream of our society. In 1948, Dr. Radhakrishnan had prepared one education mission to that end. In the year 1968, the Education Policy clearly

demonstrated the endeavour of the Government to assimilate and to include those isolated societies in the mainstream. So, a plethora of measures have been taken by the successive Governments in the country but still they are lagging behind much to the concern of all of us.

(1735/PC/VR)

So, I must suggest that they should be imparted more training and integrated services. Similarly, the girls of the tribal society should be guaranteed social security because you know that a section of tribal population in our country is still in the grip of various prejudices, superstitions, taboos, etc. etc.

सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उद्घाटन करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, तब उद्घाटन समारोह में एक ट्राइबल, आदिवासी लड़की, जिसका नाम बुधिनी मांझी था, उसने उनको माला पहनाई थी। उसी दिन से उस लड़की का समाज से बहिष्कार हो गया था। 80 साल गुजरने के बाद वह अपने गांव गई थी और उसके बाद उसका देहांत हो गया था।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर और अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। एजुकेशन के बारे में उनको थोड़ा और जागरुक करना है। इसके लिए पहल करना भी एक जरूरी मुद्दा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्राइबल स्टूडेंस को पढ़ने के लिए सरकार पैसा जरूर देती है। श्री राजीव गांधी जी के ज़माने में फेलोशिप प्रोग्राम चालू हुआ था। A Central University for Tribals was also established in Amarkantak. हमारे मंत्री जी जिस स्टेट से आते हैं, वहां Kalinga Institute of Social Sciences है। इसे पूरी दुनिया में एक बड़ा प्रतिष्ठान माना जाता है। अत: काफी पहल हुई है, लेकिन फिर भी हमें और भी आगे जाना बाकी है।

सर, मैं इस सदन में, इस संदर्भ में बात रखते हुए आउट-माइग्रेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं।

You will be astonished to note that students of Indian origin will be visible in 228 countries and dependent islands across the globe. About 17000 students are studying even in Bangladesh. Can you imagine that about 78 Indian students are studying in Afghanistan? Why? It is because the aspirational section of our society has been growing fast. The aspirations of the middle-class society do not match with the educational facilities of our country. So, there is a serious dearth of higher educational institutions in our country which has been prompting

the exodus, I may say, outmigration of Indian talent. That means, brain drain has been continuing unabated. In order to defray their tuition fee and living expenses, those Indian students are spending Rs.6 lakh crores every year which is a mindboggling amount. Not only that, more than 40 lakh Indian students are studying abroad. So, what is the policy of this Government to bring back those talent into our country?

सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में हम एजुकेशन के ऊपर बड़ी चर्चा करते हैं, हम नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी की बातें भी करते हैं। एक जमाना था, जब ब्रिटिश हुकूमत और बाहरी ताकतों ने, कोलोनियल फोर्सेज़ ने अपने एग्रेशन के चलते हमारे देश पर कब्जा किया था, लेकिन आज नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी होने के नाते आज दुनिया को हमने अपने कब्जे में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज हिन्दुस्तान के लोग पूरी दुनिया के कोने-कोने में छाए हुए हैं। चाहे वह अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी अन्य देश हो, हर जगह बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइजेशंस में बड़े-बड़े पदों पर, सबके माथे पर हमारे इंडियंस बैठे हुए हैं।

(1740/CS/SAN)

वे सब हमारे ऐसेट हैं। उन ऐसेट को हम वापस क्यों नहीं ला सकते हैं? इसमें हमारी क्या खामियाँ हैं? इन खामियों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

महोदय, मैं रविन्द्र नाथ टैगोर जी के देश से आता हूँ। स्वामी विवेकानन्द जी के देश से आता हूँ। हम जानते हैं कि रविन्द्र नाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, इन सारे विद्वानों ने हमारे देश की उच्च शिक्षा के लिए कितना प्रयास किया था। जो सोशल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था। इसके लिए हमारे सौगत राय जी कह रहे थे कि शांति निकेतन बनी थी। बिल्कुल, हमारे देश के कोने-कोने में विद्वानों की पहचान है और इन विद्वानों के नाम से बहुत सारे प्रतिष्ठानों को हम जानते हैं। Swami Vivekananda had said that 'education is needed for building our character; education helps us strengthen our character; and it is our character that can cleave through the adamantine walls of all adversities.'

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैंने जो दो-तीन मुद्दे रखे हैं, मैं इनका जवाब माँगना चाहता हूँ और सेल्फी-सैवी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को यह भी नसीहत देते हैं कि सेल्फी-सैवी न होते हुए एजुकेशन-सैवी जो हमारे देश के नौजवान हैं, इनके लिए और ज्यादा सोचिए। इसमें हमारे देश की भलाई है। नमस्ते।

(इति)

1742 बजे

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदय, कल से केन्द्रीय विश्वविद्यालय 2023 (संशोधन) विधेयक आपने इस पवित्र गृह में अनुमोदन के पहले चर्चा के लिए अनुमति दी है। मेरे सहयोगी डॉ. सुभाष सरकार जी ने कल इसे आपकी अनुमति से प्रस्थापित किया था। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन का सभी पक्षों की तरफ से, सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। 40 से ज्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बहाने सबके सामने रखे हैं। जिस मूल विषय के लिए आज चर्चा हो रही है, आन्ध्र प्रदेश बाइफरकेशन विधेयक में तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में, दो राज्यों में दो ट्राइबल विश्वविद्यालयों की प्रतिस्थिति थी, कमिटमेंट था, जिम्मेदारी थी। एक वर्ष 2018 में हो गया था। आज वह अवसर आया है। अधीर रंजन जी ने सही कहा कि जब तेलंगाना में एक नई सरकार बन रही है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि हमने कल मनायी है, ऐसे समय में तेलंगाना में एक नये जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने में इस सदन ने सर्वसम्मति से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें अमूमन सभी सर्वसम्मत होते हैं। पद्धति के बारे में किसी के थोड़े सुझाव और किसी की थोड़ी अलग पद्धति भी रहती है, लेकिन एंड-प्रोडक्ट के बारे में सब सहमत होते हैं।

माननीय अध्यक्ष : अगर किसी को आलोचना ही करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं? अधीर रंजन जी को तो कई बार सकारात्मक नहीं, केवल आलोचना ही करनी है। क्या आप यह डिसाइड करके आते हो?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैंने आलोचना नहीं की है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रधानमंत्री जी समय-समय पर देश के नौजवानों को सम्बोधित करते हैं, उनका हौंसला बढ़ाते हैं। आप यह भी तो बोला कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, उन्हें नेता को खुश करना होता है।… (व्यवधान)

(1745/IND/SNT)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं निश्चित रूप से चीजों को स्पष्ट करना उचित मानूंगा। हमारे प्रजातंत्र की यह ब्यूटी है कि कुछ विषयों में आज हम एकमत हो पा रहे हैं। आपके नेतृत्व में जो नया सदन बना है, उसमें आज हम समाज के वंचित वर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मक्का-सारक्का तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण जनजाति महोत्सव है। सदियों से कई राज्यों की, न केवल तेलुगु भाषा भाषियों की, आंध्र और तेलंगाना, पड़ोस का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की कुछ जनजातियां इस सम्मक्का-सारक्का के उत्सव के साथ मेडारमा यात्रा, जिसका पूरा नाम सम्मक्का-सरक्का मेडारम यात्रा, मुलुगु जिले में है, संयोग से बहुत मशक्कत के बाद मित्रों ने यह विषय उठाया कि इतनी देरी क्यों हुई? देरी इसलिए हुई क्योंकि तेलंगाना सरकार इस यूनिवर्सिटी के लिए स्थान तय नहीं कर पा रही थी। बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली स्थान दिया। कैबिनेट में पहले निर्णय हुआ और आज एक विधेयक आपके माध्यम से पारित

होगा। सम्मक्का-सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लगभग 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ बनाया जाएगा। आपके अनुमोदन के बाद इस प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा। पहले मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी थी। बाद में इसी सरकार को, प्रधान मंत्री मोदी जी को सौभाग्य मिला और देश में दो ट्राइबल यूनिवर्सिटीज एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में बनाने का सौभाग्य मिला। उत्तर इसी में मिल जाता है, केवल कल्पना करने से या स्लोगन देने से शासन व्यवस्था नहीं चलती है, बल्कि करने से चलती है। मोदी जी सौभाग्यशाली हैं, वे करते ही हैं, इसीलिए उनके ऊपर जनता का विश्वास और भरोसा है और इसे करने का हमें आज सौभाग्य मिला।

अध्यक्ष जी, आज इस चर्चा में सभी ने चिंता व्यक्त की। मुझे मोह हो रहा था कि सभी का नाम लूं। हमारी बहन श्रीमती सुनीता मुद्गल से लेकर नेता विरोधी दल।… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सुनीता दुग्गल।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : जी हाँ, सुनीता दुग्गल। आप गार्डियन हो, आपका ही दायित्व है कान पकड़कर ठीक करना। लेकिन आप बार-बार सेल्फी के बारे में बोलने के लिए उठना नहीं, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आपका उतावलापन समझ सकता हूं। अधीर रंजन जी को आज कल खुश नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ही खुश करना पड़ता है। दीदी को भी खुश करना पड़ता है और भतीजे को भी। आप चार बार उठे हैं, आप बैठिए, मैं आपको भी उत्तर दूंगा।… (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आप पार्लियामेंट में आते हैं और उत्तर देते हैं कि मैंने राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है।… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैंने पार्लियामेंट में कहा नहीं है। अभी कहूंगा।… (व्यवधान) अभी भी कहूंगा।… (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): You have no authority to announce a CBI inquiry on the floor of the House…. (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं दादा का दर्द समझ रहा हूं। तीर कहीं लगा है तो आज कष्ट होना स्वाभाविक ही है। गरीबों का पैसा लूटोगे तो निश्चित रूप में कार्यवाही होगी ही होगी।… (व्यवधान) मैं सेल्फी के बारे में निश्चित उत्तर दूंगा। आप पहले दिन की बात कह रहे हैं। कभी आपत्ति लाओ तो उसके ऊपर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आज देश की जनता को जानने का अधिकार है, विशेष करके बंगाल की जनता को अधिकार है कि ब्लैक एंड वाइट क्या हो रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी एक बार होना ही चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है।… (व्यवधान) जोर-जोर से चिल्लाने से, थिएट्रिक करने से, ड्रामा करने से सत्य छुप नहीं जाता है। इस विषय को हम भी कभी-कभी सामने रखना चाहेंगे।

अध्यक्ष जी, देश आजादी की लड़ाई 19वीं सदी में भी लड़ा, 20वीं सदी में भी देश आजादी की एक लम्बी लड़ाई लड़ी और इसमें आधी सेंचुरी चली गई। 19वीं सदी के मध्य से देश के कई इलाकों में आंदोलन शुरू हुए। उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व के एक तबके ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस आजादी की लड़ाई के अग्रणी नेता रहे।

(1750/RV/AK)

उसी समय, हमारे समाज जीवन में ऐसे कुछ मूर्धन्य व्यक्तित्व रहे, जिनमें स्वामी विवेकानन्द, योगीराज श्री अरविन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, राधाकृष्णन, पंडित गोपबंधु दास जैसे लोगों का एक तबका रहा, जिन्हें यह ध्यान में था कि कुछ सालों के बाद देश आज़ाद हो जाएगा और जब आज़ाद हो जाएगा, तब देश की रचना कैसे होगी। अगर हम शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, शिक्षा को भारतीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा?

अध्यक्ष जी, वर्ष 1835 में अंग्रेज नीतिकार मैकाले ने एक मीटिंग बुलाई कि इस देश को ऐसे ही पराजित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1835 में अंग्रेजों ने यह तय किया कि अगर इस देश को लम्बे समय तक अर्थनीति की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना है तो इस देश की जो मूल आत्मा शिक्षा है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह संभव नहीं है। इसलिए पराधीनता की मानसिकता के आधार पर कोलोनियल रूल को लम्बे समय तक जारी रखने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गयी। वे सारे महानुभाव, जिनका मैंने नाम लिया, सभी ने अपने-अपने तरीके से देश की अंतरात्मा को खड़ा करने के लिए काम किया।

महोदय, केरल के मुस्लिम लीग के माननीय सदस्य शायद अब्दुल्ला जी हैं। उनके भाषण की मैं प्रशंसा करूंगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था उसकी अंतरात्मा के साथ कैसे जुड़नी चाहिए, उन्होंने इसका आज उल्लेख किया है। सदन के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा की उस मौलिक आवश्यकता को भारतीयता के साथ जोड़ना और उसे आत्मनिर्भर बनाने जैसे इन सारे विषयों को रिकॉग्नाइज़ किया। इसके लिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभी का मर्म एक था कि हमें देश की गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। यह एक लम्बा प्रवास है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर सारे माननीय सदस्यों ने जिन-जिन विषयों का उल्लेख किया है, अगर मैं सारे विषयों को सारांश में देखता हूं तो उसमें तीन-चार विषयों पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता प्रकट की है, अपना कन्सर्न दिखाया है। आपकी अनुमति से मैं उसमें से एक-दो विषयों को मैं रखना चाहूंगा।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने ड्रॉप आउट के बारे में कहा है। सभी ने एस.सी./एस.टी./ओबीसी प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। कई सदस्यों ने डिस्क्रिमिनेशन को भी आज की चर्चा का विषय बनाया है। आपके माध्यम से मैं विनम्रता से सदन को दो-तीन विषयों से अवगत कराना चाहता हूं… (व्यवधान)

सौगत दा, हम आपसे सीखते हैं। मैं बचपन से आपको जानता हूं। आप तथागत जी के भाई हैं। हम आपको आदर्श मानते हैं। मेरी और आपकी उम्र में पिता-पुत्र या छोटे भाई - बड़े भाई का अन्तर है। आपके सारे विषयों का उत्तर दूंगा। मैंने जब अख़बार पढ़ना सीखा, तब से मैं सुदीप

दा का नाम पढ़ता आया हूं, लेकिन अगर आप लोग बालक जैसे स्वभाव के बन जाएंगे, तो कैसे होगा? मैं आपके सारे विषयों का बिल्कुल उत्तर दूंगा।… (व्यवधान)

दादा, मैं वही बात कह रहा हूं। जब मैं बालक था और उस समय जब मैं स्टेट्समैन पढ़ता था, उसमें मैं आपका नाम पढ़ता था। जो विषय आपने मुझे बाहर कहा, उसे मैं यहां नहीं कहूंगा। दादा, आप थोड़ा धीरज रखिए। हम आपका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष जी, ड्रॉप-आउट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। अधीर रंजन जी ने उसको कोट किया और लगभग सभी ने यह कोट किया कि पाँच सालों के अन्दर सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशन्स से इतने लोग बाहर चले गए। यह स्टैटिस्टिक्स सही है, लेकिन यह अर्द्ध सत्य है। यह सत्य है, लेकिन इसके बेस का तो थोड़ा हिसाब लगाइए। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, इनकी सभी की जिन्दगी में, यहां भी कई माननीय सदस्य हैं, अगर उन्हें पढ़ाई पूरी करनी होती तो उन्हीं में से कुछ लोग नॉबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेते, लेकिन जैसी उनकी सामाजिक आवश्यकता है, जैसे घर में दिक्कत, परिवार में दिक्कत, खुद की आवश्यकता इत्यादि के कारण उनका पढ़ाई पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। किसी व्यक्ति को पहली बार में आई.आई.टी., भुवनेश्वर में एडमिशन मिल गया। उन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। बाद में उन्हें फाइनली आई.एस.सी., बेंगलुरु में एडमिशन मिल गया। जब वह आई.आई.टी., भुवनेश्वर छोड़ कर आई.एस.सी., बेंगलुरु जाता है तो रिकॉर्ड में वह आई.आई.टी., भुवनेश्वर से ड्रॉप-आउट हो जाता है। उन्होंने पी.एच.डी. की है। पिछले दिनों हमने अध्यापकों की नियुक्ति की मुहिम चलायी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पी.एच.डी. होना अनिवार्य है, जो पहले से ही था।

(1755/GG/UB)

हमने देखा कि इस कारण से एससी एवं एसटी वर्ग के लोग अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमने उस अनिवार्यता को हटा कर पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, तो जो पीएचडी कर रहे थे, वे छोड़ कर फिर जॉइन कर गए। इसलिए ऐसे सारे लोगों का ड्रॉपआउट तो दिखेगा न? 5 सालों का जो नंबर आपने दिखाया है, यह सत्य नहीं है कि ये लोग पढ़ाई छोड़ कर चले गए। जिसको आदरणीय निशिकांत जी ने अध्ययन कर के आपके सामने रखा है कि ये दूसरे ऑप्शंस के लिए, दूसरी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या परिवार के लिए और कुछ कष्ट है, उस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूँ, उस कष्ट के लिए वे बाहर गए। अगर अभी मैं एनरोलमेंट की बात कहूँ, कई मित्रों ने उसको पूछा है कि एनरोलमेंट का क्या है। मेरे मित्र सप्तगिरी जी ने अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में कहा और कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल विद्यार्थियों के बारे में कहा। मैं पहले दो आंकड़ों का उत्तर देता हूँ। मेरे मित्र सप्तगिरी जी, शायद आपके तथ्य पर्याप्त नहीं हैं, सही नहीं हैं। मेरे पास पिछले 5 सालों के जो तथ्य हैं, उनमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी 8 पर्सेंट से नीचे ट्राइबल छात्र उस संस्थान में नहीं रहे हैं। सभी समय में 7.9, 11.15, 9.44, 9.34 पर्सेंट रहे हैं, संविधान की व्यवस्था के हिसाब

से एसटी छात्रों का रिज़र्वेशन 7.5 पर्सेंट होना चाहिए। लेकिन कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिज़र्वेशन कैटेगरी से ज्यादा विद्यार्थी आज भी पढ़ते हैं। अगर मैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक की बात करूं तो वहां किसी भी वर्ष में 13, 14 या 15 पर्सेंट से कम ट्राइबल छात्र नहीं पढ़ते हैं। यह जो एक धारणा है, आज भी कई सदस्यों ने चर्चा की है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, तो वहां केवल ट्राइबल छात्र पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ट्राइबल इलाके में होगी, ट्राइबल विषयों पर चर्चा होगी, ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में चर्चा होगी और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जितना ट्राइबल रिज़र्वेशन है, उतने विद्याथी पढ़ेंगे। आज तो उस संस्थान में उससे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह तथ्य शायद सप्तगिरी के पास पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं आज 2 बेस लाइन पर आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2014 में देश की सेवा करने का अवसर मिला, तब देश में, एबसॉल्यूट नंबर में, उच्च शिक्षा में, 3 करोड़ 42 लाख विद्यार्थी थे। यह जीईआर तब 23 पर्सेंट होता था। उस आयु के बच्चों के अंदर यह 23 पर्सेंट होता था। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो 23 पर्सेंट होता था। इसी साल, यानि वर्ष 2021-22 में ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के आंकड़े आए हैं, जो कि मेरे हाथ में हैं। वर्ष 2021-22 के सर्वे के हिसाब से यह बढ़ कर 28 पर्सेंट हुआ है। 23 से 28 पर्सेंट हुआ है और एबसॉल्यूट नंबर में 4 करोड़ 32 लाख हुआ है। अगर इसकी ग्रोथ को मैं आपके सामने विनम्रता के साथ रखूंगा तो चिंता का कोई कारण नहीं है। मैं फिर एससी, एसटी और ओबीसी के आंकड़ों पर आऊंगा। आज भारत में नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। नए क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस खुल रहे हैं। उसके कारण नए-नए कोर्सेज़ खुल रहे हैं। पहले हमारे यहां एआई में अण्डर ग्रेजुएट कोर्सेज़ नहीं थे। पहले हमारे मेडिकल इंस्टिट्यूट्स और इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट्स मिल कर जॉइंट कोलैबोरेटिव कोर्स नहीं चलाते थे। आज भारत की कई सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इस प्रकार के नए कोलैबोरेटिव इंस्टिट्यूशन चलाने के कारण देश का विद्यार्थी देश में पढ़ता है। इसके कारण आज देश में लगभग 26.5 पर्सेंट ग्रोथ, 2014 से 2021-22 तक हई है। अभी 2023 का हिसाब आने वाला है, तब थोड़ा और बढ़ेगा। यह विशेषकर महिलाओं में हुआ है। आदरणीय सुप्रीया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की है। मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन मैं वर्ष 2014 और 2021-22 का कम्पैरिज़न देता हूँ। वर्ष 2014 में जितनी महिलाएं पढ़ती थीं, छात्राएं पढ़ती थीं, उनकी तुलना में आज 31.6 पर्सेंट ज्यादा पढ़ रही हैं। यही सरकार की उपलब्धि है। आज एसटी की चर्चा हो रही है। मैं एसटी की बात कर रहा हूँ। एसटी की टोटल ग्रोथ में 65.2 पर्सेंट ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ एसटी की हुई है। ... (व्यवधान)

(1800/MY/SRG)

माननीय अध्यक्ष: अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, अगर मैं एसटी गर्ल्स स्टूडेंट्स का कम्पैरिजन वर्ष 2014-15 और वर्ष 2021-22 के बीच में करूंगा तो इसमें 80 परसेंट ग्रोथ हुई है। एससी की टोटल ग्रोथ 43.8 परसेंट हुई है। उसमें वूमेन की ग्रोथ लगभग 51 परसेंट हुई है। ओबीसी की ग्रोथ 45 परसेंट हुई है। उसमें वूमेन की ग्रोथ 49.3 परसेंट हुई है। देश में ओवरऑल जितने विद्यार्थी पीएचडी कर रहे थे, वर्ष 2014-15 में 1,17,301 पीएचडी रजिस्ट्रेशन था। इस देश के वैज्ञानिकों के आक्रोश के कारण, आज उसकी संख्या 2,13,000 हो चुकी है। इसमें 81 परसेंट की ग्रोथ हुई है। महिला पीएचडी के बारे में हमारे सुदीप दा और सौगत दा को चिंता हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी की सेल्फी प्वाइंट क्यों बना रहे हैं। इसे हम इसीलिए बना रहे हैं कि जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुई, तब हमारे प्रधानमंत्री जी बेंगलुरू पहुंच कर, वहां जो महिला वैज्ञानिक काम कर रही थी, सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्हीं की की। क्या यह गौरव का विषय नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री किसी दल के होते हैं, क्या वह किसी वर्ग के होते हैं? हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे स्कूलों और ऑफिसेज़ में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और फादर ऑफ दी नेशन महात्मा गांधी जी के फोटो लगे रहते हैं। आज हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले, विश्व में भारत को अव्वल नंबर तक पहुंचाने वाले और विकसित भारत बनाने की आह्वान देने वाले नेता का अगर हम गौरव से सेल्फी प्वाइंट लगाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? यह प्रजातंत्र है। आप भी गौरव कीजिए। आपको नहीं उठाना है तो नहीं उठाइए। हमारे बच्चे तो उठा ही रहे हैं। यह कोई कंप्लसरी नहीं है। हमारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

महोदय, आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद महिला पीएचडी की 106 परसेंट ग्रोथ हुई है। सुप्रिया ताई, वर्ष 2014 में बागडोर आपके हाथ में थी, आपके हाथ में मौका था। वहां बैठे हुए मित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी देश और राज्यों के शासन के दायित्व में थे, आपको किसी ने मना नहीं किया था। अगर आज हमें सेवा का मौका मिला है तो हमने फोकस किया है। पीएचडी करने वाली महिलाओं की संख्या 106 परसेंट बढ़ी है।

अध्यक्ष जी, अभी शिक्षक नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। आज मैं इस पवित्र गृह में एक तथ्य ऑन रिकॉर्ड रखना चाहूंगा। जब मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में आया, तो डीएमके के कुछ मित्र, तमिलनाडु के कुछ मित्र, आज वे यहां नहीं हैं, वे मुझसे मिलने के लिए आएं। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे देश की आईआईटीज़, एनआईटीज़ और सेंट्रल इंस्टीटयूशंस में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक न्याय का समर्थक हूं, उसका प्रैक्टिशनर हूं, विश्वासी हूं। हम बचपन से ही बाबा साहब अंबेडकर के लिए 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को

मनाते आए हैं। जब मैंने विभाग के अधिकारी मित्रों से चर्चा की, तब हमें पता चला, मैंने एक रिसर्च स्टूडेंट के रूप में पूरा असेसमेंट किया, जिनके आँखों में क्रोकडाइल टियर्स हैं, जो घड़ियाली आँसू बहाते हैं, इस सदन में लंबे-लंबे भाषण देते हैं, फिर मैं कहूंगा, जिनके हाथ में दशकों तक शासन रहा, उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीटयूशन में एससी, एसटी टीचर अप्वाइंटमेंट में रिजर्वेशन के बारे में क्या कानूनी व्यवस्था की थी? सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करने वाले लोगों ने क्या किया था? जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वर्ष् 2019 में पहली बार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एक्ट आया, जिसको मिशन मोड पर चलाने के लिए लाया गया है। उसमें एक कानून लाया गया।

(1805/CP/RCP)

जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें स्टूडेंट टीचर रेश्यो में जितने टीचर्स रहेंगे और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है और ओबीसी के लिए कितना है, उतने ही टीचर्स बिना कम्प्रोमाइज के अपॉइंटमेंट होंगे। वर्ष 2019 में पहली बार यह कानून आया, नरेन्द्र मोदी जी ने इसे किया। पहले आपके हाथ में दायित्व था। आज आप बहुत प्रश्न उठाते हैं कि क्यों खाली है? लेगासी इश्यू है। आज हमको मौका मिला है उस पवित्र काम को करने का, पुण्य करने का। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं। 28 अक्टूबर, 2023 को, लेटेस्ट, देश में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स में जो वैकेंसीज़ हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखता हूं। लोग रिटायर होते हैं, नई नियुक्तियां होती हैं, इसलिए पद का यह खालीपन बराबर बना रहता है। अगर मैं 28 अक्टूबर, 2023 का कोट करूं तो 18,019 पोस्ट्स एकैडेमिक्स में खाली थीं। पिछले दिनों में, अक्टूबर से 7 दिसम्बर तक का मैं हिसाब दे रहा हूं। प्रधान मंत्री जी हर एक महीने में रोजगार मेला करके नियुक्ति देते हैं। 11,272 नियुक्तियां पिछले दो महीने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में पूरी हुई हैं। उसमें एससी 1402, लगभग 12 पर्सेंट, एसटी 572, लगभग 5 पर्सेंट, ओबीसी 2,321, लगभग 21 पर्सेंट नियुक्तियां अभी पिछले दो महीने में हुई हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में 6,747 में 854 एससी, 307 एसटी, 1,441 ओबीसी नियुक्त हुए। मैं यह दो महीने की स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स शामिल हैं। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, टीचिंग, नॉन-टीचिंग, आज एक मिशन मोड पर इसको भरने का हम काम कर रहे हैं। इसका एक्ट लाये और भर भी रहे हैं। आज हमारे समय में ड्रॉप आउट की संख्या, स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया। आज एनरॉलमेंट में, जीआर में हमारी बढ़ोत्तरी क्या हो रही है, मैंने आपके सामने उसका एक तथ्य रखा।

महोदय, निवेश के बारे में चर्चा हुई कि उच्च शिक्षा संस्थान में ज्यादा निवेश होना चाहिए। …(व्यवधान) दादा को और एक बार मैं थोड़ा उस ट्राइबल जीआर के बारे में बता दूं। जब वर्ष 2014-15 में आपका दायित्व था, उस समय में ट्राइबल 16 लाख 41 हजार विद्यार्थी थे, उसमें 65 पर्सेंट ग्रोथ हुई है। अगर 3 करोड़ 42 लाख में से 16 लाख की गिनती करूं, तो यह लगभग

साढ़े 4, 5 पर्सेंट होता है और आज 4 करोड़ 32 लाख में से 27 लाख 10 हजार विद्यार्थी हो चुके हैं। इसमें 65 पर्सेंट की ग्रोथ हुई है। जो कांस्टीट्यूशनल मैनडेट है, 7.5 पर्सेंट, नियरिंग दैट, पिछले नौ सालों की सरकार में यह ट्राइबल जीआर की उपलब्धि है।

अध्यक्ष जी, निवेश के बारे में, एक्सपेंडीचर इन एजुकेशन कहा गया। कई मित्रों ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में चार, पांच, छ: पर्सेंट होता है। भारत में जब हमारा दायित्व वर्ष 2013-14 में आया, तब एजुकेशन की स्पेंडिंग जीडीपी की 3.84 पर्सेंट थी, जो आज बढ़कर 4.64 पर्सेंट हुई है, लगभग 1 पर्सेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट। पिछले दिनों में, 2013-14 में जिनके हाथों में शासन था, उनसे आज हम 30-35 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पिछले दिनों में, हमारे देश में 7 नये आईआईटीज़ बने हैं।

(1810/NK/PS)

सात नये आईआईएम बने हैं, दो नए आईआईएसईआर बने हैं, 16 ट्रिपल आईटी बने हैं, कोटा में भी एक ट्रिपल आईटी बना है। एक नया एनआईटी बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 7 और इसको मिलाकर 8 बने हैं। 40 से ज्यादा नयी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। कुल मिलाकर डेढ़ सौ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिसमें पिछले 8 सालों में 40 हमने ही जोड़े हैं। इस काल खंड में ही जोड़े हैं, यह इस सरकार की उच्च शिक्षा में खर्च बढ़ाने के बारे में प्रतिबद्धता है।

ट्राइबल कमिटमेंट के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं चार-पांच विषयों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी ने देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया। प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पहली बार मनायी। पहले भी बिरसा मुंडा थे। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई नही की थी, बाकी लोगों को भी याद करने की जरूरत थी। हमें सौभाग्य मिला, हमने उनको सम्मान दिया। आप कुछ भी कहें, इन दिनों मुझे सौभाग्य मिला।

मैं ओडिशा से आता हूं, लेकिन कभी आदरणीय राष्ट्रपति जी के गांव में नहीं गया था। वह मेरे गांव आते थे तो मैं उनके साथ में रहता था। झारखंड और ओडिशा के बार्डर पर अत्यंत ट्राइबल कन्सट्रेंट इलाका है। मैंने आंखों की चमक देखी है। पहली बार देश में अपनी जिन्दगी को एकदम दरिद्रता, bottom of the pyramid से उठ कर आने वाली महिला इसी काल खंड में देश की राष्ट्रपति बनी हैं। कोई कुछ भी कहे, महिला और जनजाति, हमें प्रजातंत्र में महिमामंडन करने का सौभाग्य मिला। यह इसी काल खंड में हुया है।

इसमें कोई वोट का संपर्क नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 24 लाख 70 हजार पीवीटीजी, आदिम जनजाति के लोग हैं, लोग कहते हैं कि सेल्फी क्यों उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं। आपको सत्ता के सात दशक मिले, लेकिन आपने गौरव नहीं किया। मेरे नेता ने याद करके बिना वोट की चिंता रखते हुए 24 हजार करोड़ रुपये उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ के लिए खर्च किए हैं। यह जनजाति विकास के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री जन मन योजना आज शुरू हुई है। 700 से ज्यादा एक्लव्य विद्यालय ट्राइबल कन्सन्ट्रेट ब्लॉक में बन रहे हैं। इसमें 28 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, एक स्कूल बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह इस सरकार की उपलब्धि है। मुझे सौभाग्य मिला, मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विजयनगरम गया, शायद यह नया जिला बना है। शायद इस सदन ने अल्लूरी सीताराम राजू का नाम नहीं सुना होगा। हम सौभाग्यशाली लोग हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश इलाके के अल्लूरी सीताराम राजू वीर पुरुष थे, आदिवासी थे, देश के गौरव के लिए लड़े थे। आज हम उन्हीं के जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में बना रहे हैं।

हमारी प्रतिबद्धता लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। लोगों के लिए करने के लिए है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे आए हैं। आज सभी ने शिक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमें विरासत में मैकाले शिक्षा पद्धति मिला था, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की।

सौगत दा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे राज्य के महापुरुष विधु भूषण दास जी का नाम लिया। एक ओडिया होने के नाते मैं कृतज्ञ हूं, आपने कम से कम याद तो किया। उन जैसे शिक्षाविदों के कारण देश में एक वैकल्पिक शिक्षा बननी चाहिए, भारतीयता के आधार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में नयी शिक्षा नीति एक दार्शनिक तत्व हमारे सामने है. It is a philosophical document for 21st century to create global citizens, जिसमें अमृत काल में आने वाले 25 सालों में देश के विद्यार्थी, देश के नौजवानों की रचना कैसी होगी, उनकी मन:स्थिति कैसी होगी, विकसित भारत बनाना है तो शिक्षा ही कुंजी है।

(1815/SK/SMN)

शिक्षा ही टर्न एराउंड करेगी कि क्या-क्या शिक्षा होनी चाहिए। आज सभी लोग उसी में सहमति दिखा रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना है।

मैं राष्ट्रीय शिक्षा के दो-तीन फीचर्स के बारे में कहूंगा। कई लोगों ने आदिवासी भाषा के बारे में कहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का है जिन्होंने कहा कि भारत की सभी स्थानीय भाषाएं, सभी मातृ भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, चाहे वह ओलचिकी हो, मुंदारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयाली हो, पंजाबी हो या असमिया हो, सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। लोग भाषा के आधार पर समाज को बांटने में लगे थे, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भाषा से जोड़ने का काम किया।

मैं अपने मित्र सप्तगिरी जी के जिले कोरापुट में गया था, वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या काम करती है? वहां दो लोकल लैंग्वेजेज में बोला जाता है, एक को

कुई भाषा कहते है और दूसरे को देशीय भाषा कहते हैं। सप्तगिरी जी, आप थोड़ी प्रशंसा तो कर देते कि हमने दो प्राइमर निकाले हैं, आप तो पढ़े-लिखे हैं, आपको तो मालूम है, हम आपके जिले में 1 अप्रैल में गए थे, उत्कल दिवस के दिन गए थे। वहां जो स्थानीय भाषा बच्चे घर में सुनकर आते हैं, उसी को उड़िया भाषा के साथ लिंक करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए प्राइमर भाषा बनाई है। भारत सरकार भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने का स्टाइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्नोलॉजी में यह संभव है।, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि संभवत: आठवीं तक भारतीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, भारत की सभी 22 शैड्यूल्ड लैंग्वेज़ेज को भारत सरकार ने, भारत की संविधान व्यवस्था ने शैड्यूल्ड किया है और सारी शैड्यूल्ड लैंग्वेज़ेज में धीरे-धीरे सीबीएसई पाठ्य पुस्तक और टीचिंग लर्निंग मैटीरियल बना देगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंश है। आज भारत सरकार काशी-तमिल संगमम आयोजित कर रही है, दूसरी बार कर रही है। काशी और तमिल संस्कृति, दोनों का अभिन्न संपर्क है और आज उस भाषा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है।

आज की शिक्षा नीति का मकसद सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। अब एक फंडामेंटल एप्रोच बदली है। हमें स्किल्ड मैन पावर बनानी है। ड्रोन आ गया है, ब्लॉक चेन आ गई है, टेक्नोलॉजी के नए आयाम आ गए हैं। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी एकांगी रूप में पढ़ाया जाता था, अब इसे इकट्ठा पढ़ाना पड़ेगा और मल्टीडिसीप्लेनरी करना पड़ेगा। हम सारी व्यवस्था का आज की राष्ट्रीय नीति में विज़न कर रहे हैं। अब हमारी प्रॉयारिटी का विषय एन्टरप्रियोनरशिप है। कई मित्रों ने रैंकिंग के बारे में कहा है। महाराष्ट्र, औरंगाबाद के आदरणीय सदस्य ने रैंकिंग के बारे में कहा। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन यह रैंकिंग रातों रात नहीं होगी। अभी-अभी क्यूएस रैंकिंग आई जिसमें पहली बार भारत के इंस्टीट्यूशन्स तेजी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बेंगलुरू रिसर्च में दुनिया के पांच इंस्टीट्यूशन्स में से एक बन चुका है। यह आज भारत की वैज्ञानिक शक्ति की उपलब्धि है। हम कितने दिन बाहर वालों के सर्टिफिकेट से चलेंगे। वर्ष 2014 के उपरांत हमने एनआईआरएफ रैंकिंग व्यवस्था भारत में शुरू की है। नैक धीरे-धीरे हम सभी इंस्टीट्यूशन्स में कम्पलसरी करने जा रहे हैं, सभी को एक्रेडिटेशन करना पड़ेगा। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यह बात सही है, विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि नैक एक्रेडिटेशन में मैं जिस इंस्टीट्यूशन का फार्म भर रहा हूं, उसका स्तर क्या है? अब हम इसे करने वाले हैं। इसमें तेजी से नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का दायरा बढ़ाया है, एनबीए का दायरा बढ़ाया है, यह आज हमारी प्रेक्टिस बन चुकी है। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट की कि बच्चे बाहर चले जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी तो फीस बढ़ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पवित्र सदन को बताना चाहता हूं और आपको सुनकर गर्व होगा कि अब माननीय प्रधान मंत्री जी को विश्व के देशों का नेतृत्व करने वाले फोन करते हैं कि हमें आईआईटी दीजिए। अब भारत की प्रेस्टीजियस आईआईटी, दिल्ली आबूधाबी में अपना कैम्पस खोल रही है और थोड़े दिनों में वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। दादा, यह उनके खर्चे पर है, हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं।

(1820/KDS/SM)

अध्यक्ष जी, अफ्रीका महादेशों को ध्यान में रखते हुए तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास, अपना कैम्पस खोल चुका है।… (व्यवधान) दादा ठीक है, मैं मान गया। मैं आपसे क्यों उलझूं, क्यों तर्क करूं? आप स्वयं जाकर आए हैं, मैं क्यों उलझूं? अध्यक्ष जी, रूडी जी यहां हैं और उधर से अधीर दा ने भी स्वीकृति दी कि हमारे राज्य में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आज देश के लिए गौरव ला रहा है। वहां आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा मॉडल खड़ा किया है। भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विदेश जा रही हैं। आज भारत की यूनिवर्सिटीज में 'स्टडी इन इंडिया' भारत में आकर पढ़िए, ऐसी व्यवस्था में विश्वभर के अनेक विद्यार्थी भारत आने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें हम पढ़ाने के लिए भारत लाएंगे। वे भारत आएंगे, पढ़ेंगे तो भारतीयता को लेकर लौटेंगे। आज भारत की शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। … (व्यवधान) दादा, आप बैठ जाइए। जब आईआईटी आबूधाबी में खोलने का प्लान किया तो वहां के मंत्री कुछ बच्चों को लेकर आईआईटी, दिल्ली लेकर आईं। बूट कैंप, समर कैंप लगाने के लिए दिल्ली आईं। मैं भी उनका स्वागत करने के लिए और मिलने के लिए गया। वह मंत्री अपने बच्चों को समझा रही थीं "Do you know what this institution is? This is IIT. If you want to become a CEO, if you want to become 'Sundar Pichai', then you have to study here." देखिए दादा, दुनिया बदल चुकी है। जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, वे देश का ही काम कर रहे हैं। आज अजय बांगा वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष हैं। जब जी-20 हुआ था, तब प्रधान मंत्री जी ने उन्हें बुलाया था। वे कहते हैं कि मैं बाहर नहीं पढ़ा हूं। मैं देसी हूं, मैं मेड इन इंडिया हूं। मैं बाहर जाकर विश्व बैंक का अध्यक्ष बन चुका हूं। भारतीय मूल का व्यक्ति आज यूके के प्रधान मंत्री बन चुके हैं। आज पुराना जमाना चला गया, आप थोड़ा आगे बढ़ें।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यहां से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग बाहर चले जाते हैं।… (व्यवधान) वे अफगानिस्तान चले जाते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं। यह चिंता का विषय है।… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, यह चिंता का विषय है, आज इसीलिए भारत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बाहर के क्वालिटेटिव विश्वविद्यालयों को भारत में आकर अपना कैम्पस खोलने की पहली बार हम अनुमति देने वाले हैं, यह कानून यूजीसी की ओर से हो चुका है। दो फॉरेन

यूनिवर्सिटीज ... वॉलोंगोंग और डिकेन गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैम्पस अगले शिक्षा वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और कम खर्च में ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्टडी यहां भी हो सकती है। धीरे-धीरे दुनिया बदल रही है और हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मैं एक-दो विषयों का थोड़ी विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा। सभी लोगों ने अच्छी चर्चा की है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोगों ने अपने मत रखे। मैं एक नागरिक के नाते, संयोग से शिक्षा विभाग के मंत्री के नाते जब इस विषय का उत्तर देता हूं, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं कि मेरा दिल भर आता है और मेरे पास उत्तर नहीं होता है कि कभी एक सभ्य समाज में हमारी आईआईटी, आईआईएम या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लड़के को आज के समाज में यदि किसी कारण से अपने अमूल्य जीवन से हारना पड़ता है, तो इससे बड़ी दुखद घटना किसी के लिए नहीं हो सकती है। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं।

(1825/MK/RP)

अगर दुनिया हमें उंगली दिखाए तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं, एज ए नागरिक और एज ए शिक्षा मंत्री। मैंने पहले भी कहा है और आज इस पवित्र गृह में भी इस बात को कहता हूं कि यह समाज का दायित्व है। हम सभी को इस विषय से जूझना पड़ेगा। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। अगर रोहित वेमुला की बात की जाएगी, दादा अगर आप विश्व भारती की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। मैंने बंगाल सरकार की विवशता को भी देखा है। सुदीप दा और सौगत दा, दोनों के पड़ोस में यादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्या आप और हम इससे सहमत हो सकते हैं? क्या यादवपुर में जो हुआ, वह अच्छा हुआ? क्या उसमें हम राजनीति करेंगे? मैं तो नहीं करने वाला हूं। हमें सारे विषय को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी कैंपस में, सरकार किसी की भी हो, अगर किसी बच्चे का जीवन जाता है तो हम सभ्य समाज के लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूं। मैं मुंह छुपाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे नेता का यह संस्कार नहीं है। हम उस समस्या को जड़ तक जाकर समझने वाले लोग हैं। इसीलिए, सारी रचना बनाई गई है। यह कोशिश है। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार की जाति की रचना की जाती है। आज मैंने शिक्षा का एक स्टैस्टिक्स दिया है, जिसमें हमारे कार्यकाल में एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्गों के लोगों की पढ़ाई का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज देश में चार ही जातियां हैं। गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है और युवा एक जाति है। विकसित भारत के लिए चार जातियों की शिक्षा, आज की सम्मक्का, सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम निवेदन लेकर आए हैं। यह पवित्र गृह इसका अनुमोदन करेगा। हम भारत को वर्ष 2040 तक विश्व की एक ताकतवर देश बनाएंगे। इसी संकल्पना के साथ मैं सभी का समर्थन चाहता हूं। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 मूव करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move:

"Page 1, line 8,-

f*or*	"a body corporate"	
substitute	"run by the Central Government".	(1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 मूव करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment no. 2 to clause 2.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3, 4 एवं 5 मूव करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move:

"Page 1, line 11,-

after	"avenues of"	
insert	"free".	(3)

"Page 1, line 11,-

after "higher education"

insert "and scholarship". (4)

"Page 1, line 12,-

for "primarily"

substitute "only". (5)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3, 4 एवं 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुमलता अम्बरीश - उपस्थित नहीं।

श्री एम. के. राघवन - उपस्थित नहीं।

श्री अब्दुल खालेक - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 13 मूव करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मुर्शिदाबाद जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसा दिया कीजिए। वे मर रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है। आप उनको पैसा दिया कीजिए। हम कुछ नहीं चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप संशोधन मूव कर रहें हैं या नहीं कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): नहीं सर, ठीक है। हम बस यही मांग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 मूव करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 1, after line12,-

insert “3H. There shall be established a Tribal University, which shall be a body corporate, be known as the Idukki Central Tribal University, having its territorial jurisdiction extending to the whole of the State of Kerala, as specified in the First Schedule to this Act, to provide avenues of higher education and research facilities primarily for the tribal population of India.”.

(14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

(1830/SJN/NKL)

माननीय अध्यक्ष : श्री हैबी ईडन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक – उपस्थित नहीं।

श्रीमती सुमलता अम्बरीश – उपस्थित नहीं।

श्री एम. के. राघवन – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving the amendment. This is an amendment to establish a Central Marine University in any coastal city.

I beg to move:

Page 2, *after* line 5,-

insert	“18. Kerala	Central Marine University, Kollam	Whole of the State of Kerala.”. (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 2,-

insert	"12a. Kerala	Idukki Central Tribal University	Whole of the State of Kerala.". (15)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, नहीं। मेरी वही मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद कैंपस को पैसा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री हैबी ईडन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1833 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर 2023 / 17 अग्रहायण 1945 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।